राष्ट्रीय सहारा
पटना • बृहस्पतिवार • 5 दिसम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

सत्य के मार्ग पे चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है: पूरा रास्ता ना तय करना, और इसकी शुरुआत ही ना करना।
-गौतम बुद्ध

डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी

डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी, 2025 को शपथ लेंगे लेकिन उन्होंने अभी से अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर अमल करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों का चयन किया है जो घरेलू एवं विदेश मोर्चे पर उनकी नीतियों से सहमत हैं। अमेरिका की घरेलू आर्थिक नीतियों का दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ता है। वह अपने चुनाव सभाओं में कहा करते थे कि वह अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करेंगे। ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों से आने वाले सामानों पर 25 फीसद टैरिफ लगाने की घोषणा करके इन देशों की बेचैनी बढ़ा दी है। आर्थिक नीतियों का इस्तेमाल राजनीतिक और रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए भी किया जाता है। यदि इन देशों से आने

वाले सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाते हैं तो यह इनके खिलाफ एक रणनीतिक कदम माना जाएगा। ट्रंप यहीं पर नहीं रुके, बल्कि अपनी संरक्षणवादी नीतियों को विस्तार देते हुए ब्रिक्स देशों को भी चेतावनी दी है कि वे डॉलर का इस्तेमाल बंद करके नई करेंसी लॉन्च करते हैं तो ब्रिक्स देशों पर 100 फीसद टैरिफ लगाया जाएगा। ब्रिक्स की अफ्रीका में संपन्न शिखर वार्ता में ब्राजीली राष्ट्रपति लूला डिसिल्वा ने ब्रिक्स करेंसी का सुझाव दिया था। ब्रिक्स करेंसी के जरिए विश्व व्यवस्था पर वर्चस्व कायम करने वाले अमेरिकी डॉलर का दबदबा खत्म हो सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के घटते प्रभाव के कारण विभिन्न महाद्वीपों के अनेक देश ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। जाहिर है कि ब्रिक्स अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। ब्रिक्स की संभावित करेंसी को लेकर ट्रंप की बेचैनी समझी जा सकती है। ट्रंप इस खतरे को अच्छी तरह समझ रहे हैं। हालांकि दुनिया में नई करेंसी का प्रचलन बहुत जटिल और दुरुह प्रक्रिया है। इसी बात को ध्यान में रखकर ब्रिक्स देशों ने तय किया है कि फिलहाल नई करेंसी के स्थान पर विभिन्न देशों की राष्ट्रीय करेंसी में आपसी व्यापार किया जाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यदि अमेरिका आपात शुल्क में बढ़ोतरी करता है तो उसके सहयोगी यूरोपीय देशों पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा। बड़ा सवाल है कि क्या ट्रंप अपने सहयोगी देशों को नाराज करके आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणा को लागू कर पाएंगे। उनका पहला कार्यकाल विवादों से भरा हुआ था। क्या डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भी उनकी तुनकमिजाजी के लिए याद किया जाएगा।

जागरूकता है जरूरी

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 का देशव्यापी अनुपालन सुनिश्चत करने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सभी विभागों में आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अदालत ने कहा, 31 दिसम्बर तक प्रत्येक जिले में अधिकारी नियुक्त किया जाए जो 31 जनवरी, 2025 तक समिति का गठन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उपायुक्तो/जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि अधिनियम की धारा 26 के तहत आंतरिक शिकायत समिति अनुपालन के लिए सार्वजनिक और निजी संगठनों का सर्वेक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) के तहत उत्पीड़न की शिकायत के निवारण के लिए कई

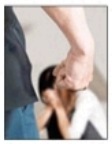

प्रावधान हैं। दोषी को एक से तीन साल की जेल और/या जुर्माना भी हो सकता है। राज्य महिला आयोगों को इस अधिनियम के विषय में जागरूकता फैलाने और समितियों के गठन का जिम्मा दिया गया। मगर देखा गया कि महिला आयोग राज्य सरकारों का मुंह ताकते रहते हैं। वे उम्मीद मुताबिक काम नहीं कर पाए। जब भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला विवादों में आता है, इस अधिनियम की आवश्यकता पर बहस छिड़ जाती है। सरकारी तंत्र की लापरवाही तथा महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गैर-जिम्मेदाराना रवैया छिपा नहीं है। संगठित ही नहीं, असंगठित क्षेत्र में भी डेरों कर्मचारियों को स्त्री विरोधी बर्ताव, छेड़छाड़, अभद्रता और उत्पीड़न झेलना पड़ता है। नौकरी जाने के डर से वे प्रतिरोध नहीं जता पातीं। दुनिया भर में कार्यस्थल महिलाओं को लैंगिक विभेद और उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। कई बार अदालतों ने सरकारों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए परंतु स्त्री अस्मिता को प्राथमिकता में न रखने वाली मानसिकता अभी भी कायम है। हालांकि झूठी शिकायतों का बहाना बना कर इससे बचना अब संभव नहीं है क्योंकि नई व्यवस्था में शिकायत झूठी या जानबूझकर की गई पाई जाने पर शिकायतकर्ता पर कार्रवाई हो सकती है। महिलाओं को जागरूक होना होगा ताकि अपने हकों को पहचान सकें और डट कर लड़ने को राजी हो पाएं।

कटाक्ष/ सहीराम

हे भगवान! तुम कहां हो!

हे भगवान! तुम कहां हो! हमने तुम्हें मंदिर में ढूंढ़ा। लेकिन भक्तों ने कहा कि नहीं तुम मंदिर में नहीं हो-मस्जिद में हो। मस्जिद तो अल्लाह का घर है। वैसे तो गांधी जी गाया करते थे-ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो हमने सोचा चलो एक ही हो-घर साझा कर रहे होंगे। वैसे आजकल लोग साझे में रहने कहां देते हैं-न धर्मों को एक साथ रहने देते हैं, न जातियों, न क्षेत्रों, न राज्यों को एक साथ रहने देते हैं। अरे भाइयों तक को एक साथ नहीं रहने देते। तो ईश्वर-अल्लाह को ही कहां साथ रहने देंगे। फिर भी हमने सोचा चलो ईश्वर अल्लाह घर साझा कर रहे होंगे। लेकिन फिर बताया गया कि नहीं मस्जिद में नहीं हो, मस्जिद के नीचे हो। आश्चान हुआ कि मस्जिद के नीचे ढूंढो। अदालतों ने भी तुम्हें मस्जिद के नीचे ही ढूंढने के आदेश दिए। हम तो सुनते आए थे कि घट-घट में हो। कण-कण में हो। पर अब कह रहे हैं कि नहीं तुम तो मस्जिद के नीचे हो। अभी तक तो हम यही मान कर चल रहे थे कि तुम ही हमारा उद्धार करोगे। लेकिन अब देखो तुम्हारा उद्धार करने के आदेश हो रहे हैं। लेकिन हे भगवान, नीचे तो पाताललोक है। और आप तो ऊपर देवलोक में रहते हो। अब मृत्युलोक वाले हम आपको कहां ढूंढें-ऊपर देवलोक में या पाताललोक में। बड़ी दुविधा पैदा हो गई है भगवान। मंदिर में ढूंढें तो कहते हैं मस्जिद में हो। मस्जिद में ढूंढें तो कहते हैं कि मस्जिद के नीचे हो। घट-घट में और कण-कण में रहना तो लगता है पहले ही छोड़ चुके हो। वैसे तो पहले यह भी कहते थे कि तुम गरीब के झोपड़े में रहते हो। लेकिन जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहां तो कोई गरीब था ही नहीं। तो क्या आपने गरीब को छोड़ कर अमीर में रहना शुरू कर दिया। पहले कहते थे कि भगवान बच्चे में मिलेगा। लेकिन बच्चे तो कभी ऑक्सीजन की कमी से और कभी आग लगने से अस्पतालों में ही मर रहे हैं। कुपोषण से मर रहे हैं। उनकी तो तस्करी हो रही है, वे तो बेचे जा रहे हैं। बहुत ठिकाने बदल रहे हो भगवान। कहां ढूंढें बताओ। यह तो सच है भगवान कि तुम्हारी तलाश आसान नहीं है। इसीलिए बड़े-बड़े तपस्वी तुम्हें पाने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। तुम्हारे लिए मठ खड़े करते हैं। लेकिन रविदास बाबा तो आपको कठौती में ही पा जाते थे। लेकिन उसके लिए जरूरी था कि मन चंगा हो। बस, यही मुश्किल है!

क्षेत्रीय दल कर रहे अनदेखी

कांग्रेस

मुकेश बालयोगी

दिल्ली विधानसभा चुनाव के दस्तक देते ही विपक्षी एकता एक बार फिर से कटी पतंग जैसी हो गई है, जो कभी इस दीवार और कभी उस स्तंभ से टकरा कर लूटी-पिटी सी नये तारणहार की राह देख रही है। आम आदमी पार्टी (आप) के अगुवा अरविंद केजरीवाल ने साफ ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी आने वाले साल में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। सभी 70 सीटों पर खुद उम्मीदवार उतारेंगी। मजबूरी में कांग्रेस नेताओं को भी सभी सीटों पर प्रत्याशी देने की घोषणा करनी पड़ी है।

संसद से लेकर सड़क तक भाजपा या भाजपा-नीत केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस और आप कदमताल करती हुई दिखाई तो पड़ती हैं, लेकिन चुनाव आते ही दोनों की राहें जुदा हो जाती हैं। आप के रणनीतिकारों का मानना है कि भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ भिड़ने में एकता के मोर्चे पर दोनों के साथ आने से जनता में माहौल बन तो जाता है, लेकिन चुनावी तालमेल करने से आप को कोई खास फायदा नहीं मिल पाता। इस बार भी आप को डर है कि कांग्रेस का आधार वोट आप को ट्रांसफर होने की बजाय कहीं भाजपा को फायदा न पहुंचा दे। वैसे भी पिछले चुनाव के आंकड़े यही बता रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस का जनाधार लगातार कमजोर होता जा रहा है। 2024 के लोक सभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। भाजपा सभी सात सीटें जीत गई। आप भी खाली हाथ रही। 2019 के लोक सभा चुनाव में कांग्रेस को 23 फीसद वोट मिलने के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली थी। 2014 के लोक सभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी 15 फीसद वोट पाने के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।

अलबत्ता, 2009 में कांग्रेस दिल्ली की सातों लोक सभा सीट जीतने में कामयाब हुई थी, साथ ही वोटों की 57 फीसद हिस्सेदारी भी उसने हासिल की थी। इस तरह कांग्रेस के वोटों का यह छीजन आप को डूबती नैया पर सवार होने जैसा लग रहा है। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सफाये के बाद भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए आप और कांग्रेस ने मिल कर सरकार बनाई थी। परंतु यह सरकार 49 दिनों तक ही चल सकी। बाद में 2015 में आप खुद की बदौलत सत्ता में आई और कांग्रेस 2015 और 2020, दोनों विधानसभा चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत सकी। अब तो आप को दिल्ली में कांग्रेस टक्कर में ही नहीं दिखती। साफ है कि आप अपना मुख्य मुकाबला भाजपा के साथ मान रही है, और अपनी बदौलत कांग्रेस को जीवन दान देने से परहेज कर रही है।

दूसरे दल भी कांग्रेस का साथ देने को घाटे का सौदा मान रहे हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि एक बड़ा गठबंधन इंडी अलायंस के रूप में बना जरूर है, लेकिन यह प्रभाव छोड़ता नहीं दिखलाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ने पहली बार कांग्रेस को ठेंगा दिखाया है, बल्कि इससे पहले भी पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन किए बिना चुनाव जीत कर और वहां वह सरकार बना कर दिखा चुकी है।

इस मामले में कांग्रेस भी दूध की धोई नहीं है, बल्कि लोक सभा चुनाव के तुरंत बाद हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में खुद को सरकार में आना तय मान कर कांग्रेस के नेता आप से गठबंधन के विरोध में लगातार बयान देते रहे। आखिरकार, दोनों पार्टियों में गठबंधन नहीं हो सका और दोनों ही पार्टियां सत्ता में नहीं आ सकीं। इस तरह की स्थिति पहले गुजरात समेत दूसरे कई राज्यों के चुनावों में भी रही है। दोनों पार्टियों को सीटों का तालमेल नहीं होने का खमियाजा उठाना पड़ता रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस और आप, दोनों के अपने-अपने पूर्वाग्रह हैं। आप मान कर चलती है कि कांग्रेस का देश में कहीं कोई जनाधार नहीं है, या तो वह क्षेत्रीय दलों की बैसाखी पर चल रही है, या फिर उसे नाराज वोटों का फायदा मिल जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव लगभग 10 महीने बाद हैं। लेकिन अभी से ही कांग्रेस के नेता अपने आला कमान की जगह राजद सुप्रीमो की चौखट पर ज्यादा माथा टेक रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि विधानसभा चुनाव की वैतरणी लालू-तेजस्वी के बिना पार नहीं हो सकते। कांग्रेस की ओर से पूर्णिया लोक सभा सीट से पप्पू यादव को उतारने की पूरी तैयारी के बावजूद राजद की हरी झंडी नहीं मिलने के कारण कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं दे सकी। आखिरकार, पप्पू जीते लेकिन निर्दलीय सांसद के तौर पर। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में तो लालू प्रसाद ने विहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बारे में साफ तौर पर कहा कि उन्हें राज्य सभा सदस्य कांग्रेस ने नहीं, बल्कि राजद ने बनाया है।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) की ओर से भी बार-बार गठबंधन तोड़ देने की चेतावनी दी जाती रहती है। कुछ और भी प्रदेशों में क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपने जूनियर पार्टनर के तौर पर भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर, इन हालात में कांग्रेस जाए तो जाए कहां? लंबे समय तक देश पर राज करने और अधिकतर राज्यों में सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस की यह स्थिति एक दिन में नहीं बनी है। कांग्रेस के वोट बैंक के तीन मुख्य आधार-दलित, मुस्लिम और सवर्ण-उसके हाथ से पूरी तरह से निकल चुके हैं। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय दलों की बदौलत अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है

क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपने जूनियर पार्टनर के तौर पर भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आखिर, इन हालात में कांग्रेस जाए तो जाए कहां? लंबे समय तक देश पर राज करने और अधिकतर राज्यों में सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस की यह स्थिति एक दिन में नहीं बनी है। कांग्रेस के वोट बैंक के तीन मुख्य आधार-दलित, मुस्लिम और सवर्ण-उसके हाथ से पूरी तरह से निकल चुके हैं। इस क्षेत्रीय दलों की बदौलत अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है

(लेख में विचार निजी हैं)

अविचलित मति

डॉ. ज्ञानानंद दास

अविचलित मति का अर्थ है ऐसी स्थिर और दृढ़ मानसिकता, जो कठिनाइयों और बाधाओं के बावजूद अपने लक्ष्य और आदर्शों पर अडिग रहती है। जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं और सामने चुनौतियां खड़ी होती हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति अपनी सोच, ध्येय और कार्यों में अविचलित रहता है, वही सफलता प्राप्त करता है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में हर पल चुनौतियों के तूफान आते रहते हैं, उनमें आम इंसान के लिए स्थिर और अविचल रहना मुश्किल हो जाता है। विचलित मति व्यक्ति को कमजोर बना देती है। हम जीवन में स्थिर और दृढ़ नहीं रहेंगे, तो न केवल अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे, बल्कि दूसरों की नजरों में भी हमारी विश्वसनीयता कम हो जाएगी। इसीलिए सफलता के लिए अविचलित मति होना अनिवार्य है। महाभारत के युद्ध से पूर्व अर्जुन इसी तूफान में घिरा था। इस समय अर्जुन के जीवन में आई इस परिस्थिति को गीता में 'क्षुतिप्रतिघ्न' (अनेक प्रकार की बातों को सुनने और जानने से जन्मा विपरीत ज्ञान) कहा गया है। उसे लग रहा था कि युद्ध करना तो मेरा धर्म है किंतु अपने गुरुओं और अपने कुल को नष्ट करना भी उचित नहीं है। एक ओर परिवार की रक्षा और दूसरी ओर क्षात्रधर्म का पालन।-इसमें यदि वह कुल की रक्षा करेगा तो युद्ध नहीं होगा-इन दोनों विषयों में अर्जुन की क्षुतिप्रतिघ्न बुद्धि विचलित हो रही थी। अतः भगवान कृष्ण उसे स्थिर मति होने का उपदेश देते हैं। यह न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि हमारे कार्यों को दिशा और स्थिरता भी प्रदान करती है। महतंस्वामी महाराज समझाते हैं कि पहले तो साधक इसी बात को लेकर संशय में रहता है कि उसे सांसारिक कार्य को ही करने चाहिए या परमात्मा की खोज करनी चाहिए? इससे ऊपर उठ कर जब साधक ईश्वर की ओर बढ़ता है तो ईश्वर के स्वरूप के बारे में पहले से सुने हुए वचनों के कारण उसके सामने विभिन्न मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। ईश्वर को कैसे जानें, यह निर्णय करना कठिन हो जाता है। लेकिन जब साधक दिव्य सत्गुरु के सत्संग के माध्यम से भगवान के स्वरूप के बारे में सही निर्णय लेता है, तो उसकी बुद्धि भगवान की कृपा से स्थिर हो जाती है।

रीडर्स मेल

भारी न पड़ जाए गूगल मैप

विज्ञा ने बहुत कुछ तैयार कर लिया है, लेकिन कहते हैं कि विज्ञान वरदान है तो हमारे लिए अभिशाप भी बन सकता है। आजकल लगभग लोग ड्राइविंग करती बार अनजान जगह पहुंचने के लिए गूगल मैप का सहारा लेते हैं, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए और सतर्कता बरतनी चाहिए कि गुगल मैप कहीं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में गुगल मैप कुछ लोगों की जान का दुश्मन बन गया। वहां गुगल मैप ने ड्राइवर को निर्माणाधीन पुल से रास्ता दिखा दिया और हादसा हो गया। इसी तरह कुछ समय पहले गूगल मैप के जरिए केरल के एर्नाकुलम में गूगल मैप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले दो डॉक्टरों की जान पर भारी पड़ गया। वहां पांच लोग एक कार में सवार हो कर कहीं जा रहे थे, लेकिन वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते से अनजान थे, इसके लिए उन्होंने जीपीएस का सहारा लिया और यह सहारा उन पांच में से दो लोगों के लिए मौत का सामान बन गया। इन हादसों से सबक लेते हुए हम सभी को गूगल मैप पर भरोसा सोच-समझ कर करना होगा। हमें इंटरनेट का प्रयोग समझदारी से करना चाहिए। इंटरनेट का प्रयोग हमें अपने लिए वरदान बनाना है, अभिशाप नहीं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

बांग्लादेश में हिन्दुओं पर संकट

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं की स्थिति अत्यंत भयावह है। दिन-ब-दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं। आए दिन वहां से हिन्दुओं के दमन के तो हिन्दू मंदिरों के तोड़े जाने के समाचार अखबारों की सुर्खियां बन रहे हैं। बांग्लादेश से इस मामले में कुछ भी अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि यह हिंसा राज्य प्रायोजित है और मो. युनुस सरकार की चरमपंथी इस्लामिक ताकतों से मिलीभगत है। इसीलिए वहां हिन्दुओं पर अत्याचार रुक नहीं रहे। हिन्दू बच्चों और महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है। उनके मन्दिर और संपत्ति नष्ट की जा रही हैं। इसके विरोध में खड़े होने वाले चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत सरकार द्वारा इस पर चिंता व्यक्त करना नाकाफी है। वह हस्तक्षेप कर वहां के हिन्दू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। भारतीय हिन्दू संगठन भी पुरजोर विरोध प्रकट करें।

गोपाल सोनी, धार, मप्र

एक्शन मोड में आएं शहरी निकाय

भारत गांवों का देश है, लेकिन ग्रामीण जनता बड़ी तेजी से शहरों की ओर पलायन कर रही है। शहरों की बुनियादी समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी नगर निकाय की होती है, सभी नगर निकाय लालफीताशाही और राज्य सरकार के हस्तक्षेप से त्रस्त हैं। अधिकांश शहर बेतरतीब तरीके से बस रहे हैं। शहरों की प्रमुख बुनियादी समस्या आवास, सड़क, अतिक्रमण, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली-पानी और जल निकासी हैं। यदि नगर निकाय और सरकार मिल कर शहरों की बुनियादी समस्याओं को दूर कर दें, तो वहां के लोग उन्हें खुद ही स्मार्ट बना लेंगे। सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। शहरी निकाय और ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस मसले पर शीघ्र एक्शन मोड में आना होगा।

हिमांशु शेखर, गया

letter.editorsahara@gmail.com

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी का स्पष्ट कहना है कि शाम साढ़े पांच बजे मतदान समाप्त होने के 24 घंटे बाद ही वोट प्रतिशत में बड़ा उछाल आने पर कोई कैफियत नहीं दी जा सकती। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आखिर, क्या बदल गया है? चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए।

एम.के. वेणु, पत्रकार
@mkvenu1

शेयर बाजार | राहुल लाल

गिरावट का गुणा गणित

भारतीय शेयर बाजार पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट का रुख है और बेचमार्क निफ्टी और स्मॉलकैप 100 अपने सार्वकालिक उच्चतम स्तर से 10 फीसद से ज्यादा टूट चुके हैं। बाजार कमजोर नतीजों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली का पहले से दबाव झेल रहा था। इस बीच, खुदरा मुद्रास्फीति में तेजी और डॉलर में मजबूती ने चिंता बढ़ा दी है। बाजार के उच्चतम स्तर से 10 फीसद से ज्यादा फिसलने को ही 'तकनीकी रूप से गिरावट' कहा जाता है।

डॉलर में मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड में तेजी के मद्देनजर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) भारत से अपना निवेश लगातार निकाल रहे हैं। अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने 94,017 करोड़ डॉलर की निकासी की तो नवम्बर में 21,612 डॉलर की। अमेरिकी फेड रेट में कटौती के बाद से ही एफपीआई में निकासी जारी है। बीते माह चीन सरकार ने स्पेशल राहत पैकेज का ऐलान कर अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने की कोशिश की। इस राहत पैकेज ने भी विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया। इसलिए विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल कर अमेरिका और चीन के बाजार में निवेश करना शुरू कर दिया। विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार से दूरी बनाई तो घरेलू निवेशकों ने शेयर बाजार में मोर्चा संभाला। लेकिन चिंता की बात यह है कि घरेलू निवेशकों में काफी ऐसे हैं, जिन्हें शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था की मोटी-मोटी जानकारियां नहीं हैं। कड़वी सच्चाई है कि शेयर बाजार से 90 फीसद से ज्यादा रिटेलर पैसे नहीं बना पाते, बल्कि अपनी मेहनत से कमाए पैसे गंवा जरूर देते हैं। रिटेल निवेशकों को समझना होगा कि अभी जब निजी इक्विटी फर्में, प्रवर्तक इकाइयां इत्यादि शेयर बाजार से दूरी बना रही हैं, तब वे बिना रिसर्च किए शेयर बाजार में निवेश करेंगे, तो उनका निवेश कैसे सुरक्षित रह सकता है?

शेयर बाजार काफी जोखिम भरा होता है, एक छोटी सी गलती निवेशक को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आज सोशल मीडिया पर कई इनफ्लुएंसर ज्ञान देते हैं कि किस शेयर में निवेश करना चाहिए। हमें इनसे प्रभावित होकर निवेश नहीं करना चाहिए। जब भी किसी कंपनी के शेयर खरीदें, तो आपको उस कंपनी के बारे में गहन रिसर्च

करनी चाहिए। शेयर बाजार में कई कंपनियों में उतार- चढ़ाव कृत्रिम किस्म का होता है, जिसमें बड़े खिलाड़ी तो लाभ लेकर निकल जाते हैं, परंतु छोटे खुदरा निवेशक बर्बाद हो जाते हैं। सरकार और सेबी जैसे नियामकों के लिए आवश्यक है कि शेयर बाजार में कृत्रिम उतार-चढ़ाव को लेकर सदैव सख्त रहें। छोटे निवेशकों की पूंजी न डूबे, इसके लिए सेबी और सरकार को भी कुछ सेफगार्ड बनाने चाहिए। निवेशकों को शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था की बारीकियों की सीख देने के लिए भी सेबी को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। निवेशकों को भी अर्थव्यवस्था की विभिन्न चुनौतियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय एक ओर महंगाई और दूसरी ओर सुस्त होती रफ्तार से जूझ रही है। आरबीआई के लिए आवश्यक है कि महंगाई को 6% के दायरे में रखे जबकि इस समय खुदरा महंगाई दर 6.2 प्रतिशत है। आरबीआई इस दृष्टि से ब्याज दरों में कटौती नहीं कर सकता। ब्याज दरों में कटौती करेगा, तो महंगाई और बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ, इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर केवल 5.4 फीसदी रही, जो 7 तिमाहियों में सबसे कम है। इस समय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए सस्ते कर्ज की जरूरत है, जिसके लिए आरबीआई को ब्याज दर में कटौती करनी होगी परंतु महंगाई दर के कारण यह संभव नहीं। ब्याज दरें कम नहीं हुईं तो आर्थिक सुस्ती जल्द ही आर्थिक मंदी की ओर अग्रसर हो जाएगी।

कुल मिला कर ब्याज दरें घटाने की गुंजाइश सीमित होना अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है। ऐसे में निवेशकों को परिस्थितियों के अनुसार निवेश की योजना बनानी चाहिए। शेयर बाजार में जो हाहाकार मचा है, उसमें विदेशी निवेशकों की भारी-भरकम निकासी भी प्रमुख कारण है। स्पष्ट है कि भारत को टिकाऊ स्तर पर उच्च निवेश की आवश्यकता है, ताकि लंबी अवधि तक देश ऊंची वृद्धि दर हासिल कर सके। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जिस तरह उच्च स्तर पर निकासी की है, उससे बचने के लिए आवश्यक है कि अर्थव्यवस्था के सभी उच्चतर संकेतकों को मजबूत रखा जाए। देश विकास के जिस चरण में है, वहां हमारी घरेलू बचत 'जीडीपी वृद्धि' के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में विश्व से टिकाऊ पूंजी जुटाने की जरूरत है। भारत में आने वाली विदेशी पूंजी कई लक्ष्यों के साथ आती है। उदाहरण के लिए कुछ एफपीआई केवल भारत और अमेरिका की ब्याज दरों के अंतर का लाभ उठाने के लिए आते हैं। ऐसे निवेश अल्पकालिक प्रकृति के हो सकते हैं, और बहुत जल्दी वापस चले भी जाते हैं।

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्यूनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया केम्पर्स लिमिटेड प्लैट, गौता-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया विहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428
वर्ष - 19, अंक 6498
आर.एन.आई. नं. बीआईएचएचएन/2006/18062 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

सम्पादकीय

राजमार्गों पर अतिक्रमण, संसद में पेश हुई चौंकाने वाली रिपोर्ट

देश में राजमार्गों पर अतिक्रमण के मामले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केवल राज्य सरकारों को दोष नहीं दे सकता क्योंकि प्रश्न यह है कि उसकी अपनी एजेंसियां क्या कर रही हैं? किसी राजमार्ग पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण को हटाकर कर्तव्य की इतिश्री इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इसकी गारंटी नहीं कि वहां फिर से अतिक्रमण नहीं होगा। यह जानना निराशाजनक है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण को लेकर उदासीनता का परिचय दिया जा रहा है। हाल में संसद में दी गई एक जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों में राजमार्गों पर अतिक्रमण के मामलों में न तो किसी पर कोई मामला दर्ज किया गया और न ही कोई जुर्माना वसूला जा सका। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि राजमार्गों पर होने वाले कब्जे एवं अतिक्रमण को हटाने का काम होता रहता है, क्योंकि ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न होने से वे फिर से राजमार्गों को बाधित करने आ जाते हैं।

इसका पता चलता इससे चलता है कि इस वर्ष मध्य प्रदेश में राजमार्गों से 1866 अवैध कब्जे हटाए गए, महाराष्ट्र में 1062 और गुजरात में 1153। इसी तरह एनसीआर से 92 अवैध कब्जे हटाने पड़े। क्या कोई यह दावा करने की स्थिति में है कि ये अवैध कब्जे फिर से नहीं हुए होंगे? भरी-पूरी आशंका यही है कि इनमें से कुछ कब्जे फिर से हो गए होंगे।

समझना कठिन है कि राजमार्गों को बाधित करने वालों के खिलाफ इतनी उदारता क्यों बरती जा रही है? यह समझा जाना चाहिए कि राजमार्गों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई किए बिना आवागमन को सुगम बनाए रखना संभव नहीं। जब राजमार्ग अतिक्रमण और अवैध कब्जे का शिकार होते हैं तो केवल यातायात ही बाधित नहीं होता, बल्कि दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ता है। यह एक तथ्य है कि राजमार्गों पर होने वाली दुर्घटनाएं और उनमें मरने एवं घायल होने वालों की लगातार संख्या बढ़ रही है। राजमार्गों पर अतिक्रमण के मामले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केवल राज्य सरकारों को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि प्रश्न यह है कि उसकी अपनी एजेंसियां क्या कर रही हैं? किसी राजमार्ग पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण को हटाकर कर्तव्य की इतिश्री इसलिए नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं कि वहां फिर से अतिक्रमण नहीं होगा। अपने देश में तो स्थिति यह है कि यदि कहीं आज अतिक्रमण हटाया जाता है तो कल वह फिर से कायम हो जाता है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कई बार राजमार्गों पर अस्थायी अतिक्रमण होता है। व्यस्त समय में शहरी इलाकों में कई राजमार्गों के किनारे पर दुकानें लग जाती हैं या फिर आटो-टैंपों और बसें सवारियां उतारने-चढ़ाने का काम करने लगती हैं। इस पर तब तक कोई ध्यान नहीं देता, जब तक लंबा जाम न लग जाए या फिर कोई हादसा न हो जाए। यह ठीक है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ हाईवे प्रशासन को अवैध कब्जे और अतिक्रमण की जांच के लिए उसमाही के निरीक्षण का निर्देश दिया है, लेकिन ऐसे किसी निर्देश की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी।

अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर, 2024 पर विशेष

स्वयंसेवक रचते हैं सेवा एवं संस्कृति के नये स्वस्तिक

ललित गर्ग

सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष दुनिया भर में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 दिसंबर, 1985 को स्वयंसेवक दिवस मनाने की घोषणा की। तब से, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, सरकारों, नागरिक समाज संगठनों आदि द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। यह दिवस उन लोगों और संगठनों का सम्मान करता है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए अपना समय और ऊर्जा स्वेच्छा से देते हैं। स्वयंसेवकों को मान्यता देने के साथ-साथ, इस दिन का उद्देश्य परोपकार, सेवा एवं सहायता के रूप में स्वयंसेवा को बढ़ावा देना भी है। यह स्वयंसेवकों से जुड़े संगठनों और व्यक्तिगत स्वयंसेवकों को स्वयंसेवा को बढ़ावा देने, सरकारों को स्वयंसेवी प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करने और स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की उपलब्धि में स्वयंसेवकों के योगदान को मान्यता देने का अवसर प्रदान करता है। पूरी दुनिया में 970 मिलियन स्वयंसेवक हैं। भले ही लाखों स्वयंसेवक हों, लेकिन दुनिया को हमेशा और अधिक की आवश्यकता है। आज देश एवं दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जिस स्वयंसेवक संगठन की उपयोगिता एवं सार्थकता की चर्चा है, जिसकी विलक्षणताओं एवं विशेषताओं पर शोध हो रहा है, वह है भारत का शताब्दी वर्ष मना रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो दुनिया सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। संघ देश की सरकारों तथा गैर-सरकारी संस्थाओं को आर्थिक तथा सामाजिक विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन देने एवं राष्ट्रीय अस्तित्व एवं अस्मिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का स्मरण कराता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक दक्षिणपंथी, हिन्दू राष्ट्रवादी, अर्धसैनिक, स्वयंसेवक संगठन हैं, जो भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का व्यापक रूप से पैतृक संगठन माना जाता हैं। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपेक्षा संघ या आर.एस.एस. के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। बीबीसी के अनुसार संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। इसकी स्थापना सन् 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन मोहिते के बाड़े नामक स्थान पर डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार ने की थी। संघ के 5 स्वयंसेवकों के साथ शुरू हुई विश्व की पहली शाखा आज 50 हजार से अधिक शाखाओं में बदल गई और ये 5 स्वयंसेवक आज करोड़ों स्वयंसेवकों के रूप में हमारे समाने हैं, जो स्वयं में एक विलक्षण एवं अद्भुत उदाहरण है। संघ आर्थिक असंतुलन, सांस्कृतिक उग्रवन एवं गरीबी को दूर करने एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्र कई क्षेत्रों में प्रगति करने के बाद भी देश में गरीबी एक राक्षस के रूप में खड़ी है। जिस तरह हम विजयादशमी के दिन राक्षस रूपी पुतला का वध कर बुराई पर अच्छाई को स्थापित करने का संकल्प लेते हैं उसी तरह हमें इस गरीबी पर विजय पाने का प्रण लेना होगा। इसके लिए देश में सभी को नौकरी सरकार या निजी संस्थाएं दे नहीं सकती हैं। इसलिए हमें स्वरोजगार एवं स्व उद्यमिता पर जोर देना होगा। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वावलंबी भारत के लिये संघ प्रयासरत है।

संघ की विचारधारा में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, राम जन्मभूमि, अखंड भारत, समान नागरिक संहिता जैसे विषय हैं, जो देशवासियों को देश की समरसता की ओर ले जाते हैं। 1975 के बाद से धीरे-धीरे इस संगठन का न केवल सामाजिक-सांस्कृतिक बल्कि राजनीतिक महत्व बढ़ता गया और इसकी परिणति भाजपा जैसे राजनीतिक दल के रूप में हुई जिसे आमतौर पर संघ की राजनीतिक शाखा के रूप में देखा जाता है। संघ की स्थापना के 75 वर्ष बाद सन् 2000 में प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार भारत की केन्द्रीय सत्ता पर आसीन हुई। इसके पश्चात 2014 एवं 2019 में नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री नेतृत्व इसकी सरकार बनी हैं। संघ का मूल उद्देश्य भारत को उसकी अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में पहचान प्रदान करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संघ या आरएसएस के नाम से अधिक लोकप्रिय है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है। संघ के छोटे बड़े लगभग 55 स्वस्थ समाज निर्माण में जुटे संगठन एवं गतिविधियां हैं जो संसारभर में फैले हैं। महात्मा गाँधी ने 1934 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर की यात्रा के दौरान वहाँ पूर्ण अनुशासन, समर्पण देखा और छुआछूत की अनुपस्थिति पायी। इससे प्रभावित होकर उन्होंने संघ की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संसार का अकेला ऐसा संगठन है जिसमें आज तक भ्रष्टाचार, पदलिप्सा या अनैतिकता की स्थिति नहीं आई। इस समय संघ द्वारा करीब 25,028 सेवा-प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। ये प्रकल्प देश के 30 प्रांतों में 11,498 स्थानों पर चल रहे हैं। ये सेवा कार्य भिन्न-भिन्न क्षेत्रों पर केन्द्रित हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक विकास, कौशल विकास, गोसेवा आदि। भौगोलिक दृष्टि से 16,101 सेवा कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में, 4,266 वनवासी क्षेत्रों में, 3,412 सेवा बस्तियों में और शेष स्थानों पर 1,249 सेवा कार्य चल रहे हैं। संघर्षों से जूझने की क्षमता संघ को अपने उदयकाल से ही प्राप्त है। इसके सामने प्रारंभ से जैसी संघर्षपूर्ण परिस्थितियां रही है, साधारण व्यक्ति या संस्था उसके सामने टिकने का साहस नहीं कर पाता। किन्तु जिसकी जन्मघूंटी के साथ ही अनुशासन, सहिष्णुता, संगठन, राष्ट्रीयता के संस्कार मिल जाये, वह कभी हार नहीं सकता।

अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थितियों का आकलन इस दिवस की सार्थकता को व्यक्त करता है। आरएसएस में स्वयंसेवक इस शब्द का अर्थ होता है- स्वेच्छा से काम करने वाला। संघ के विचारों को मानने वाले और नियमित तौर पर शाखा में जाने वाले लोगों को संघ का स्वयंसेवक कहा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रमुख शैक्षणिक प्रवृत्ति एवं संगठनात्मक उपक्रम है विद्या भारती। जो आज 20 हजार से ज्यादा स्कूल चलाता है, लगभग दो दर्जन शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, डेढ़ दर्जन कॉलेज, 10 से ज्यादा रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थाएं चलाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विश्व के सबसे बड़ा छात्र संगठन के रूप में भी जाना जाता है। विद्यार्थी परिषद का नारा है- ज्ञान, शील और एकता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में संघ के कुल प्रकल्पों की संख्या 3,112 है। भारतीय किसान संघ की स्थापना 4 मार्च 1979 को राजस्थान के कोटा शहर में महान भारतीय तत्त्वचिंतक, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त मजदूर नेता श्री दत्तोपंतजी ठेंगडी ने भारतीय किसानों के उत्थान हेतु की। इस सम्पूर्ण संगठन के पीछे की मूल भावना यह है कि निहित स्वार्थों की जगह सामूहिक हित, राष्ट्रीयता की भावना, स्व-संस्कृति एवं स्व-पहचान को प्राथमिकता देना है। इतनी अकल्पित उपलब्धियों से भरा-पूरा संघ सम्पूर्ण राष्ट्र को एक नई शक्ति, नई ताजगी, नया विश्वास देने वाला है। इसकी सफलता में संघ के शीर्ष नेतृत्व के साथ-साथ कार्यकर्ताओं, जन साधारण का उत्साह, हौसला एवं पुरुषार्थ का योग है। सुदृढ़ संगठन इसकी विरल विशेषता है, संगठन के क्षेत्र में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। यही कारण है कि आज संघ की तेजस्विता, वर्चस्विता एवं प्रखरता की चर्चा आम आदमी के मुंह पर है।

सूरज की एक किरण को देखकर सूरज बनने का सपना संजोने वाला संगठन महान होता है। वह और अधिक महान होता है, जो सूरज बनने का सपना देखकर परिपूर्ण सूरज बन जाता है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधियां लगाते जो पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के ऐसे सौभाग्य क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद होंगे और दुःखों तथा, अपनों मित्रों बातों से लाभकर तरक्की होगी। हम न सिर्फ हमारे तरफ से और सर्टिफ तुरंत को सुलझाने तथा लाभदायक उपायों को सहयुक्त करेंगे, क्रमिक पारम्परिक तरीकों से नहीं, जहां हम लाभदायक नहीं लगता और बातों से लाभ प्राप्त करेंगे

मेष
आप तन-मन से स्वस्थ होकर कई तरह के काम आसानी से पूरे कर पाएंगे। सफलता मिलने से आपके उत्साह में वृद्धि होगी। आज भाग्य आपका साथ देगा। इनकम बढ़ेगी। परिजनों के साथ आनंद एवं उल्लास से समय गुजरेगा। आज धन

वृष
पानी वाली जगहों से दूर रहें। आज नियम विरुद्ध कामों से दूर रहें। आज आपका दिन आनंद-प्रमोद में गुजरेगा। रोमांस के लिए आज का दिन अच्छा है और किसी खास व्यक्ति का साथ आपको आनंद देगा। आज कोई नया काम शुरू ना करें।

मिथुन
माता से लाभ होने के संकेत आपको मिल रहे हैं। मित्र और संबंधियों से घर का वातावरण अच्छा रहेगा। आज अचानक होने वाली घटनाओं से आप चिंतित रहेंगे। स्वास्थ्य खराब होने और आंखों में दर्द होने की आशंका बनी रहेगी। आपका

कर्क
स्वजनों एवं परिजनों के साथ विवाद हो सकता है। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा और ज्यादा परिश्रम के बाद ही सफलता मिलेगी। दुर्घटना हो सकती है, सावधान रहें। आज आपका दिन बहुत लाभदायी है।

सिंह
हेल्थ का ध्यान रखने और खासकर बाहर के खाने-पीने से परहेज करने की सलाह आपको दी जाती है। आज आपमें क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए वाणी में गुस्सा ना रखें। परिजनों से उग्र चर्चा के कारण मनमुटाव न हो।

कन्या
आज आपके धार्मिक एवं मांगलिक कामों में व्यस्त रहने की संभावना ज्यादा रहेगी। आप में आज क्रोध की मात्रा अधिक रहेगी, इसलिए आप सावधान ही रहें। संतान एवं व्यापार की परेशानियों के कारण आपका मन अशांत रहेगा।

तुला
अविवाहितों को योग्य जीवनसाथी मिलने के योग हैं। धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। मित्रों से अचानक हुई मुलाकात आनंददायी रहेगी। मित्रों से लाभ होगा। आज आपको अच्छा खाना नसीब होगा। मित्रों से लाभ होगा।

वृश्चिक
नौकरी में आपके अधिकारी खुश रहेंगे। आपकी पदोन्नति के योग हैं। अधिकारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा होगा। परिजनों के साथ खुले मन से बातचीत होगी। घर के डेकोरेशन पर कुछ खर्च हो सकता है।

धनु
बाहर जाना हो सकता है। माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। सरकारी लाभ होगा एवं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आप का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। पहले से निर्धारित काम के लिए आपका प्रयास ज्यादा रहेगा। आज कोई नया काम शुरू

मकर
संतान पक्ष से अच्छे समाचार मिलेंगे। नौकरीपेशा लोगों से आपको लाभ होगा। आय में वृद्धि होगी। वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। आप आज हर काम सरलता से पूरे कर पाएंगे।

कुंभ
मित्र एवं प्रियजन आपके प्रवास को आनंद से भर देंगे। नए वस्त्रों की खरीदी के योग हैं। तन-मन की तंदुरस्ती अच्छी रहेगी। अच्छे भोजन एवं वैवाहिक सुख की अनुभूति होगी। आज आप के घर में सुख शांति और आनंद का माहौल रहेगा।

मीन
आपका शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य अच्छा रहेगा। जरूरी कामों पर धन खर्च होगा। बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। दफ्तर में सहकर्मियों का अच्छा साथ मिलेगा। मित्रों से मुलाकात होगी।

शख्सियत

नमस्कार साथियों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री हेमेन्द्र नागर जी। 10 अक्टूबर सन 1976 को उदयपुर में जन्में हेमेन्द्र नागर बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन इंसान हैं। एक बेहतरीन इंसान ही बेहतरीन अधिकारी बन सकता है। एल्यूकेश्न के रूप में इन्होंने एमए (राजनैतिक विज्ञान) एमएससी (गणित) बीएससी किया हुआ है और आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् कम अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा) उदयपुर पद को सुशोभित कर रहे हैं। इससे पूर्व ये उप सचिव मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, डूंगरपुर। अतिरिक्त जिला कलक्टर, जोधपुर। जिला रसद अधिकारी, जोधपुर। जिला आबकारी अधिकारी, उदयपुर। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़। अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अलवर। उपखण्ड अधिकारी, गंगरार चित्तौड़गढ़। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। सहायक कलेक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट प्रशिक्षणाधीन चित्तौड़गढ़। बेहद संवेदनशील

श्री हेमेन्द्र नागर
(वरिष्ठ अल्पसंख्यक)

अधिकारी के रूप में इन्हे जाना जाता है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है।

-रूपक शर्मा

आज का इतिहास

महत्वपूर्ण घटनाएँ

- शाहजहां के छोटे बेटे मुराद ने 1657 में खुद को बादशाह घोषित किया।
- नेपोलियन बोनापार्ट रुस में भारी पराजय और नुकसान का सामना करने के बाद 1812 में पेरिस लौटे।
- रूस में 1917 में नई क्रांतिकारी सरकार गठन तथा रूस-जर्मनी के बीच युद्ध विराम।
- कनाडा में 1917 में हुए दो जहाजों के भीषण टक्कर में कम से कम 15 सौ लोगों की मौत हो गई।
- ब्रिटिश संसद द्वारा 1922 में आयरिश स्वतंत्र राज्य संविधान अधिनियम को स्वीकृति मिली।
- जापानी हवाई जहाज ने 1943 में कोलकाता पर बम गिराया।
- भारत में 1946 में होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई।
- सिक्किम 1950 में भारत का संरक्षित राज्य बना।
- लंबी दूरी के टेलिफोन कॉल को हर घर तक पहुंचा देने वाली एसटीडी सेवा 1955 में आज ही के दिन अस्तित्व में आई.
- अफ्रीकी देश घाना ने 1960 में बेल्जियम के साथ राजनयिक संबंध समाप्त किये।
- भारत ने 1971 में बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी।
- गेराल्ड फोर्ड ने 1973 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली।
- मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार (उत्तर प्रदेश) के मुख्यमंत्री बने।
- विवादास्पद लेखक सलमान रुश्दी दो वर्ष के अंतराल के बाद 1990 में पहली बार लोगों के सामने आये।
- मुलायम सिंह यादव 1993 में पुनः (उत्तर प्रदेश) के मुख्यमंत्री बने थे।
- भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, इटली में पोम्पेली और हमयूलेनियम स्थल, पाकिस्तान में शेरशाह सूरी निर्मित रोहतास का किला और बांग्लादेश में सुंदरवन को 1997 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल या।
- वेंचेन्या में रूस ने 1999 में अस्थायी तौर पर सेना तैनात करने की घोषणा की।
- भारतीय सुंदरी युक्ता मुखी 1999 में 'मिस वर्ल्ड' चुनी गईं।
- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 2000 में राष्ट्रपति चुनाव में जार्ज बुश के पक्ष में फैसला दिया।
- अफगानिस्तान में 2001 में हामिद करजई के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन पर चारों गुट सहमत।
- अमरीकी सेनाओं ने 2001 में ओसामा बिन लादेन के अफगानिस्तान स्थित तोरा बोरा पहाड़ी ठिकाने पर कब्जा किया।
- चीन में 2003 में पहली बार आयोजित विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में ब्रायरलैंड की रोसान्ना दाविसन विजयी।
- वेंचेन्या में ट्रेन में 2003 में हुए आत्मघाती हमले में 42 लोगों की मृत्यु, जबकि 160 घायल। राष्ट्रकुल देशों के शासनाध्यक्षों का चार दिवसीय सम्मेलन अबुजा में प्रारम्भ।
- सन 2005 में बनाये गए एक नये कानून द्वारा ब्रिटेन में समलैंगिक पुरुष (गे) और समलैंगिक स्त्री (लेस्बियन) का वैध सम्बन्ध स्थापित करने की मान्यता दी गयी।
- रूस के राष्ट्रपति दमित्री मे देवेदेव ने 2008 में अगली पीढ़ी की परमाणु अभियांत्रिकी को भारत के साथ संयुक्त रूप से विकसित करने का प्रस्ताव किया।
- कांग्रेस ने 2008 में अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की।
- यमन की राजधानी सेना में रक्षा मंत्रालय परिसर पर 2013 में हुए आतंकवादी हमले में 52 लोगों की मौत।

5 दिसंबर को जन्मे व्यक्ति

- आधुनिक पंजाबी काव्य और गद्य के निर्माता के रूप में प्रसिद्ध कवि भाई वीर सिंह का 1872 में जन्म हुआ।
- भारत के क्रांतिकारियों में से एक एव. सी. दासप्पा का 1894 में जन्म हुआ।
- भारत और पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दू कवि जोश मलीहाबादी का 1898 में जन्म हुआ।
- जम्मू और कश्मीर के क्रांतिकारी नेता शेख़ मोहम्मद अब्दुल्ला का 1905 में जन्म हुआ।
- हिन्दी फ़िल्मों की मशहूर अभिनेत्री नादिरा का 1932 में जन्म हुआ।
- गुजराती साहित्यकार रघुवीर चौधरी का 1938 में जन्म हुआ।
- भारत की प्रसिद्ध महिला निशानेबाज़ अंजलि भागवत का 1969 में जन्म हुआ।

5 दिसंबर को हुए निधन

- जर्मनी के रसायन शास्त्री और दार्शनिक आलबर्ट महान का 1230 में निधन हुआ।
- स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद? और सामाजिक कार्यकर्ता एस. सुब्रह्मण्य अय्यर का 1924 में निधन हुआ।
- प्रसिद्ध भारतीय महिला चिकित्सक अमृता शेरगिल का 1941 में निधन हुआ।

प्रेरक प्रसंग

गुरू निष्ठा

गुरू के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का भाव मां शबरी में ही देखने को मिला लेकिन एक ऐसे संत भी हुए हैं जिन्होंनें ईश्वर से पहले अपने गुरू को स्थान दिया हैं। ब्रजमण्डल में अनेकों संत हुए हैं जिन्होंनें कृष्णमय जीवन जीया है,जिन्होंने राधा नाम की महिमा को समीप से समझा व जाना है। ब्रज के प्रमुख संत हैं .. श्री भट्टदेव, श्री विट्ठल बाहुदेव, श्री हरिराम व्यास, श्री हितहरिवंश, श्री नागरीदेव, श्री विहारिण देव, श्री रुपसखी, श्री ललित किशोरी, श्री भगवत रसिक, श्री पीतांबर, श्री ध्रुवदास, श्री हित वृंदावनदास, घनानंद, विद्यापति, रसखान व मीराबाई आदि। इन्हीं संतों में श्री हरिदासराम जी महाराज जिन्होंने अपने गुरू के प्रति सम्र्पण भाव को देखा है समझा है और जीया है। एक कथा के माध्यम से भक्ति प्रवाह को समझाने को प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों ये कहानी यदि आस्था,निष्ठा और प्रभु प्रेम की आसक्ति से सुने या पढ़ेंगे तो ईश्वर का आभास होगा और यदि इसे मनगढंत और मनमुखी समझ कर पढ़ेंगे तो ये महज एक स्टोरी सी प्रतीत होगी। संत विद्याचरण जी महाराज अपने चेले को ये कह कर कि कन्हैया के भजन करना,कीर्तन करना और यदि वो दर्शन भी दे तो आश्रम के भीतर ही दर्शन करना गोविंद के धाम समा गए। हरिदासराम जी महाराज हमेशा भजन व कीर्तन में लीन रहने लगे। एक दिन शाम को ठाकुरजी की आरती के समय पीछे से आवाज आई हरिदास पीछे देखो,तो संत ने सोचा कि हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो इसलिए कुछ बोले नहीं। आवाज दुबारा आई कि पीछे देख हरिदास, तो संत ने पीछे नहीं देखा और कह दिया कि कौन है, आगे आकर बात कर। आवाज आई मैं हूं,जिसके तू भजन कर रहा है सालों से, इधर हरिदासराम जी महाराज को भी थोड़ी सी सिहरन सी हुई पूरे शरीर में रोमांच सा भर गया। उन्हें पता तो चल गया कि कोई आलौकिक शक्ति है जो आवाज लगा रही है। अब संत ने फिर कहा कि आगे आजा जो भी होए। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये कैसा संत है जो तनिक भी टस से मस नहीं हो रहा। भगवान बोले देख रहा है पीछे या चला जाऊं,तो संत ने कहा मैंने कौन तो लोए बुलाऊं भेझो है, तू खुदही तो आयो है अभी ठाकुरजी की आरती हुई है भोग के बाद ही मैं उठूंगों। भगवान ने कहा कि मैं साक्षात आया हूं और तू ठसक में है। तो संत बोले वो साधु ही काहे को जामे ठसक नाय होए,दर्शन तोए देतो है आगे आके दे दे मोए तो तेरा दर्शन से ज्यादा रस तेरा भजन और तेरी कथान में आवे,और सुन यदि दर्शन भी देगों तो पाँच दस मिनट,यहां मेरे पास तो रूकेगो नाय, और काऊ नाम ते मोए अभी यहीं रहनों है, तो भाई मैं तो भजन में ही आनन्द ले रहयों हूं। आखिर भगवान को अंदर

आना पड़ा और सामने आकर खड़े हो गए। अखिलकोटि ब्रहम्माण्डनायक साक्षात भगवान श्री कृष्ण मुरली मनोहर खड़े हो गए। दिव्य तेज से सारा सत मण्डल प्रकाशित हो गया। संत ने भोग लगाया प्रद्य प्रक्षालण किए। तो भगवान बोले तू पीछे मुड के मेरा दर्शन क्यों नहीं कर रहा था कारण बता हरिदास। तो संत ने कहा कि मेरे गुरूवर कहकर गए थे कि यदि कन्हैया आ भी जाए तो उसके दर्शन आश्रम के भीतर ही करना। भगवान अचरज में पड़ गए और बोले कि गुरू जी बता के भी तो गए होंगें कि क्यूं ना करियों बाहर दर्शन। तो संत बोले- तो सुन ली भगवन,गुरूजी ने कहा कि हमारा आश्रम ब्रज की सीमा पर ही है। आश्रम के बाहर वाली सड़क ब्रज मण्डल के बाहर है यदि आश्रम में आकर भगवान गोविन्द, गोपाल,मुरलीमनोहर दर्शन देंगे तो हाथ में मुरली होगी और ब्रज के बाहर यदि कृष्ण के दर्शन करोगे तो द्वारिकानाथ के दर्शन होंगे हाथ में मुरली नहीं सुदर्शन होगा जो कभी भी गला रेत देगा। इसलिए गोपाल के दर्शन ही करना। संत की बात सुनकर कहते हैं भगवान वहां रूके और संत हरिदास जी महाराज के भजन व कीर्तन सुनकर गए।

रूपक शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार
दैनिक बढ़ता राजस्थान

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इण्डस्ट्री रोड खण्डवा,निवाई रोक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिष्ठा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान* । प्रधान संपादक-राम विलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 रोक कार्यालय-बाईपास निवाई, रोक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-सेहतास सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 249

डॉलर को खतरा नहीं

अमेरिका के साथी और विरोधी दोनों डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात के साफ संकेत हैं कि उनका दूसरा कार्यकाल मौजूदा विश्व व्यवस्था के लिए उनके पहले कार्यकाल की तुलना में अधिक अप्रत्याशित और शायद अधिक उथलपुथल भरा हो सकता है। भारत भी इससे सुरक्षित नहीं रहेगा। खबरों के मुताबिक संबंधित विभाग अमेरिका के साथ भारत की कारोबारी स्थिति का आकलन कर रहे हैं और संभावित दिक्कतों से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। शुल्क में कमी का मामला बनता है लेकिन भारत को अपनी स्थिति प्रस्तुत करने के लिए अमेरिकी प्रतिष्ठान के साथ अधिक सक्रियता से संबद्धता दिखानी होगी। यह दिलचस्प बात है कि ट्रंप ने हाल ही में ब्रिक्स देशों को धमकी दी है कि अगर उन्होंने ब्रिक्स मुद्रा बनाई या अमेरिकी डॉलर के स्थान पर किसी अन्य मुद्रा को तरजीह दी तो वह उन पर 100 फीसदी शुल्क लगा देंगे। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं और इसका विस्तार करके अन्य देशों को स्थान दिया जा सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि किस बात ने उन्हें यह टिप्पणी करने के लिए विवश किया लेकिन इससे मुद्रा बाजार में अस्थिरता आई। ऐसे में इस धमकी के गुणदोषों पर चर्चा करना जरूरी है।

पहली बात, फिलहाल जैसे हालात हैं उनमें अमेरिकी डॉलर को कोई खतरा नहीं दिखता। बैंक ऑफ इंटरनैशनल सेटलमेंट्स के 2022 के नोट के मुताबिक 90 फीसदी मुद्रा व्यापार में डॉलर शामिल था। करीब 60 फीसदी विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में हैं। दूसरा, किसी मुद्रा को आरक्षित मुद्रा का दर्जा देने की इच्छा का कोई खास अर्थ नहीं है। इसके अलावा अब तक संभावित ब्रिक्स मुद्रा का आकार और उसकी कार्यविधि को लेकर भी कुछ पता नहीं है। ट्रंप शायद ब्रिक्स के सदस्य देशों को हतोत्साहित करना चाह रहे थे। खास तौर पर वह चीन को मुद्रा परियोजना आगे ले जाने देने से रोकना चाहते थे। चाहे जो भी हो भारत को ऐसे प्रयासों से बचना चाहिए। चूंकि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए योजना में उसका कद भी बड़ा होगा। हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसे कैसे तैयार किया गया है। तीसरी बात, कुछ वैश्विक व्यापार समय के साथ युआन में स्थानांतरित हो सकता है क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ा है और उसके व्यापक कारोबारी संबंध हैं। बहरहाल, ऐसा सीमित दायरे में होगा क्योंकि चीन की पूंजी पर लगड़ा नियंत्रण है। मुद्रा भंडार की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार 2024 की दूसरी तिमाही में चीनी मुद्रा में करीब 245 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा रखी गई थी जबकि अमेरिकी डॉलर वाला मुद्रा भंडार 6.6 लाख करोड़ डॉलर था। विभिन्न देश कारोबारी लेनदेन की सुगमता और वित्तीय बाजारों की गहराई को देखेंगे जो डॉलर के पक्ष में है।

बहरहाल, यह बात ध्यान देने लायक है कि अगर डॉलर की स्थिति समय के साथ कमजोर पड़ती है तो इसकी वजह अमेरिकी राजनीति होगी। डॉलर के दबदबे वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना कुछ देशों पर विकल्प तलाशने का दबाव बनाएगी। इतना ही नहीं ट्रंप द्वारा उच्च कर को प्राथमिकता और व्यापार घाटे को समाप्त करने की कोशिश डॉलर के खिलाफ जा सकती है। अमेरिकी व्यापार घाटा शेष विश्व को डॉलर मुहैया कराती है। अगर आपूर्ति में उल्लेखनीय कमी आती है तो दुनिया विकल्प तलाशने पर विचार करेगी। भारत की बात करें तो गिफ्ट सिटी की स्थापना कुछ वित्तीय सेवाओं को देश में लाएगी और कंपनियों की लागत में कमी आएगी। ऐसे में निकट भविष्य में डॉलर पर निर्भरता कम होती नहीं नजर आती। अगर युआन अधिक लोकप्रिय होता है तो भी डॉलर भारत की प्राथमिकता वाली मुद्रा बना रहेगा। डॉलर की पुरानी मजबूती के अलावा भारत के हित भी चीन के बजाय अमेरिका से अधिक जुड़े हैं।

अजय मोहंती

विविध विकल्पों के बीच आरबीआई का चुनाव

मौद्रिक नीति समिति की तीन दिन की समीक्षा बैठक ऐसे समय में हो रही है जब वृद्धि में धीमापन आया है, मुद्रास्फीति ऊंचे स्तर पर है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है। बता रहे हैं तमाल बंद्योपाध्याय

नवंबर के पहले सप्ताह में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी मानक ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कमी करके उसे 4.5 से 4.75 फीसदी कर दिया जो मार्च 2023 के बाद का न्यूनतम स्तर है। फेड की नीतिगत समिति ने सर्वसम्मति से मौजूदा चक्र में लगातार दूसरी बार कटौती की। इन दो कटौतियों की बदौलत फेडरल फंड्स की दर में कुल मिलाकर 75 आधार अंकों की कमी आई है।

विश्लेषक कहते हैं कि अगर फेड दिसंबर की बैठक में तथा 2025 में भी दरों में कटौती जारी रखता है तो बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। सीईएम फेडवॉच के अनुमानों के मुताबिक दिसंबर में फेड द्वारा दरों में कटौती करने की 60 फीसदी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो 4.25 से 4.5 फीसदी के साथ दरें हालिया उच्चतम स्तर से एक फीसदी कम हो जाएंगी। सीईएम फेडवॉच एक टूल है जो 30 दिवसीय फेड फंड वायदा के मूल्य संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करके दरों में बदलाव का अनुमान लगाता है।

नवंबर में उम्मीद के मुताबिक ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी दूसरी बार दरें कम करके उन्हें 4.75 फीसदी करने की बात कही। यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) ने इस साल ब्याज दरें तीन बार कम कीं और ऋण दर को 3.25 फीसदी कर दिया। माना जा रहा है कि वह दिसंबर में एक बार फिर 25 आधार अंकों की कमी के बाद अगले वर्ष फिर कटौती करेगा। विश्लेषकों का मानना है कि ईसीबी की अहम जमा दर को 2025 के मध्य तक कम करके दो फीसदी कर दिया जाएगा। दरों में पिछली कटौती अक्टूबर में हुई थी और वह 13 साल में पहला मौका था जब लगातार कटौती की गई थी।

रिजर्व बैंक ने अक्टूबर की अपनी नीति में मुद्रास्फीति से निपटने का निर्णय किया जो खाद्य कीमतों के कारण बढ़ी हुई थी। उसने फेड का अनुसरण नहीं किया। गत शुक्रवार को दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े जारी होने तक देश में मुद्रास्फीति की वृद्धि का गणित दरों में कटौती के अनुकूल नहीं था। परंतु दूसरी तिमाही में 5.4 फीसदी की जीडीपी ने हालात को बदल दिया। यह दर 6.5 फीसदी के अनुमान से काफी कम थी। यह सात तिमाहियों में सबसे कम दर है और पिछली तिमाही के 6.7 फीसदी के अनुमान से नीचे है।

सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) भी दूसरी तिमाही में 5.6 फीसदी के साथ काफी कम रहा जबकि इसके 6.3 फीसदी रहने का अनुमान था। वृद्धि-मुद्रास्फीति के गणित में संतुलन अचानक वृद्धि के समर्थन की दिशा में झुक गया है। यानी आरबीआई को दरों में कटौती करनी चाहिए। यह इतना आसान नहीं है। वृद्धि में उल्लेखनीय धीमापन आया है लेकिन मुद्रास्फीति अभी भी काफी अधिक है। यह रिजर्व बैंक के लचीले लक्ष्य से ऊपर है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है।

सैद्धांतिक रूप से जब फेड दरें बढ़ाता है तो रिजर्व बैंक पर यह दबाव होगा कि वह भी ऐसा करे। परंतु जब वह दरें कम करता है तो भारतीय केंद्रीय बैंक को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि फेड द्वारा दरों में कटौती फेड और आरबीआई के ब्याज दर अंतर को बढ़ा देती है। परंतु डॉलर के समक्ष रुपये में कमजोरी के बीच वृद्धि में धीमापन और उच्च मुद्रास्फीति ने रिजर्व बैंक के लिए नीतिगत कठिनाई पैदा की है।

अक्टूबर में रिजर्व बैंक की नवगठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने रीपो दर को 6.5 फीसदी पर अपरिवर्तित रखा लेकिन उसने समायोजन को समाप्त करने की जगह 'तटस्थ' रुख अपनाया।

इससे यह संकेत मिला कि केंद्रीय बैंक नीतिगत रुख में बदलाव ला रहा है। या फिर हमें ऐसा लगा। परंतु बाद में रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्पष्ट किया कि कुछ नहीं बदला है और तटस्थ रुख का कुछ खास अर्थ नहीं है। यह वृद्धि को लेकर भी आशान्वित रहे।

अक्टूबर की बैठक के पहले देश की खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर जुलाई में 3.6 फीसदी और अगस्त में 3.65 फीसदी रही जो रिजर्व बैंक के मुद्रास्फीति के चार फीसदी के लक्ष्य (दो फीसदी इधर या उधर) से कम था।

तब से मुद्रास्फीति का दायरा बदल गया है। मुद्रास्फीति में इजाफे की उम्मीद थी लेकिन अक्टूबर में यह जिस तेजी से बढ़ी वह अनुमान से परे था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति साल दर साल आधार पर 6.21 फीसदी के साथ 14 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सितंबर में यह 5.49 फीसदी थी। खाद्य मुद्रास्फीति भी सितंबर के 9.2 फीसदी से बढ़कर 10.9 फीसदी हो गई जो 15 महीनों का उच्चतम स्तर था। वहीं गैर खाद्य-गैर तेल मुद्रास्फीति भी सितंबर के 3.6 फीसदी से बढ़कर 3.8 फीसदी हो गई जो 11 महीने का उच्चतम स्तर था।

अक्टूबर की नीति में रिजर्व बैंक ने दिसंबर तिमाही में 4.8 फीसदी की मुद्रास्फीति का अनुमान जताया था। मार्च तिमाही में इसके 4.2 फीसदी और पूरे वित्त वर्ष में 4.5 फीसदी रहने की बात कही गई थी। यकीनन खाद्य कीमतों में कमी के चलते खुदरा मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति मार्च तिमाही में पांच फीसदी से नीचे आ जाएगी। परंतु दिसंबर तिमाही में यह 5.5 फीसदी से छह फीसदी के बीच रह सकती है। पूरे वर्ष के लिए यह 4.7 फीसदी से 4.9 फीसदी के बीच रह सकती है यानी रिजर्व बैंक के अनुमानों से अधिक।

उसी नीति में रिजर्व बैंक ने कहा कि देश की वृद्धि गाथा बरकरार रही क्योंकि खपत और निवेश मांग के रूप में उसके बुनियादी कारक गति पकड़ते रहे। उसने पाया कि निजी खपत की संभावनाएं बेहतर हैं क्योंकि बेहतर कृषि के कारण ग्रामीण मांग में बेहतरी देखने को मिल सकती है। चुनाव के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के व्यय में भी सुधार होने की उम्मीद थी।

उसने 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2 फीसदी रहने का अनुमान जताया है। सितंबर तिमाही में इसके 7 फीसदी और दिसंबर और मार्च तिमाही में इसके 7.4 फीसदी रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 की जून तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.3 फीसदी रहने की बात कही गई है।

अहम सवाल यह है कि क्या आरबीआई इस सप्ताह दरों में कटौती करेगा?

अगर केंद्रीय बैंक दरों में कटौती करता है तो वृद्धि के मोर्चे पर जोखिम होगा जो अनावश्यक होगा। खासतौर पर तब जबकि आने वाली तिमाहियों में वृद्धि में इजाफा नजर आएगा। इसके अलावा मुद्रास्फीति भी काफी ऊंची है। क्या उसे नकद आरक्षित अनुपात यानी सीआरआर में कटौती करनी चाहिए? व्यवस्था में नकदी की स्थिति तंग है। रिजर्व बैंक स्थानीय मुद्रा में तेज गिरावट को थामने के लिए डॉलर की बिक्री कर रहा है। वह जितने डॉलर बेचता है उतने ही मूल्य का रुपया व्यवस्था से बाहर जाता है। इसके अलावा बिना नकदी की स्थिति में सुधार के दरों में कटौती का कोई तुक नहीं बनता क्योंकि यह बैंकों के लिए नुकसानदायक होगा।

आरबीआई अगर इस तिहरी दुविधा की स्थिति का प्रबंधन करना है तो उसे खुले बाजार की गतिविधियों का चयन करना चाहिए और बैंकों से चरणबद्ध तरीके से सरकारी बॉन्ड खरीदने चाहिए ताकि नकदी की स्थिति बहाल हो सके। वह फरवरी में होने वाली बैठक में दरों में कटौती भी कर सकता है क्योंकि उस समय तक मुद्रास्फीति में धीमापन आना शुरू हो जाएगा। जीडीपी वृद्धि में तेज गिरावट के बावजूद लगता नहीं कि शुक्रवार को रिजर्व बैंक दरों में कटौती करेगा। बाजार भी रिजर्व बैंक के कदमों से अधिक उसके संवाद पर नजर रखेगा। कोविड महामारी की अवधि को छोड़ दिया जाए तो यह शक्तिकांत दास के लिए सबसे कठिन नीति है। उनका मौजूदा कार्यकाल नीतिगत घोषणा के एक सप्ताह के भीतर समाप्त हो जाएगा।

ज्यादा मुसीबत लाएगा ट्रंप का दूसरा कार्यकाल

नीति नियम

मिहिर शर्मा

दुनिया ने डॉनल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की बात को अप्रत्याशित रूप से स्वीकार कर लिया है। उन्होंने 2016 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीता था और उस जीत का जिस आक्रोश, भय और तिरस्कार भाव के साथ स्वागत किया गया था, उसकी तुलना में इस बार उनकी जीत को कुछ हद तक आश्वस्ति के साथ देखा जा रहा है। यहां तक अमेरिकी उदारवादियों में भी आठ साल पहले की तुलना में कम आत्मावलोकन देखने को मिल रहा है और 'प्रतिरोध' को लेकर पहले जैसी प्रतिबद्धता भी नहीं नजर आ रही है। आम भावना यह नजर आ रही है कि वह एक बार सत्ता में रह चुके हैं और उनके रहने से दुनिया खत्म तो नहीं हो गई।

हालांकि यह सोचने की भी पर्याप्त अच्छी वजहें हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप का अगला कार्यकाल, पिछले कार्यकाल की तुलना में अधिक उथलपुथल वाला होगा। ऐसी चार वजहों की बात करते हैं।

पहली वजह, इस बार उनके पास जबरदस्त जनादेश है। 2016 में वह लोकप्रिय वोट में हार गए थे और निर्वाचक मंडल में भी एक लाख से कम वोटों ने तीन अहम स्विंग राज्यों को उनके पक्ष में किया था। स्विंग राज्य उन्हें कहा जाता है जहां चुनाव परिणाम किसी भी दल की ओर जा सकते हैं। इस साल वे उन राज्यों में भी अपेक्षाकृत आसानी से चुनाव जीत गए। पुराने स्विंग राज्यों मसलन फ्लोरिडा में उन्हें बड़े अंतर से जीत मिली। डेमोक्रेटिक पार्टी की ये उम्मीदें खत्म हो गई हैं कि टेक्सस अगला स्विंग राज्य होगा क्योंकि ट्रंप ने वहां अपने प्रतिद्वंद्वियों पर भारी बढ़त हासिल कर ली। रिपब्लिकन पार्टी ने सीनेट पर नियंत्रण कर लिया और बहुत सहजता से वे सरकार की तीनों शाखाओं पर काबिज हैं। पारंपरिक रूप से डेमोक्रेट पार्टी के साथ रहे न्यूयॉर्क जैसे क्षेत्रों में ट्रंप के पक्ष में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अपने पहले कार्यकाल में सरकार के भीतर और बाहर उनके प्रतिद्वंद्वियों का मानना था कि यह उनका नैतिक अधिकार और लोकतांत्रिक दायित्व है कि वे उनके कदमों का विरोध करें। अगले चार साल में विपक्ष सुनिश्चित तरीके से यह नहीं कह सकता।

दूसरा कारण, उन्होंने पारंपरिक रिपब्लिकन पार्टी से निर्णायक ढंग से राह अलग कर ली है। पहले कार्यकाल में उनकी कैबिनेट और व्हाइट हाउस के लिए चुने गए लोगों में पार्टी के प्रतिनिधियों का वर्चस्व था। जो लोग बाहर से चुने गए थे मसलन उनके पहले विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन या उनके पहले रक्षा मंत्री जिम मैटिस, को किसी भी रिपब्लिकन कैबिनेट के ऐसे सदस्य के रूप में देखा जा सकता है जिन्हें बाहर से लाया गया। इनमें से एक तेल कंपनी का पूर्व मुखिया था और दूसरा सेवानिवृत्त चार सितारा जनरल। इस कार्यकाल में अब तक जितने नाम घोषित किए गए हैं वे इस दूसरे कार्यकाल के लिए बहुत अलग रुख प्रदर्शित करते हैं। फ्लोरिडा के विवादास्पद रिपब्लिकन मैट गेट्ज अब अटॉर्नी जनरल नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। परंतु न्याय विभाग में जेफ सेशंस जैसे रुढ़िवादी लेकिन मुख्यधारा के रिपब्लिकन सीनेटर की तैनाती और गेट्ज को नामित करने में बहुत अधिक अंतर है। याद रहे कि सेशंस ने 2016 में रूसी हस्तक्षेप की जांच के मामलों में स्वतंत्र अभियान के लिए काफी समय तब दबाव बनाए रखा था। ऐसी ही चिंताएं ट्रंप द्वारा रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री या राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के पदों पर चुने गए नामों को लेकर भी होनी चाहिए। 2016 की ट्रंप सरकार स्पष्ट रूप से एक रिपब्लिकन सरकार थी। ट्रंप 2024 में पूरी तरह दक्षिणपंथी सरकार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं।

तीसरी बात, 2024 में दुनिया 2016 की तुलना में अधिक खतरनाक हो चुकी है। अब चूक की गुंजाइश बहुत कम है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में विदेश नीति को सबसे बड़ी चुनौती थी उत्तर कोरियाई मिसाइल परीक्षण। आज चीन की आक्रामकता को देखते हुए न केवल उत्तर-पूर्वी एशिया कहीं कम सुरक्षित है बल्कि यूरोप और पश्चिम एशिया में भी क्षेत्रीय स्तर पर हिंसक घटनाएं भड़क रही हैं। ये बातें दुनिया को और गहरे संकट की दिशा में ले जा सकती हैं।

चौथी बात, खुद ट्रंप की बात करें तो वे 78 साल के हो चुके हैं। पहली बार राष्ट्रपति बनते समय उनकी उम्र 70 वर्ष से कम थी। राष्ट्रपति पद का दबाव उन्हें प्रभावित करेगा। उनके भाषण बताते हैं कि उनमें भटकाव है। परंतु उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनकी शिकायतें भी बढ़ रही हैं। 2016 में उन्होंने संघीय सरकार को एक नए खिलौने की भांति देखा होगा जिसके साथ वे खेल सकते थे। 2024 में कई जांचों और अभियोगों के बाद शायद वे इसे एक शत्रु के रूप में देखें। उनका दूसरा कार्यकाल उस राज्य के विरुद्ध बागी होने का हो सकता है जिस पर उनका शासन है।

यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय जैसे एक-दो अपवादों को छोड़कर अमेरिकी घरेलू संस्थान, ट्रंप के पहले कार्यकाल में बरकरार रहे और उसके बाद दोबारा उठ खड़े हुए। उनके जलवायु समझौते से पीछे हटने तथा विश्व व्यापार संगठन को कमजोर करने से वैश्विक संचालन प्रभावित हुआ लेकिन जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर जहां इसका असर नहीं हुआ वहीं विश्व व्यापार संगठन के मामले में उनके बाद राष्ट्रपति बने जो बाइडन ने उसी रुख को जारी रखा। परंतु मैं यह कहने की जल्दबाजी नहीं करूंगा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अंत में भी हम यही कहने में सफल होंगे।

आपका पक्ष

सबसे पहले वैश्विक सुरक्षा फिर अर्थव्यवस्था

लेख 'ट्रंप का दूसरा कार्यकाल आसियान की दुविधा' अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे डॉनल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान और इंडो पैसिफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क और चीन की बेल्ट ऐंड रोड इनीशिएटिव के भविष्य पर अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में गहन चर्चा करता है। सभी देशों में और वैश्विक परिदृश्य में अर्थव्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दे कर विचार विमर्श और नीति निर्धारण होता है। परंतु देशों की सुरक्षा और सामरिक शक्ति के साथ ही अर्थव्यवस्था का विकास संभव है। डॉनल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रवादी नेता दूसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं तो इसका अर्थ है कि अमेरिका उन ताकतों को उखाड़ना चाहता है जो देश की अस्मिता, सामरिक शक्ति और उसके वैश्विक प्रभाव को खोखला करना चाहते हैं। इस परिदृश्य में चीन की हिंद महासागर में विस्तारवादी भूमिका, जापान-ताइवान- भारत जैसे देशों को चुनौती देता है। चीन का आसियान और बॉर्डर रोड इनीशिएटिव के माध्यम से विभिन्न देशों को ऋण जाल फंसाकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयासों को भी ध्यान में रखना चाहिए। चीन की जो स्थिति अमेरिका के साथ है वैसी स्थिति यूरोप और भारत में भी है। जिन विषम परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक प्रभाव क्षीण हो रहा है, ऐसे में क्षेत्रीय संगठनों की सफलता पर संदेह तो निश्चित रूप से रहेगा।

विनोद जौहरी, दिल्ली

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप 20 जनवरी, 2025 को अपने देश के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे

कौशल का संकट और विकास का सपना

भारत, एक विकासशील राष्ट्र के रूप में, 2047 तक एक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखता है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए आर्थिक वृद्धि दर को 10 प्रतिशत के आसपास बनाए रखना आवश्यक है। भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कौशल का संकट है। भारत में बेरोजगारी की समस्या गहराती जा रही है, वहीं उद्योगों में कुशल श्रमिकों की कमी है। देश में हर साल लाखों इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स और अन्य पेशेवर तैयार होते हैं, लेकिन कई युवा के पास उद्योगों की जरूरत के अनुरूप कौशल नहीं होते हैं। कौशल संकट से निपटने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। पाठ्यक्रम को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना होगा।

राजूराम प्रजापत, नागौर

बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध

ऑस्ट्रेलिया में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के प्रयोग पर प्रतिबंध वाला कानून पारित किया है। केवल कानून बनाकर बच्चों को इसके दुष्प्रभाव से बचाना संभव नहीं है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए माता-पिता, शिक्षक और समाज की सामूहिक भूमिका अहम है। उन्हें डिजिटल साक्षरता, जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार और स्क्रीन टाइम प्रबंधन करने और सकारात्मक सामग्री की ओर प्रोत्साहित करने की जरूरत है। साथ ही, सोशल मीडिया कंपनियों को भी बच्चों के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

प्रो. आरके जैन, बड़वानी

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

अमेरिका के राष्ट्रपति आवास 'व्हाइट हाउस' के सामने बुधवार को बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। वे चिन्मय कृष्ण ब्रह्मचारी को रिहा करने और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की रक्षा करने की मांग कर रहे थे।

कल्पमेधा

सहनशील होना अच्छी बात है, परंतु अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है।

– जयशंकर प्रसाद

सुरक्षा पर सवाल

पंजाब अलगाववादी गतिविधियों के लिहाज से अब भी संवेनशील राज्य है। पिछले कुछ समय से फिर कनाडा आदि देशों में रह रहे कुछ अलगाववादी सिख खालिस्तान की मांग उठाने लगे हैं। उसका कुछ असर पंजाब में भी देखा गया। हालांकि सरकार ने चुस्ती दिखाई और ऐसे तत्त्वों पर लगाम कसने में कामयाब हुई। मगर पिछले कुछ समय से पंजाब में आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, दिनदहाड़े और सरेआम किसी को गोली मार देने में भी अपराधियों को कोई हिचक नहीं होती। ऐसे वातावरण में पुलिस से अधिक चौकस रहने की अपेक्षा की जाती है। मगर पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जिस तरह स्वर्ण मंदिर परिसर में जानलेवा हमला हो गया, उससे जाहिर है कि पुलिस ने उनकी सुरक्षा के अपेक्षित इंतजाम नहीं किए थे। जिस व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई वह खालिस्तान समर्थक पूर्व आतंकवादी है। रामरहीम के आपराधिक मामले में सुलह करवाने के आरोप में अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित कर गुरुद्वारे में सेवा करने और कीर्तन सुनने का आदेश दिया था। उसी का पालन करते हुए स्वर्ण मंदिर परिसर में वे सेवा दे रहे थे। एक व्यक्ति ने उसी वक्त उन पर हमला करने की कोशिश की। गनीमत थी कि वहां सादी वर्दी में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे दबोच लिया। इस तरह गोली बादल को न लग कर दीवार पर जा लगी।

हालांकि स्वर्ण मंदिर परिसर में उस तरह श्रद्धालुओं की तकनीकी जांच नहीं होती, जिस तरह अन्य अनेक पूजा स्थलों पर की जाती है। श्रद्धालु मुक्त रूप से परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। पर सुरक्षा के लिहाज से परिसर में सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। यह अच्छी बात है कि श्रद्धा के मामले में वहां सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, मगर सुखबीर बादल वहां किसी सामान्य श्रद्धालु की तरह नहीं गए थे। उनकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह की लापरवाही की अपेक्षा नहीं की जा सकती। गनीमत है कि सादी वर्दी में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उस हमले को नाकाम कर दिया, पर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि आखिर बंदूक लेकर कोई शख्स कैसे पूर्व मुख्यमंत्री के करीब तक पहुंच गया। अगर उसे परिसर में प्रवेश से पहले ही पकड़ लिया जाता, तो वह गोली चलाने में कामयाब ही न हो पाता। दूसरी बात, कि अगर मंदिर परिसर में सादी वर्दी में प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तैनात थे, तो उन्हें उस व्यक्ति को पहचानने में इतनी देर कैसे हो गई कि वह बादल के करीब तक पहुंच गया।

पंजाब सीमावर्ती राज्य होने के कारण भी बहुत संवेदनशील है। अमृतसर तो बिल्कुल पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ है। यह भी छिपी बात नहीं है कि अलगाववादी तत्त्वों के तार पाकिस्तानी दहशतगर्दों से भी जुड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति ने बादल पर हमला किया, उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि खालिस्तान आंदोलन के दौरान पाकिस्तान गया था। ऐसे में पुलिस और सुरक्षाबलों की मामूली लापरवाही भी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। पंजाब में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर काबू न पा सकने की वजह से स्वाभाविक ही वहां की राज्य सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। सुखबीर बादल पर हमले के बाद फिर से सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर अंगुलियां उठने लगी हैं। हमला करने वाले की बादल पर गोली चलाने के पीछे मंशा चाहे जो रही हो, पर चिंता की बात है कि वह सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी का फायदा उठाने में कामयाब हो गया।

दावों की पोल

देश की राजधानी में डेंगू के साथ मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, उससे यह साबित हो गया कि स्थानीय निकाय के साथ राज्य सरकार भी इनकी रोकथाम के लिए गंभीर नहीं थी। इसी के साथ उनके तमाम दावों की पोल भी खुल गई है। यह हाल तब है जबकि दिल्ली सरकार का शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा बजट है। यह दुखद है कि डेंगू के मामले प्रति वर्ष आते हैं, लेकिन इसे रोकने की पुख्ता तैयारी नहीं होती। इस साल नवंबर तक करीब पौने छह हजार लोग डेंगू की चपेट में आए। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक यह संख्या पांच वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। चिकनगुनिया से भी दिल्लीवासी त्रस्त रहे। मलेरिया सहित इस तरह के रोग आमतौर पर अगस्त-सितंबर में बढ़ते हैं और मौसम में ठंडक उतरने के साथ अक्तूबर-नवंबर तक समाप्त हो जाते हैं। मगर इस बार मौसम निकल जाने पर भी लोग मच्छरजनित बीमारियों की चपेट में आते रहे। हालांकि दिल्ली नगर निगम ने लार्वारोधी उपायों, धुएं के छिड़काव और दवा आदि पर खर्च करने की बात कही है, फिर भी मामले नहीं थमे। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं उससे बड़ी चूक हुई है।

अमूमन सर्दियों की शुरुआत के साथ मच्छर कम होने लगते हैं, लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से बीमारियां बढ़ीं। अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। जबकि मच्छरों से निपटने और इलाज आदि पर सौ करोड़ रुपए खर्च करने की जानकारी दिल्ली नगर निगम ने दी है। आखिर इतनी बड़ी राशि किस तरह और कहां खर्च हुई, यह जांच का विषय है। बीमारियों से निपटने के उपायों पर स्थानीय निकाय और राज्य सरकार में समन्वय होना चाहिए। खासकर जब एक ही दल दोनों जगह सत्तारूढ़ हो। कोई दो राय नहीं कि राज्य सरकार और नगर निगम अगर योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाते, तो डेंगू और चिकनगुनिया के मामले इतने नहीं बढ़ते। सरकार मोहल्ला क्लीनिकों को सक्रिय कर सकती थी। मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए टीमें तैनात की गई थीं, लगातार जनजागरूकता अभियान चलाए जाते रहे, इसके बावजूद इन बीमारियों का बढ़ते जाना चिंता की बात है।

बढ़ता मृदा प्रदूषण, घटता उत्पादन

मृदा क्षरण का गहराता संकट न सिर्फ पैदावार को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में यह अनेक समस्याओं का कारण बन रहा है, जिनमें मुख्य रूप से पारिस्थितिकी असंतुलन भी शामिल है।

कुशाग्र राजेंद्र

मिट्टी के ऊपर भुरभुरा और स्नेहिल तत्त्व बीजों को अंकुरित कर और जड़ों को धारण कर हमारी धरती पर जीवन सुनिश्चित करता है। यह आज के दौर में आठ अरब लोगों के लिए खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने, बिगड़ते पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और जलवायु संकट को काफी हद तक कम करने का मजबूत संबल है। मगर आज प्राणियों के लिए पोषक मिट्टी का अस्तित्व खुद गंभीर संकट में घिरा है। मिट्टी का बड़े पैमाने पर क्षरण न केवल कृषि पैदावार और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को और अधिक व्यापक तथा जटिल बना रहा है। मिट्टी के क्षरण के साथ उसकी उत्पादकता की कमी धीरे-धीरे बढ़ रही है, प्रदूषण के इतर इसका दायरा आधुनिक कृषि तरीकों के कारण दबे पांव फैल रहा है।

मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, जमा होता नमक और जहरीले रसायनों के संदूषण और फसल उत्पादन में आ रही कमी मृदा क्षरण के दायरे में आते हैं। मृदा क्षरण आमतौर पर मौजूदा रसायनों (जिसमें खाद और जहरीले कीटनाशक शामिल हैं) के अंधाधुंध इस्तेमाल, भूमि के परंपरागत उपयोग में व्यापक बदलाव, जंगल की कटाई, बाढ़, सुखाड़, जलजमाव और जलवायु परिवर्तन से तापमान आदि कारणों से पैदा होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां खेती-किसानी आज भी अधिकांश लोगों के लिए जीविका का स्रोत है, दस लाख 78 हजार वर्ग किलोमीटर दायरे में फैले विश्व के दूसरे सबसे बड़े कृषि तंत्र की रीढ़ मिट्टी ही है। मृदा क्षरण का गहराता संकट न सिर्फ पैदावार को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में यह अनेक समस्याओं का कारण बन रहा है, जिनमें मुख्य रूप से पारिस्थितिकी असंतुलन भी शामिल है। मिट्टी सर्वेक्षण के राष्ट्रीय ब्यूरो के मुताबिक भारत में लगभग एक-तिहाई मिट्टी यानी लगभग 12 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र मृदा क्षरण के दायरे में है, जिसका अच्छा-खासा हिस्सा समुद्र के लवणीकरण से प्रभावित है।

बड़े पैमाने पर मृदा क्षरण के बावजूद, तकनीक आधारित गहन कृषि के कारण पैदावार में वृद्धि हुई है, और अब भारत कृषि उपज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चह खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। मगर बाढ़ के दौरान और निर्माण कार्य के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी के कटाव, रासायनिक खाद के व्यापक इस्तेमाल से जमा होती लवणता, बढ़ती अम्लीयता और जलभराव आदि से कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भाग ऊसर होता जा रहा है। अगर इसी तरह मृदा क्षरण जारी रहा तो आने वाले वर्षों में खाद्य आयात करना पड़ सकता है, जबकि भारत, दुनिया के केवल 2.4 फीसद भूमि क्षेत्र के साथ, विश्व की 18 फीसद आबादी की खिलाने में सक्षम है।

मृदा क्षरण के प्रमुख कारणों में अमर्यादित तरीके से खेती के अलावा बड़े पैमाने पर शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए भूमि उपयोग में व्यापक बदलाव भी जिम्मेदार है। इसके साथ-साथ भारत मवेशियों की संख्या के लिहाज से भी सबसे बड़ा देश है। इनके चरने के दौरान जमीन की ऊपरी वनस्पति हटने से मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर हो

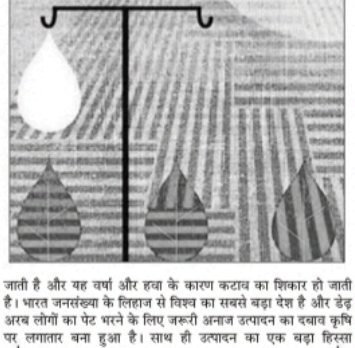

जाती है और यह वर्षा और हवा के कारण कटाव का शिकार हो जाती है। भारत जनसंख्या के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा देश है और डेढ़ अरब लोगों का पेट भरने के लिए जरूरी अनाज उत्पादन का दबाव कृषि पर लगातार बना हुआ है। साथ ही उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा

> **उर्वर मिट्टी आज के दौर में भारत जैसे देश के लिए न सिर्फ पेट भरने किए जरूरी, बल्कि अर्थव्यवस्था की धुरी है। ऐसे में जरूरत है कि मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक तरीके से वापस लाया जाए। इसके लिए हमें मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक स्वास्थ्य को बहाल करने की आवश्यकता होगी, जो एक लंबी और जटिल, पर संभव प्रक्रिया है। अपने जैविक तत्व यानी कार्बन को खोकर ऊसर हो चुकी मिट्टी में दोबारा जैविकता लौटाने की जरूरत होगी। अभी कुल इस्तेमाल हो रहे उर्वरकों में केवल छह फीसद जैविक स्रोत वाले उर्वरक का इस्तेमाल हो रहा है। जरूरत है कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम कर जैविक खाद आधारित खेती-किसानी को प्रोत्साहन मिले।**

रखरखाव और अक्षम प्रबंधन के कारण बर्बाद हो जाता है। इन सबका असर अंततः मिट्टी पर पड़ता है।

आजादी के बाद अनाज की बढ़ती जरूरत और खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए हरित-क्रांति का प्रकल्प लागू हुआ, जो मुख्य रूप से कृत्रिम सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और संकर बीज पर आधारित था, जिसका मुख्य लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन। इस प्रयास में मिट्टी की उर्वरता नेपथ्य में चली गई। लगातार एक ही तरह की फसल उगा कर ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा किया जाने लगा, जिससे मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्त्व कम होने लगे। इसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव और जैविक पदार्थ खत्म होते चले गए। वर्तमान में कृषि कार्य में 94 फीसद तक रासायनिक उर्वरक का उपयोग होता है। यहां तक कि रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से हमारे खेतों और फसलों को जहरीला बना दिया। हरित-क्रांति के दौरान हमारा अनाज उत्पादन पांच करोड़ टन से बढ़ कर तीस करोड़ टन पहुंच गया, पर यह उपलब्धि उपजाऊ मिट्टी की कीमत पर हासिल की गई प्रतीत होती है।

ऐसे में मिट्टी का तेज गति से क्षरण भारत की बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा के गंभीर संकट का कारण बन सकता है। मृदा क्षरण के कारण न सिर्फ उत्पादकता में कमी आती है, बल्कि इसमें प्राकृतिक रूप से मौजूद कार्बन की मात्रा कम हो जाने से इसकी पानी सोखने और जकड़ कर रखने की क्षमता भी काफी हद तक घट जाती है। नतीजा यह कि पानी के स्रोतों से जल का पुनर्भरण काफी कम हो जाता है, जो भारत में बड़े स्तर के भूजल स्तर में गिरावट और सूखे की बड़ ही समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। हरियाणा और पंजाब, जो भारत के सबसे अधिक अनाज उत्पादक हैं, वहां जल स्तर खतरनाक रूप से गिर चुका है। समृद्ध और उपजाऊ मिट्टी कृषि-प्रधान भारत के लिए वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रखती है। तभी तो पिछले कुछ दशक में आई बड़े स्तर की वैश्विक मंदी में भी भारतीय अर्थव्यवस्था मामूली असर के साथ तेजी से आगे बढ़ती रही।

उर्वर मिट्टी आज के दौर में भारत जैसे देश के लिए न सिर्फ पेट भरने किए जरूरी, बल्कि अर्थव्यवस्था की धुरी है। ऐसे में जरूरत है कि मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक तरीके से वापस लाया जाए। इसके लिए हमें मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक स्वास्थ्य को बहाल करने की आवश्यकता होगी, जो एक लंबी और जटिल, पर संभव प्रक्रिया है। अपने जैविक तत्त्व यानी कार्बन को खोकर ऊसर हो चुकी मिट्टी में दोबारा जैविकता लौटाने की जरूरत होगी। अभी कुल इस्तेमाल हो रहे उर्वरकों में केवल छह फीसद जैविक स्रोत वाले उर्वरक का इस्तेमाल हो रहा है। जरूरत है कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम कर जैविक खाद आधारित खेती-किसानी को प्रोत्साहन मिले। हालांकि इससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी की आशंका शामिल है।

भारत में प्रकृति केंद्रित समृद्ध कृषि परंपरा रही है, जो मिट्टी की क्षमता, मौसम और पानी की उपलब्धता के सामंजस्य पर आधारित है। इसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। दबे पांव मिट्टी-पानी का संकट हमारे खेतों से होते हुए हमारी थाली तक आ पहुंचा है। ऐसे में इस भीषण समस्या का संज्ञान लेने और सरकार, समाज तथा व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है।

जिंदगी के मोड़

प्रभात कुमार

जिंदगी के रास्तों पर अनेक जगह चाहे-अनचाहे मोड़ आ जाते हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता। किसी भी रास्ते पर सही जगह मुड़ने का खास महत्त्व है। वाहन चलाते हुए भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हम रास्ता भूल जाते हैं, सड़क पर आगे निकल जाते हैं और एकदम से बाएं या दाएं नहीं मुड़ सकते। हमें कुछ आगे जाकर वापस मुड़ने के लिए अगर थोड़ी दूरी से पीछे आना पड़ता है और सही रास्ता लेना होता है। खासकर लंबी दूरी की सड़कों पर कहीं भी मुड़ जाने की सुविधा हर कहीं नहीं होती। इस क्रम में कई बार काफी दूरी का सफर तय करना पड़ता है। अपनी मर्जी से कहीं भी मुड़ जाने पर तेज रफ्तार सड़कों पर जोखिम से गुजरना या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है। जिंदगी एक दिलचस्प, अप्रत्याशित घटनाओं और संभावनाओं से भरा सफर है। इसे सुरक्षित तरीके से तय करते रहने वाले भी अनेक बार गलती से आगे, इधर या उधर चले जाने के कारण थोड़ा पीछे आते हैं और फिर सही रास्ता अपना लेते हैं, ताकि आगे बढ़ते रहें। यों भी, सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अगर थोड़ी दूरी भी तय करनी पड़े, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बल्कि यह अपने हित में होता है।

दुनिया मेरे आगे

इस सफर में उचित स्थिति अपने मन की बात कहकर यह आकलन कर लेने की है कि आपके शब्द सामने वाले को बुरे तो नहीं लगे या कितने बुरे लगे। अगर माफी मांगना जरूरी है, तो वक्त की जरूरत के मुताबिक माफी मांग भी लेनी चाहिए। खुले दिल से माफी मांग ली जाए तो संबंधों का पुल सलामत रहता है। जमाने से सुनते आए हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन जबान से निकले शब्दों से बना जख्म कभी नहीं भरता। हालांकि वक्त के साथ यह बात अपनी प्रवृत्ति बदल रही है। शब्द उन फलों की तरह हैं कि पहले भेंट कर दें, पता चले कि सामने वाले ने चख लिए, लेकिन स्वाद नहीं लगे तो फल वापस ले लिए जाएं। शब्दों में अब वह पुरानी बात नहीं रही। जिंदगी बाजार की गिरफ्त में है। कहे गए शब्द वापस लिए जा सकते हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि इस तरह से सामने वाले को भी बेहतर लगने लगेगा।

> **अगर माफी मांगना जरूरी है तो वक्त की जरूरत के मुताबिक माफी मांग भी लेनी चाहिए। खुले दिल से माफी मांग ली जाए तो संबंधों का पुल सलामत रहता है। जमाने से सुनते आए हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन जबान से निकले शब्दों से बना जख्म कभी नहीं भरता। हालांकि वक्त के साथ यह बात अपनी प्रवृत्ति बदल रही है।**

जिंदगी जीने के अंदाज सिखाने वाले कम नहीं हैं। राजनीति भी अब जिंदगी की प्रशिक्षक हो गई है। यह सिखाती है कि बात कैसे करते हैं। अवसर और परिस्थिति के अनुसार कौन-से स्वादिष्ट या बेस्वाद शब्द दूसरों को परोसने चाहिए। यह अभिनेताओं को अभिनय सिखा रही है। उन्हें समझाती है कि राजनीति में सिर्फ अभिनय नहीं करते, बल्कि बहुत समझदारी भरी कुटिलता से अभिनय करते हैं। काबिल अभिनेता भी अगर वांछित अभिनय न कर पाए, तो छोटा-सा संवाद वापस लेने के लिए मोड़ ढूंढ़ना पड़ता है। इससे मानसिक रूप से परेशानी होती है, भूख उड़ जाती है और आत्मा तड़पती है, फिर भी स्थिति ठीक होने का अभिनय लगातार करते रहना होता है। सही मोड़ काटना सीखते रहना होता है।

दिग्गज व्यक्ति अनुभव के वस्त्र बदल-बदल कर, अभिनय करते-करते निर्देशक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी नए मोड़ चुनने पड़ते हैं। शतरंज की बिसात पर नए मोहरे चलाना सीखना पड़ता है। कई मोड़ ऐसे भी आते हैं, जहां सार्वजनिक खेद प्रकट करना होता है। देखा जाए तो अपनी गलती पर अगर सचमुच अफसोस नहीं है, तो खेद प्रकट करना भी कई बार सही अवसर पर किया गया कुशल अभिनय होता है। जिंदगी में हर तरह का किरदार निभाना होता है जो उसी तरह के अभिनय की मांग करता है। यहां करतब भी जरूरी होते हैं। स्थिति के अनुसार एक दूसरे को स्थिर या अस्थिर करने के लिए विश्वसनीय करतब करवाए जाते हैं और कई बार तो असली मारधाड़ भी जरूरी हो जाती है, जो करनी ही पड़ती है। यह जिंदगी का खतरनाक मोड़ होता है, जिस पर आमतौर पर सभी ठहरना नहीं चाहते। ऐसी जगह रुकना एक तरह की मजबूरी होती है। पीड़ित व्यक्ति अगर शांत रहे तो बेहतर, नहीं तो फिर अनुभवी मोड़ चुनना होता है।

यह मोड़ होता है 'माफी मोड़', जहां अपनी गलती का अहसास करते हुए या फिर स्थिति को सामान्य करने के मकसद से माफी मांग ली जाती है। यह तारीफ के काबिल मोड़ होता है। सभी समझदार लोग इसकी तारीफ ही करते हैं। देखा जाए तो इससे दोनों काम हो जाते हैं। गुस्सा भी जाहिर कर दिया और माफी मांगकर स्थिति भी नियंत्रण में कर ली। माफी मांगते हुए अगर यह कह दिया जाए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या मेरे कहने का वह मतलब नहीं था तो भी तारीफ मिल सकती है।

निजी जिंदगी में आराम से काटे गए मोड़ काफी राहत पहुंचाते हैं। अगर पत्नी और पति एक दूसरे को ऐसा कहते रहें तो अच्छा संवेदनशील व्यवहार माना जाता है, जिसमें रास्ते पर आगे जाकर मुड़कर लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। विकास के कारण बढ़ती आजादी ने हर एक को कुछ भी बोलने, देखने और करने का अधिकार दे दिया है, लेकिन आजादी के इस मोड़ पर कर्तव्य भुलाए जा रहे हैं। ड्राइविंग चाहे राजनीतिक, धार्मिक या पारिवारिक हो, ऐसी होनी चाहिए कि नियंत्रण बरकरार रहे। स्थितियों की आवाजाही उचित गति से चलती रहे। जहां मुड़ना है, उस जगह की भूला न जाए, ताकि आगे जाकर वापस आना न पड़े।

इतिहास की भूमिका

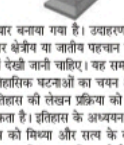

इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि यह समाज के मूल्यों तथा विचारधारा का जीवंत दस्तावेज है। जब इस दस्तावेज को तोड़ा-मरोड़ा जाता है, तो न केवल अतीत के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की दिशा को भी विकृत करता है। हमारे देश में ऐतिहासिक तथ्यों को प्रायः राजनीतिक उद्देश्यों, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और वैचारिक प्रचार के लिए हथियार बनाया गया है। उदाहरण के लिए, स्थानीय नायकों और स्वतंत्रता संग्राम के योगदान को कई बार क्षेत्रीय या जातीय पहचान तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि उनकी भूमिका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए। यह समस्या विशेष रूप से शिक्षा प्रणाली में स्पष्ट होती है, जहां पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक घटनाओं का चयन और प्रस्तुति प्रायः पक्षपातपूर्ण होती है। इस स्थिति से निपटने के लिए इतिहास की लेखन प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष, वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित बनाने की आवश्यकता है। इतिहास के अध्ययन को तर्कसंगत दृष्टिकोण से जोड़ना अहम कदम हो सकता है। इतिहास को मिथ्या और सत्य के बीच संतुलित रखना न केवल शिक्षाविदों की जिम्मेदारी है, बल्कि यह हर नागरिक का दायित्व भी है।

– अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

चुनाव पर नजर

महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद अब दिल्ली विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर है। दिल्ली में चुनाव अगले साल फरवरी में संभावित है। दिल्ली के चुनावी परिणाम का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। इसलिए सभी प्रमुख दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम जनता में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गली-मोहल्ले में चर्चा शुरू हो चुकी है। सड़कें-गलियां और चौराहे संभावित उम्मीदवारों के पोस्टरों से भर चुके हैं। सभी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने तो अपने ग्यारह उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है, लेकिन मौजूदा समय में दिल्ली की राजनीति का जो हाल है, उसमें भाजपा को इस चुनाव में पर्याप्त अवसर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी यहां की विभिन्न समस्याओं को हल करने में असफल रही है।

– विजय किशोर तिवारी, दिल्ली

निरर्थक बहस

आज इलेक्ट्रानिक मीडिया का चेहरा बदल गया है। दिन-रात समाचार देने की उनमें क्षमता बची नहीं है, तो ज्यादातर समय वे निरर्थक राजनीतिक बहसों में बर्बाद कर देते हैं। लोग टीवी पर समाचार सुनने-देखने के लिए तरस जाते हैं। इतने बड़े देश में कहीं न कहीं कोई घटना घट रही होती है। मगर कोई खबर नहीं। टीवी चैनलों पर चर्चा के लिए गैर-राजनीतिक विश्लेषकों जैसे लेखकों और राजनीति में रुचि रखने वाले प्रबुद्ध नागरिकों को बुलाया जाना चाहिए। आर्थिक विषयों के लिए विषयज्ञ अर्थशास्त्रियों को बुलाना चाहिए, विशेषकर चुनाव परिणाम और बजट प्रस्ताव पर बातचीत के लिए या इनकी संभावित भविष्यवाणी के लिए। नेताओं को नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग प्रायः गलत व्याख्या करते हैं। झूठे आरोप लगाते हैं। भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, जिससे जनता को गलत जानकारी देने के साथ ही सामाजिक सद्भावना को आघात पहुंचने का डर रहता है।

– ललिता दुबे, रतलाम

लापता होते बच्चे

राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने वर्ष 2018 से 2022 तक गायब हुए बच्चों के आंकड़े जारी किए हैं। एनसीआरबी के अनुसार मध्यप्रदेश में रोजाना औसतन 30 बच्चे लापता हो रहे हैं। वर्ष 2018 से 2021 तक देश में यह राज्य पहले, तो 2022 में दूसरे स्थान पर था। मध्यप्रदेश बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक है। यहां लड़कों की तुलना में लड़कियों का अपहरण चार गुना ज्यादा हो रहा है। भीख मंगवाने और मानव अंग तस्करी के लिए भी अपहरण किए जा रहे हैं। अपहरण के लिए दो से चौदह साल तक के बच्चे उठाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें फुसलाना और धमकाना आसान होता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि पुलिस बच्चों के लापता होने पर गुमशुदगी नहीं, बल्कि अपहरण की धारा में मामला दर्ज करे। साथ ही एक दिशा-निर्देश में कहा गया है कि लापता बच्चों के बारे में तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित करे।

– हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com

तथ्य

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पारंपरिक शिक्षा से कौशल आधारित शिक्षा की ओर रुझान बढ़ रहा है। हाल ही में कोर्सेरा की 'माइक्रो-क्रेडेंशियल इंपैक्ट' रपट 2024 जारी की गई है। इसके अनुसार, विश्वविद्यालयों में डीन, प्रोवोस्ट, अध्यक्ष, प्रोफेसर और अन्य शिक्षकों सहित 95% विशेषज्ञों का मानना है कि माइक्रो-क्रेडेंशियल छात्रों के रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाते हैं। यह फीसद वैश्विक औसत 87% से अधिक है, जो दर्शाता है कि भारत कौशल-आधारित शिक्षा को अपनाकर कार्यबल की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

युवा शक्ति
जनसत्ता | 5 दिसंबर, 2024

शिक्षा का अधिकार: यूपी में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू

उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए एक दिसंबर से आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक और पात्र छात्रों के अभिभावक आरटीई पोर्टल के माध्यम से अंतिम तिथि तक या उससे पहले आवेदन फार्म भर सकते हैं। आरटीई के तहत यूपी के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त में पढ़ने वाले पात्र छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया चार चरणों में 27 मार्च, 2025 तक आयोजित की जाएगी। प्रदेश में आरटीई के तहत निजी स्कूलों के 6,03,000 सीटों पर गरीब परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।

मनोविज्ञान के क्षेत्र में हैं कई संभावनाएं

विशेषज्ञ की कलम से

मनोविज्ञान ऐसा क्षेत्र है, जिसमें करिअर की अपार संभावनाएं हैं। मनोविज्ञान में करिअर आपको अच्छी आय के साथ-साथ समाज में योगदान करने का अवसर भी देता है, खासकर यदि आप उच्च शिक्षा और विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इसमें विशेषज्ञता हासिल करके आप लोगों का मन और व्यवहार समझ सकते हैं। इसमें मानव मन और मस्तिष्क से जुड़ी कई चीजों का अध्ययन किया जाता है। मस्तिष्क तनाव में कैसे काम करता है, यह कोई भाषा कैसे सीखता है, तथ्यों को कैसे याद रखता है या किसी भी तरह की मानसिक बीमारी इसके काम करने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकती है जैसी चीजें इसमें प्रमुखता से शामिल हैं।

पाठ्यक्रम, फीस और अवधि

मनोविज्ञान में करिअर बनाने के लिए कई कोर्स उपलब्ध हैं। हर कोर्स की फीस और अवधि अलग-अलग होती है। यहां पर प्रमुख कोर्स और उनकी जानकारी दी गई है। बीए/बीएससी इन साइकोकाजी का पाठ्यक्रम तीन वर्षों का होता है, जिसकी फीस सरकारी कालेजों में 5,000 से 20,000 रुपए प्रति वर्ष और निजी कालेजों में 30,000 से 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष होती है। एमए/एमएससी इन साइकोलाजी दो वर्ष का कोर्स है, जिसमें सरकारी कालेजों की फीस 10,000 से 30,000 रुपए प्रति वर्ष और निजी कालेजों की फीस 50,000 से 2,00,000 रुपए प्रति वर्ष तक होती है। डिप्लोमा इन काउंसलिंग छह महीने से एक वर्ष का कार्यक्रम है, जिसकी फीस 10,000 से 50,000 रुपए तक होती है। पीएचडी इन साइकोलाजी की अवधि 3 से 5 वर्ष है, जिसमें सरकारी संस्थानों की फीस 20,000 से 50,000 रुपए प्रति वर्ष और निजी संस्थानों की फीस 1,00,000 से 3,00,000 रुपए प्रति वर्ष होती है। एमएसडब्ल्यू (मेडिकल और साइकेट्रिक सोशल वर्क) की अवधि दो वर्ष है, और इसकी फीस 10,000 से 40,000 रुपए प्रति वर्ष (सरकारी कालेज) और 50,000 से 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष (निजी कालेज) तक हो सकती है। अंत में, बीएड (विशेष शिक्षा) का पाठ्यक्रम दो वर्ष का है, जिसकी सरकारी कालेजों की फीस 20,000 से 50,000 रुपए प्रति वर्ष और निजी कालेजों की फीस 1,00,000 से 2,50,000 रुपए प्रति वर्ष होती है।

वेतन

मनोविज्ञान के क्षेत्र में वेतन आपकी विशेषज्ञता, अनुभव और जिस संस्थान में आप काम करते हैं, उस पर निर्भर करता है। स्कूल काउंसलर का वेतन 15,000 से 35,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है। वहीं, कालेज प्रोफेसर का 50,000 से 2,00,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है। कार्डसलिंग साइकोलाजिस्ट का वेतन 20,000 से 50,000 रुपए प्रति माह होता है। प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक का वेतन 30,000 से 1,50,000 रुपए प्रति माह तक हो सकता है।

- पूजा आहूजा ममतानी, पुनर्वास मनोविज्ञानी

इन क्षेत्रों में बनेगा भविष्य

- **परामर्शदाता** : परामर्शदाता बनने के लिए मनोविज्ञान में स्नातक के बाद परामर्श मनोविज्ञान में परास्नातक करना आवश्यक है। **परामर्शदाता** स्कूलों, अस्पतालों, एनजीओ और निजी क्लीनिक में काम कर सकते हैं।
- **आरसीआइ लाइसेंस प्राप्त पेशेवर** : रिहैबिलिटेशन काउंसिल आफ इंडिया (आरसीआइ) की मान्यता प्राप्त कोर्स जैसे कि एमफिल विलनिकल साइकोलाजी या पुनर्वास मनोविज्ञान पूरा करने के बाद आरसीआइ से लाइसेंस प्राप्त होता है। यह लाइसेंस विलनिकल या पुनर्वास मनोवैज्ञानिक के रूप में काम करने के लिए अनिवार्य है।
- **चिकित्सीय मनोवैज्ञानिक** : चिकित्सीय मनोवैज्ञानिक बनने के लिए एमफिल या डाक्टरेट की डिग्री आवश्यक है। ये प्रोफेशनलस मानसिक विकारों जैसे अवसार, एंग्जायटी, और सिजोफ्रेनिया का उपचार करते हैं।
- **पुनर्वास मनोवैज्ञानिक** : यह पेशेवर शारीरिक और मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के पुनर्वास में मदद करते हैं। इसके लिए एमफिल/पुनर्वास मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की आवश्यकता होती है।
- **विशेष शिक्षक** : विशेष शिक्षा में डिप्लोमा या बीएड (विशेष शिक्षा) करके आप विशेष शिक्षक बन सकते हैं, जो बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण में सहायक होते हैं।

सूचनापट्ट

निफ्ट 2025

राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नोलाजी (निफ्ट) में प्रवेश के लिए स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी प्रवेश परीक्षाओं के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो उम्मीदवार देश के विभिन्न हिस्सों में निफ्ट परिसरों द्वारा पेश किए जाने वाले उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की योजना बना रहे हैं, वे परीक्षा के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। बिना विलंब शुल्क दिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी, 2025 है, और आवेदन सुधार विंडो 10 जनवरी से 12 जनवरी, 2025 तक उपलब्ध रहेगी, जिससे उम्मीदवार अपने जमा किए गए फार्म में आवश्यक संपादन कर सकेंगे। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए यूजी, पीजी और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए निफ्ट प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का कार्य राष्ट्रीय परीक्षण एजंसी (एनटीए) को सौंपा है।

अंतिम तिथि : 6 जनवरी, 2025

एनटीटी, सीटी (नर्सरी) व डीपीएड

परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की ओर से सीटी नर्सरी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एवं डीपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। सीटी नर्सरी और एनटीटी में प्रवेश केवल महिला अभ्यर्थी ले सकती हैं। इसके लिए उन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से 50 फीसद अंकों के साथ स्नातक डिग्री प्राप्त की हो। आरक्षित श्रेणी के लिए अंकों में पांच फीसद की छूट दी गई है। डीपीएड पाठ्यक्रम में पुरुष एवं महिला दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग का स्नातक 50 फीसद अंकों के साथ और आरक्षित वर्ग का स्नातक 45 फीसद अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 साल से कम और अधिकतम आयु 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

अंतिम तिथि : 26 दिसंबर, 2024

वायु सेना (एएफसीएटी)

भारतीय वायु सेना ने एअर फोर्स कामन एडमिशन टेस्ट (एएफसीएटी 01/2025) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। वायु सेना ने पात्र उम्मीदवारों से आनलाइन आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण विंडो 31 दिसंबर रात 11:30 बजे तक खुली है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 20 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए आयु वर्ग 20 वर्ष से 26 वर्ष है। आनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद, एएफसीएटी प्रवेश के लिए 550 रुपए के साथ जीएसटी (गैर-वापसी योग्य) का परीक्षा शुल्क (एनसीसी विशेष प्रवेश के लिए लागू नहीं) आनलाइन भुगतान करना होगा। कुल 336 रिक्तियों की अधिसूचना जारी की गई है। परीक्षा 22 और 23 फरवरी, 2025 को दो पालियों में आनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। आवेदक 7 फरवरी, 2025 (शाम 5 बजे) से हाल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

अंतिम तिथि : 31 दिसंबर, 2024

इग्नू

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड (ओडीएल) और आनलाइन मोड के माध्यम से पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए जनवरी 2025 सत्र में दाखिले के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल जनवरी सत्र में दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 रखी गई है। इग्नू में साल में दो बार दाखिले होते हैं। इग्नू में 200 से ज्यादा स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स चलते हैं। इग्नू में आवेदन के समय उम्मीदवार की फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन कापी 100 केबी से बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अन्य दस्तावेजों का साइज 200 केबी से बड़ा नहीं होना चाहिए।

अंतिम तिथि : 31 जनवरी 2025

जानें-सीखें

कैट स्कोर और पर्सेंटाइल में क्या है फर्क, ऐसे करें गणना

देश के प्रमुख मैनेजमेंट कालेजों में प्रवेश लेने के लिए कैट परीक्षा पास करना जरूरी है। कैट परीक्षाफल में दो चीजें देखी जाती हैं ड्ड कैट स्कोर और कैट पर्सेंटाइल। कई उम्मीदवार अक्सर कैट स्कोर को कैट पर्सेंटाइल के साथ भ्रमित करते हैं, जो दोनों ही परीक्षा परिणामों के महत्त्वपूर्ण घटक हैं। अगर आपने भी इस साल कामन एडमिशन टेस्ट दिया था तो आपको कैट स्कोर और कैट पर्सेंटाइल के बीच फर्क पता होना चाहिए। साथ ही हर किसी को कैट पर्सेंटाइल निकालना भी आना चाहिए। कैट 2024 परीक्षा 24 नवंबर को हुई थी और इसमें 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस साल की उत्तर कुंजी जारी की जा चुकी है। जल्द ही कैट 2024 के नतीजे भी जारी कर दिए जाएगा।

अगर आपका कैट स्कोर 250 है और पर्सेंटाइल 95 है तो इसका मतलब है कि आपने कैट परीक्षा में 250 अंक हासिल किए हैं और परीक्षाफल 95% परीक्षार्थियों से बेहतर है।

कैट स्कोर क्या होता है

कैट स्कोर परीक्षा में हासिल कुल अंकों को दर्शाता है। यह स्कोर 0 से 300 के बीच होता है। कैट परीक्षा के के तीनों खंडों ड्ड मौखिक योग्यता और पढ़ने की समझ (वीए-आरसी), डेटा इंटरप्रिटेशन और तार्किक तर्क (डीआइ-एलआर) और क्वांटेटेटिव एबिलिटी (क्यूए) में हासिल अंकों को जोड़कर कैट स्कोर का कुल निकाला जाता है।

कैट पर्सेंटाइल क्या होता है

पर्सेंटाइल परीक्षा में आपके प्रदर्शन को अन्य परीक्षार्थियों के साथ तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैट पर्सेंटाइल 0 से 100 के बीच होता है, इसमें 100वां पर्सेंटाइल उच्च स्कोर दर्शाता है। पर्सेंटाइल से आप जांच कर सकते हैं कि अन्य परीक्षार्थियों की तुलना में आपने कैसा प्रदर्शन किया है।

इस तरह निकालें पर्सेंटाइल

- कैट पर्सेंटाइल (पी) = (आर/एन)×100
  पी= पर्सेंटाइल स्कोर
  आर= मतलब उम्मीदवार की रैंक, उम्मीदवार को स्केल किए गए कैट स्कोर या आपसे नीचे रैंक वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या के आधार पर रैंक दी जाएगी
  एन= कैट परीक्षा (तीनों सत्र) में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या।

युवा शक्ति डेस्क

हौसला

अगरतल्ला में अपने पैर से पैरालिंपिक कांस्य पदक विजेता शीतल देवी का चित्र बनाता दिव्यांग चित्रकार।

युवाओं को अलग-अलग रखना चाहिए निजी और पेशेवर जीवन

परामर्श

अपनी नौकरी से प्यार करना बेशक करिअर का सबसे बड़ा लक्ष्य लगे, लेकिन इसे ही जिंदगी बना लेना उचित नहीं है। नौकरी से इतर भी जीवन के कई रंग-रूप होते हैं। ऐसे में आप चौबीस घंटों में से ज्यादातर समय पेशेवर काम को ही देंगे, तो बाकी चीजों से कैसे जुड़ पाएंगे? यह समस्या युवा पेशेवरों में आम हो गई है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के लिए आपका नजरिया अलग-अलग हो। इस तरह से न सिर्फ आपका करिअर बेहतर होगा, बल्कि आपकी जिंदगी में हर दिन कुछ नया करने का रोमांच और संतुलन भी बना रहेगा।अगर आपको लगता है कि काम के प्रति आपका मिजाज जुनूनी तरह का है और उस पर आपका नियंत्रण नहीं है या आप अपनी सफलताओं का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको अपने करिअर में बदलाव करने पर विचार करना चाहिए। आपको ऐसी भूमिका की तलाश करनी चाहिए, जिसमें कलात्मक या सामाजिक तत्व अधिक हों। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि काम के प्रति जुनून दो तरह का होता है: सामंजस्यपूर्ण और जुनूनी। सामंजस्यपूर्ण जुनून तब होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी से प्यार करते हुए भी जीवन के अन्य पहलुओं के साथ बेहतर तालमेल और संतुलन बनाए रखता है। ऐसे लोगों का उनके काम पर नियंत्रण होता है। दूसरी ओर, जुनूनी व्यक्तियों का काम उनके जीवन पर हावी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अक्सर पदोन्नति या वेतन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए ऐसी नौकरी का लक्ष्य रखें, जिससे जीवन में संतुलन बना रहे।

यूजीसी : स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में होंगे बड़े बदलाव

स्नातकोत्तर छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रमों के लिए नया 'करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क' जारी कर दिया है। पाठ्यक्रम से जुड़े कई बदलाव की सिफारिश की गई है। जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा परिदृश्य को आधुनिक बनाना है। इससे छात्रों को सीखने के आधुनिक और विविधतापूर्ण मौके मिल सकेंगे।

स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए भी एकाधिक संरचनाओं का प्रस्ताव रखा गया है। नए फ्रेमवर्क के तहत जो छात्र तीन वर्षीय स्नातक एडीपी के तहत कम समय में पूरा करते हैं, वे भी दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। वहीं चार वर्षीय स्नातक आनर्स करने वाले छात्र एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम में दाखिला ले सकते हैं। पांच वर्षीय इंटिग्रेटेड प्रोग्राम का विकल्प भी छात्रों को दिया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट सिस्टम, एंट्री एग्जिट विकल्प समेत अन्य कई बदलाव भी कार्यक्रम में हो सकते हैं।

जरूरी जानकारी

आनलाइन कार्यक्रम पर केंद्रित होगा

नया फ्रेमवर्क आनलाइन कार्यक्रम को बढ़ावा देता है। छात्रों को एक साथ कई डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश लेने का विकल्प मिलेगा। नया बदलाव क्रास-डिसिप्लिनरी लर्निंग (अंतर-विषयक शिक्षा) को प्रोत्साहित करता है।

क्रेडिट और पात्रता

एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा (एनएचईक्यूएफ) के लेवल 6.5 पर न्यूनतम 160 क्रेडिट के साथ आनर्स के साथ स्नातक की डिग्री या शोध के साथ आनर्स की जरूरत पड़ेगी। दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए कम से कम 120 क्रेडिट के साथ तीन वर्षीय स्नातक डिग्री या एनएचईक्यूएफ के स्तर 7 पर न्यूनतम 160 क्रेडिट के साथ चार वर्षीय स्नातक डिग्री होनी चाहिए।

अन्य बड़े बदलाव

स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में मशीन लर्निंग जैसे मुख्य क्षेत्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) जैसे प्रोफेशनल डोमेंस और सम्मिलित क्षेत्र शामिल होंगे, जिसमें स्वास्थ्य सेवा और कानून जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। एनईपी के अनुरूप पाठ्यक्रम होगा।

जेईई एडवांस 2025 परीक्षा दो पालियों में 18 मई को होगी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा की तारीख का एलान कर दिया गया है। यह परीक्षा अगले साल 18 मई दिन रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। परीक्षा की अवधि तीन घंटे की होगी। जेईई एडवांस परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाती है। एक उम्मीदवार लगातार दो वर्षों में अधिकतम दो बार ही यह परीक्षा दे सकता है।जेईई एडवांस पात्रता मानदंड के अनुसार, जेईई मेन 2025 परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और बीई, बीटेक पेपर में शीर्ष 2,50,000 में शामिल अभ्यर्थी ही, जेईई एडवांस 2025 परीक्षा में भाग लेने के लिए और आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। हाल ही में, संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) ने पिछले जेईई एडवांस्ड 2025 पात्रता मानदंड को बहाल कर दिया और प्रयासों की संख्या घटाकर दो कर दी है। बोर्ड ने पहले प्रयासों की संख्या बढ़ाकर तीन कर दी थी। हालांकि, प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर विचार करने के बाद जेईई एडवांस्ड के तीसरे प्रयास को हटा दिया गया था।

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार, 5 दिसंबर 2024

गुड गवर्नेंस की चुनौती

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के 11 दिन बाद यह तय हो पाया कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि इन चुनावों में महायुति और उसमें भी BJP को जैसा जनादेश मिला था, उसके बाद इस सवाल पर इतनी माथापच्ची होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन पिछले नवंबर में प्रदेश की राजनीति में जिस तरह के मोड़ आए हैं, उन्हें देखते हुए आखिरी पलों तक कुछ भी हो जाने का सस्पेंस बना रहा।

सहज स्वाभाविक चयन | खुद देवेंद्र फडणवीस के हालिया करियर को देखें तो 2014 से 2019 तक बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 2022 में उन्होंने एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री की भूमिका मंजूर की। किसी भी महत्वाकांक्षी राजनेता के लिए यह स्वभाविक चाँइस नहीं कही जाएगी, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में पार्टी के आग्रह पर उन्होंने न केवल सरकार का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया बल्कि चुनाव में पार्टी की अगुआई करते हुए उसे शानदार जीत भी दिलाई।

महाराष्ट्र को सरकार से उम्मीदें

निरंतर सतर्कता | फिर भी अगर यह सवाल बना हुआ है कि महायुति सरकार की नई पारी पिछली पारी जैसी सहजता और स्थिरता दिखा पाएगी या नहीं तो उसके पीछे प्रदेश राजनीति के हालिया उतार-चढ़ाव ही हैं। दो पुरानी और सुगठित राजनीतिक पार्टियों में हुई असाधारण तोड़फोड़ के परिणामस्वरूप बनी महायुति ने हालांकि 2024 विधानसभा चुनावों में अपनी सार्थकता सिद्ध कर दी है और इसलिए अब इसे किसी भी रूप में कृत्रिम गठबंधन नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। जाहिर है, नए मुख्यमंत्री और BJP नेतृत्व को सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने और किसी भी असंतोष से बचने पर खास ध्यान देना होगा।

दोहरी चुनौती | प्रदेश राजनीति की यह खास स्थिति जहां सहयोगी दलों की आकांक्षाओं का ध्यान रखने और उन्हें यथासंभव संतुष्ट रखने की जरूरत को रेखांकित करती है वहीं आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति से जुड़े दलों पर बेहतर प्रदर्शन की जिम्मेदारी भी बढ़ा देती है। हालांकि पहली चुनौती मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को संतोषजनक ढंग से निपटाने की है।

कसौटी पर कुशलता | साफ है कि विशाल बहुमत वाली इस सरकार के मुखिया के तौर पर देवेंद्र फडणवीस की यह पारी किसी भी रूप में कम चुनौतीपूर्ण नहीं साबित होने वाली। देखना होगा कि महाराष्ट्र को राजनीतिक स्थिरता और विकास के नए दौर में ले जाने की जिम्मेदारी वह किस हद तक पूरी कर पाते हैं। साथ ही, लोगों ने उनकी पार्टी और सहयोगी दलों पर जो भरोसा जताया है, महायुति सरकार उनकी उम्मीदें पूरी कर पाती है?

साड्डी दिल्ली

बाबा साहेब का घर

विवेक शुक्ला

इंडिया गेट से पृथ्वीराज रोड की तरफ बढ़ने पर दाईं तरफ 22 नंबर का बंगला दिखाई देता है। इसका भारत के संविधान और संविधानसभा के अध्यक्ष डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर से करीब का नाता रहा है। कल यानी 6 दिसंबर को बाबा साहेब की पुण्यतिथि है। 29 अगस्त 1947 को जब बाबा साहेब को संविधान तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई, तब वह 22, पृथ्वीराज रोड में ही रह रहे थे। इससे पहले देश को आजादी तो मिली थी, मगर वह बंट भी गया था। दिल्ली के कई भागों में दंगे भड़के हुए थे। उस मुश्किल दौर में संविधानसभा की बैठकें पुराने संसद भवन में होती थीं। संविधान तैयार करने के लिए बाबा साहेब अपने पृथ्वीराज रोड के स्टडी रूम में ही दिन-रात शोध और अध्ययन करते थे।

बाबा साहेब 20 अप्रैल,1942 को पहली बार दिल्ली आए थे। उन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई विभाग का पदभार संभालने के लिए बुलाया गया था। उस समय मौजूदा मावलंकर हॉल के पीछे छोटी-छोटी कुटिया बनी हुई थीं। बाबा साहेब दिल्ली में पहली रात 35 नंबर की कुटिया में रहे। उस रात मच्छरों की वजह से उन्हें नींद नहीं आई। उसके बाद उन्हें जनपथ स्थित वेस्टर्न कोर्ट के कमरा नं. 2 में शिफ्ट कर दिया गया। कुछ दिनों बाद बाबा साहेब ने लोदी एस्टेट में कुछ सरकारी बंगले देखे। उन्हें लोदी एस्टेट पसंद नहीं आया। आखिरकार उन्हें 22, पृथ्वीराज रोड का बंगला दिखाया गया। यह उन्हें सही लगा। बाबा साहेब के जीवन पर शोध कर रहे सुभनजी संघमित्र कहते हैं, उस समय पृथ्वीराज रोड का बंगला खंडहर की सूरत में था। एकदम उजाड़। अंदर मकड़ी के बड़े-बड़े जाले थे, दरवाजों की लकड़ियां टूटी पड़ी थीं, प्लास्टर उखड़ा पड़ा था। उसे भूत-बंगला कहते थे। लेकिन वैज्ञानिक मानसिकता रखने वाले बाबा साहेब ने इसमें रहना पसंद किया। उस बंगले में उनकी हजारों किताबें भी सधा गईं।

उनके साथ उस समय पत्नी डॉ. सविता के अलावा सहयोगी नानक चंद रत्तू और खाना पकाने वाले साथी सुदामा भी रहते थे। दिन के वक्त बाबा साहेब की किताबों और लाइब्रेरी की देखभाल करने वाले देवी दयाल भी होते। देवी दयाल किताबों को झाड़ने-पोंछने से लेकर अखबारों की कतरनों को तारीख के क्रम में रजिस्टर में चिपकाने का काम उनकी मृत्यु तक बखूबी करते रहे। बाबा साहेब रोज 17-18 घंटे काम करते थे। बाबा साहेब ने इसी घर में 15 अप्रैल 1948 को डॉ. सविता से सादगी के साथ विवाह किया था। डॉ. सविता डॉक्टर थीं। वह महाराष्ट्र के चित्तपावन ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उनका मुंबई में क्लीनिक था, जहां इलाज के दौरान बाबा साहेब से उनका परिचय हुआ था। अब 22 पृथ्वीराज रोड में तुर्की के राजदूत रहते हैं।

एकदा

एकनाथ की परीक्षा

16वीं सदी में महाराष्ट्र में एक महान संत एकनाथ हुए। उनकी जीवनशैली और उपदेशों ने लोगों का जीवन बदल दिया। एक बार की घटना है। कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। जब उनमें लड़ाई होने लगी तो किसी ने ऐसा करने से मना किया। इस पर एक ने गुस्से में कहा, 'मैं क्या संत एकनाथ हूं, जो इसकी बातों को सहता जाऊं?' अब बात एकनाथ की तरफ मुड़ गई। उन्होंने संत एकनाथ को गुस्सा दिलाने की चुनौती दी और कहा, 'जो एकनाथ को गुस्सा दिला पाएगा, उसे सारा पैसा मिल जाएगा।' एकनाथ का घर गोदावरी नदी के पास ही था। अगली सुबह एक जुआरी रास्ते में पड़ने वाले एक पेड़ पर चढ़ गया। जब संत एकनाथ स्नान करने नदी की ओर जा रहे थे, तब उसने पान की पीक उन पर थूक दी। लेकिन एकनाथ ने अनदेखा कर स्नान करने चले गए। जब वह वापस लौट रहे थे, तो जुआरी ने फिर उनके सिर पर पान थूक दिया। फिर भी एकनाथ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह सिलसिला कई बार चला। अंत में जुआरी नीचे उतर गया और इंतजार करने लगा। जैसे ही एकनाथ लौटे, जुआरी ने पूछा, 'आपमें इतनी सहनशीलता कैसे है? तब से देख रहा हूं कि मैं पान की पीक थूके जा रहा हूं और आपने जरा भी गुस्सा नहीं किया।' तब एकनाथ ने कहा, 'मैं स्नान करने आता हूं ताकि शरीर और मन को शुद्ध कर सकूं। तुमने केवल मेरे शरीर को गंदा किया, लेकिन अगर मैं गुस्से में आता तो मेरा मन भी गंदा हो जाता।' यह सुनकर जुआरी बहुत प्रभावित हुआ और एकनाथ के चरणों में गिरकर कहा, 'आपकी इस शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया है।'

Subrata Chai

संकलन : विजय पाटिल

US के नव निर्वाचित राष्ट्रपति एक दिन में युद्ध ख़त्म कराने की बात कह रहे, पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं

यूक्रेन में बाइडन ने ट्रंप को फंसा दिया

रशीस सिंह

सोवियत संघ के पतन के एक साल बाद ही 'द एंड ऑफ हिस्ट्री' की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन यह पश्चिमी दुनिया का खेल था, क्योंकि उस इतिहास का अंत कभी हुआ ही नहीं। हां, दुनिया जरूर एकध्रुवीय हो गई, जिसमें अमेरिका और पश्चिम को सोवियत संघ से मिलने वाली चुनौती खत्म हो चुकी थी। हालांकि ऐसा भी नहीं रहा कि वे चुनौतीविहीन हो गए। पश्चिमी दुनिया, विशेषकर यूरोप 'सभ्यता के संघर्ष' के दौर से गुजर रहा है, भले ही इसे सैद्धांतिक स्तर पर स्वीकार न किया जाए। मध्य-पूर्व खतरनाक मोड़ पर है और यूरेशिया युद्ध का मैदान बना हुआ है। इन सभी क्षेत्रों में अमेरिका का बहुत कुछ दांव पर है, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि वॉशिंगटन और उसके सहयोगी बिना किसी चुनौती के आगे बढ़ रहे हैं?

नए खतरे | रूस-यूक्रेन युद्ध 'रेड लाइन' पार करता दिख रहा है। इसके चलते दुनिया 'न्यू वॉर जोन' में पहुंचती लग रही है। यह वक्त शीत युद्ध के बाद सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में सवाल है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के करीब पहुंच रही है?

अमेरिकी खेल | हाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस नई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेगा। उनका कहना है कि मॉस्को अपने नए हथियारों का प्रयोग जारी रखेगा। डॉनल्ड ट्रंप एक दिन में यह युद्ध खत्म कराने की बात कह रहे थे, लेकिन उनके शपथ लेने से पहले जो स्थितियां बन रही हैं, वह उनका साथ देती नहीं लगतीं। यह 'वॉर गेम' अमेरिका की ही देन है। बाइडन प्रशासन ने ही यूक्रेन को अनुमति दी है कि वह अमेरिकी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से रूस पर डीप स्ट्राइक कर सकता है।

चुनाव का असर | अमेरिका और यूक्रेन की तरफ से तर्क दिया गया कि अमेरिकी नीति में यह बदलाव कुरस्क सीमा क्षेत्र में रूस की मदद के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों की तैनाती के कारण आया है। ध्यान रहे कि कुरस्क रूस की सीमा में है, जहां यूक्रेन ने अगस्त से ही करीब 1000 वर्ग किमी क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। लेकिन, असल वजह यह नहीं मालूम पड़ती। असली कारण अमेरिका में डेमोक्रेट्स की हार और रिपब्लिकन पार्टी की जीत में छुपा है। शायद जो बाइडन अगले साल 20 जनवरी को ट्रंप को कांटों का ताज सौंपना चाहते हैं। इससे ट्रंप की 'पीस स्टैटेजी' प्रभावित होगी, जो अमेरिकी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इससे ट्रंप की लोकप्रियता गिरेगी और वह चुनौतियों से घिरने लगेंगे।

AI Image

वैश्विक टकराव | अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के इस निर्णय की प्रतिक्रिया में रूस ने 'रिवाइज्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन' पेश कर दिया, जिससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। पूतिन का कहना है कि यह युद्ध अब क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा, बल्कि वैश्विक टकराव में बदल चुका है। हालांकि रूस-यूक्रेन युद्ध सही अर्थों में पहले भी क्षेत्रीय विवाद के रूप में नहीं दिख रहा था। रूस के खिलाफ यूक्रेन नहीं, अमेरिका और उसके सहयोगी हैं।

संकट के बादल
- बाइडन के फैसले ने स्थिति उलझाई
- पूतिन पहले से ज्यादा आक्रामक हुए
- न्यू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चिंता बढ़ाने वाला

नया डॉक्ट्रिन | पूतिन के 'न्यू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन' के कई आयाम हैं, जो खतरनाक हैं। एक तो यही कि कोई ऐसा देश जिसके पास स्वयं परमाणु हथियार न हों, लेकिन वह किसी परमाणु हथियार संपन्न देश के साथ मिलकर हमला करता है तो रूस इसे अपने ऊपर संयुक्त हमला मानेगा। अगर रूस को पता चला कि दूसरी तरफ से उस पर मिसाइल, ड्रोन या हवाई हमले हो रहे हैं तो वह अपने परमाणु हथियारों से जवाब दे सकता है। इसके अलावा इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कहा गया है कि अगर किसी देश ने नया सैन्य गठबंधन बनाया, पुराने को विस्तार दिया, रूस की सीमा के करीब सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया, उसे प्रयोग में लाया, तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है।

पुरानी धमकी | रूस पहले भी 'न्यूक रिस्ट्रॉन्ग' की धमकी दे चुका है। बीते मार्च महीने में रूस में चुनाव के पहले भी पूतिन ने कहा था, 'रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है।' ऐसे में बाइडन के कदम के पीछे मकसद जो भी हो, लेकिन दुनिया को भली-भांति समझ लेना चाहिए कि यदि रूस ने न्यूक्लियर हमला करने का विचार किया तो परिणाम भयावह होंगे। न्यूक्लियर बम के एक्सप्लोजन के साथ ही ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी रिएक्शन होता है, जिसे 'म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन' (मैड) कहा जाता है। साधारण शब्दों में क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया।

शांति की जरूरत | दुनिया शांति के शिखर पर नहीं, बल्कि बारूद के ढेर पर बैठी है। शांति के रास्ते बहुत संकरे हैं। अब देखना यह है कि नव-निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप 20 जनवरी के बाद कोई करिश्मा कर पाएंगे या वह 'अमेरिका फर्स्ट' के आदर्शों में ही खोए रहेंगे?

(लेखक विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं)

महिला कमांड पर अफ़सरों की यह कैसी सोच

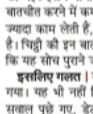
नवदीप सिंह

पिछले दिनों आर्मी से लीक हुई एक चिट्ठी को लेकर खूब बवाल मचा। महिला अफसरों को लेकर यह चिट्ठी आर्मी के किसी बड़े अफसर ने खुद से बड़े अफसर को लिखी थी। उन्होंने लिखा कि उनके अधीन आठ महिला कमांडिंग ऑफिसर हैं, जिनकी परफॉर्मेंस पर एक 'इन-हाउस' स्टडी की गई। इसमें पाया गया कि ये महिला अफसर दूसरों से बातचीत करने में कमजोर हैं, शिकायती हैं, अपनी कमान से ज्यादा काम लेती हैं, घमंडी हैं, और उनमें हमदर्दी भी नहीं है। चिट्ठी की इन बातों को सुनकर किसी को लग सकता है कि यह सोच पुराने जमाने की है।

इसलिए गलत | स्टडी कैसे हुई, इस बारे में बताया नहीं गया। यह भी नहीं कि कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या सवाल पूछे गए, डेटा क्या सामने आया, कितने लोगों से इस बारे में पूछा गया और क्या मनोवैज्ञानिकों से भी राय ली गई? भले ही इसका मकसद सेना को बेहतर बनाना रहा हो, लेकिन यह खत कई मायनों में गलत है:

- इस तरह की स्टडी सेना की प्रफेशनल टीमों, जैसे आर्मी ट्रेनिंग कमांड, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और डिफेंस इंस्टिट्यूट ऑफ साइकॉलजिकल रिसर्च द्वारा वैज्ञानिक तरीके से की जानी चाहिए थी।
- सभी महिला ऑफिसरों को एक जैसा बताना गलत है।
- अधिकारी क्या लिख रहे हैं, उन्हें इसे लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, भले वह गोपनीय पत्र ही क्यों न हो। यह कोई आम बातचीत नहीं है, बल्कि किसी के आधिकारिक काम से जुड़ा मामला है।

बात बराबर की

- महिलाओं को कमान संभाले हुए सिर्फ एक साल हुआ है, उन पर जल्दबाजी में फैसला सुनाना गलत है।

आधा-अधूरा ज्ञान | हैरानी की बात है कि यह सारा बवाल कुछ अफसरों की ओर से किया जा रहा है, निचले दर्जे के जवानों की ओर से नहीं! इस तरह की बातें करने से समाज के कुछ लोगों, खासकर सेना के कुछ मौजूदा और रिटायर्ड अफसरों को अपनी महिला साथियों पर पुराना गुस्सा निकालने का मौका मिलता है। सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आ रहे हैं, उनमें औरतों, अदालतों, सरकार और सेना के बड़े अफसरों के खिलाफ बेबुनियाद गुस्सा आधा-अधूरे ज्ञान से भरा हुआ है। जाहिर है, किसी भी नए बदलाव में शुरुआती दिक्कतें होती हैं। एक ऐसा वक्त आएगा जब किसी सैनिक को स्त्री-पुरुष के रूप में नहीं देखा जाएगा।

कोर्ट से कम्फर्ट | जो लोग कह रहे हैं कि अदालतों ने सीधे तौर पर औरतों को युद्ध में भेजने का फैसला किया है, वे बिल्कुल गलत हैं। दिल्ली हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन पदों पर औरतों को स्थायी कमिशन और कमान देने की बात कही थी, जहां वे पहले से ही काम कर रही थीं। अदालतों ने कॉम्बैट फोर्स में औरतों को शामिल करने के फैसले में दखल नहीं दिया। औरतें यह कानूनी लड़ाई जीत गईं क्योंकि अदालत ने कहा कि 14 साल तक अल्पकालिक अफसर के तौर पर काम करना मंजूर करना, लेकिन उसी पद पर 20 साल से ज्यादा समय तक स्थायी अफसर के तौर पर काम करने की इजाजत न देना गलत है। यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का पालन था। इसलिए महिलाओं को कमान मिली।

न्याय और समानता | यह बात कोई नहीं कह रहा है कि औरतों को खासतौर पर तरजीह दी जानी चाहिए। उन्हें पुरुषों की तरह ही काम करना होगा और उनका मूल्यांकन भी पुरुषों की तरह ही होगा। यह भी साफ है कि सेना कोई सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला नहीं है, लेकिन लैंगिक समानता एक सतत प्रक्रिया है। ज्यादा जरूरी है कि उनके साथियों और अफसरों को संवेदनशील बनाया जाए, पुराने विचारों को छोड़ दिया जाए। अच्छी बात यह है कि ये विचार सरकार और सैन्य नेतृत्व के नहीं हैं। उन्होंने तो हमेशा ही 'नारी शक्ति' के कामयाब होने की बात कही है।

(लेखक पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकील हैं)

1962 में चीन वापस क्यों लौटा

जंग में जब जीत मिल रही हो, तो कोई भी पीछे हटना नहीं चाहेगा। तब कोशिश होती सामने वाले पर ज्यादा से ज्यादा काबू पाने की। लेकिन, 1962 में चीन ने जो किया, उसने तमाम रणनीतिक जानकारों को आश्चर्य में डाल दिया। भारत के खिलाफ लड़ाई चीन ने ही शुरू की थी और LAC से वह 20 किलोमीटर तक भीतर घुस आया था। जब सारी बातें उसके पक्ष में दिख रही थीं, तब एक दिन अचानक उसने एकतरफा युद्धविराम की घोषणा कर दी। चीनी सैनिक जिस तरह भारतीय जमीन पर आए थे, उसी तरह वापस लौट गए। 20 अक्टूबर से शुरू हुआ युद्ध एक महीने चला और 21 नवंबर को संघर्षविराम हो गया। आखिर चीन पीछे क्यों हटा?

AI Image

हमले की वजह | इस सवाल का जवाब जानने के लिए उस समय के हालात पर गौर करना पड़ेगा। भारत-चीन के बीच सीमा विवाद औपनिवेशिक दौर का है। पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चिन और पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर चीन अपना दावा करता है। यह विवाद तब भी था। ऊपर से, पेइचिंग ने तिब्बत पर कब्जा करके मामले को और उलझा दिया था। इसकी वजह से चीन और भारत की सीमाएं मिल गई थीं, जबकि इससे पहले तिब्बत बफर जोन का काम करता था। इसने तनाव बढ़ा दिया।

नेहरू की नीति | भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में विवादित इलाकों में भारतीय दावे को मजबूत करने के लिए चेकपोस्ट बनाने का आदेश दिया। इसे नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार Neville Maxwell अपनी किताब 'India's China War' में लिखते हैं कि इस पॉलिसी को चीन ने उकसावे वाली कार्रवाई के रूप में देखा। हालांकि बस यही एक वजह नहीं थी। अमेरिकी सिक्योरिटी एनालिस्ट Bertil Lintner के मुताबिक, तिब्बत में अपनी स्थिति मजबूत करने और इलाके में दबदबा बनाने के लिए चीन ने 1959 से ही युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी।

युद्ध का समय | तब शीत युद्ध का दौर था। खास बात है कि 22 से 28 अक्टूबर 1962 के बीच ही क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, जिसने अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध का खतरा पैदा कर दिया। पूरी दुनिया की नजरें इस संकट की ओर थीं। ऐसे में चीन ने मौके का फायदा उठाया। उसे इस बात का डर नहीं रहा कि वॉशिंगटन या मॉस्को में से कोई दखल देने आएगा।

कूटनीतिक लक्ष्य | शीत युद्ध में भी भारत ने तटस्थ रहने की नीति अपनाई थी, हालांकि नई दिल्ली की सोवियत संघ के साथ करीबी थी। नेहरू चाहते थे कि भारत तीसरी दुनिया का नेतृत्व करे। चीन ने अचानक युद्ध छेड़कर भारत की कमजोरी सभी के सामने जाहिर कर दी। Lintner के मुताबिक, यह युद्ध जमीन कब्जाने के लिए छेड़ा ही नहीं गया था। चीन बस राजनीतिक और सैन्य मोर्चे पर भारत को कमतर दिखाना चाहता था। फिर, युद्ध लंबा चलने की स्थिति में दूसरी महाशक्तियों के दखल देने का भी खतरा था। तब अमेरिका और ब्रिटेन भारत को सैन्य साजो-सामान मुहैया कराते थे। सोवियत संघ ने भी मिग लड़ाकू विमान देने का वादा किया था।

मौसम का डर | सर्दियां बढ़ती जा रही थीं। हिमालय के कठिन हालात में टिके रहना चीनी सेना के लिए आसान नहीं था। भारतीय सीमा में घुसने के साथ ही उसकी सप्लाई चेन डगमगाने लगी थी। युद्ध दिसंबर तक खिंचता तो शायद चीन अपने सैनिकों तक जरूरी सामान नहीं पहुंचा पाता।

टाइम मशीन

नज़रिये का फ़र्क़

प्रणव प्रियदर्शी

जब भी आबादी के बढ़ने या घटने की बात होती है, उसका साया किसी न किसी रूप में महिलाओं पर पड़ ही जाता है। पिछले दिनों जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हर परिवार को कम से कम तीन बच्चे पैदा करने चाहिए तो उन्होंने सीधे तौर पर महिलाओं की बात नहीं की, लेकिन उस पर आई प्रतिक्रियाओं ने इस बयान के जमीन पर पड़ने वाले असर को स्पष्ट कर दिया। कई महिला सांसदों की तीखी प्रतिक्रिया ने बताया कि इस बयान को आधी दुनिया की सोच, समझ और संवेदनशीलता के अनुरूप नहीं माना जा सकता। हालांकि न तो मोहन भागवत इस तरह का बयान देने वाले पहले व्यक्ति हैं और न ही ऐसे बयान सिर्फ भारत में दिए जा रहे हैं। चाहे चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग हों या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन- सभी अपने-अपने देशों में आबादी में तेज बढ़ोतरी चाहते हैं। लेकिन उनकी इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही। मुख्य वजह यह है कि बच्चों के लालन-पालन की जिम्मेदारी खासतौर पर महिलाओं के ही हिस्से में आती है। और महिलाएं कहीं भी अब इस व्यवस्था को ज्यों का त्यों स्वीकार करने को तैयार नहीं कि उनके जीवन का सबसे बड़ा और महान मकसद है बच्चे जनना और उन्हें बड़ा करना। जैसे-जैसे घर-परिवार में लड़कियों की अहमियत बढ़ रही है, शिक्षा का प्रसार हो रहा है और ये आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बन रही हैं, अपने जीवन और शरीर से जुड़े फैसलों पर उनकी अपनी सोच का असर बढ़ता जा रहा है। लिहाजा धर्म, समुदाय और राष्ट्र के कथित हितों के नाम पर जारी की जाने वाली भावनात्मक अपीलों का उनकी अपनी प्राथमिकता पर खास असर नहीं होता। महिलाओं के बीच से उभरता यह नया नजरिया न सिर्फ आधी दुनिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए हितकर है। यह बताता है कि आबादी घटने-बढ़ने को किसी खास समुदाय, धर्म या राष्ट्र के वर्चस्व के सीमित नजरिए से नहीं बल्कि पृथ्वी के समस्त संसाधनों की रोशनी में देखा जाना चाहिए।

AI Image

आधी दुनिया

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

समाज सुधार के काम में नहीं फंसता असली गुरु

सुरभित गोस्वामी

जो हर बीतते हुए पल में परमात्मा को याद रखने में सफल हो गया, वही आध्यात्मिक गुरु है। परमात्मा का अनुभव करने वाले गुरु का एक ही लक्ष्य होता है, संपर्क में आने वाले शिष्यों को भी परमात्मा का अनुभव कराना! गुरु पर समाज-सुधार का दायित्व नहीं होता। संसार में चोरी, हत्या, बलात्कार, हिंसा, झूठ, फरेब, भ्रष्टाचरी, अशिक्षा, अनैतिकता आदि कर्मों का बोलबाला हजारों बरसों से है। इसे तभी गुणी सृष्टि कहते हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं था, जब ये चीजें नहीं थीं। इसका रूप या स्थान बदल सकता है, लेकिन तभी गुणी सृष्टि अपने अनुपात में हमेशा से उतनी ही बनी रहेगी। हजारों बरसों से समय-समय पर अनेक लोगों ने इस सृष्टि को बदलने की कोशिश की, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं आया। वजह कि तम गुण तो सृष्टि के तीन गुणों में से एक है। इसका नाश कभी हो ही नहीं सकता।

इसलिए गुरु, तमोगुणी सृष्टि में न फंसता है और न इसे ठीक करने में लगता है, बल्कि गुरु तो इस सृष्टि को अच्छी तरह से जानकर उससे ऊपर उठ जाता है। असलियत में गुरु समाज-सुधारक नहीं होते। समाज को सुधारना गुरु का कार्य नहीं, बल्कि 'गुरु बनाये आप समान' यानी गुरु तो अपने संपर्क में आने वाले शिष्यों को परमात्मा का अनुभव पाने की सीख देते हैं। गुरु समाज सुधार नहीं करता, विश्व कल्याण का भाव रखता है।

सच कहूं तो वेदांत कभी सामाजिक समस्याओं के समाधान पर चर्चा नहीं करता। वेदांत का विषय समाज-सुधार नहीं बल्कि परमगति है। वर्तमान में अनेक आध्यात्मिक गुरु समाज-सुधार के कार्यों में शायद इसलिए लग जाते हैं, ताकि वे विशाल जन-समूह को अपनी ओर आकर्षित कर सकें और अपना दायरा बढ़ा सकें। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि करोड़ों में कोई एक प्रयास करता है और उन प्रयास करने वाले करोड़ों में से कोई कभी एक मुझे प्राप्त होता है, क्योंकि प्रभु को पाने की यात्रा में साधक अपने मार्ग से हटने लगता है। वह समाज-सुधार को अपना लक्ष्य बना लेता है, उनकी समस्याओं को ठीक करने लगता है। समाज सुधारने का कार्य सरकार या NGO का है, उन्हें उनका कार्य करने देना चाहिए। गुरु का कार्य व्यक्ति की चेतना को परम चेतना के साथ एक करने का है। आज गुरुओं में भी अपने को बड़ा बताने की होड़ लग गई है कि जिसके पास ज्यादा followers हैं। इसी होड़ के कारण समाज-सुधार का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जबकि वेदांत का ज्ञान, आत्मा-परमात्मा की चर्चा भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकती।

असल में, जब व्यक्ति तमो गुणी सृष्टि को ठीक करने लगता है, तब उसकी चेतना भी उसी तम गुण की तरफ बढ़ने लगती है। इससे चेतना अधोगति करने लगती है और साधक का अध्यात्म पथ छूट जाता है। वैसे भी तमो गुणी सृष्टि अपने आप में बड़ा आकर्षण है। यदि एक बार इसे ठीक करने का चस्का लग जाए, तब उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वेदांत के किसी भी ग्रंथ में कहीं भी समाज सुधार का वर्णन नहीं किया और न ही बुद्ध, महावीर, कृष्ण, पतंजलि, गोरख, कबीर, नानक, रैदास, मीरा आदि किसी ने भी समाज-सुधार की तरफ ध्यान दिया।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ कैसे सुधरे GDP

यह पत्र 4 दिसंबर के लेख 'सब पॉलिटिक्स का चक्कर है बाबू भइया' से संबंधित है। इस साल GDP ग्रोथ में गिरावट आई है, जबकि भारत की क्षमता इससे कहीं ज्यादा हासिल करने की है। बेमतलब के आंदोलनों में देश की काफी ऊर्जा खर्च हो जाती है। कार्यक्षमता का मात्र 60% ही इस्तेमाल में लिया जा रहा है। छुट्टियों की अधिकता और काम में सुस्ती से हम खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। यही स्थिति रही तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकते। सरकार को भी अपनी प्राथमिकताएं दुरुस्त करते हुए नीतियों में बदलाव लाना होगा। तभी जीडीपी में बढ़ोतरी रफ्तार पकड़ सकेगी।

विभूति बुपक्या, ईमेल से

■ प्रगति में रुकावट

3 दिसंबर का लेख 'संभल जैसे मामलों में फैसला कोर्ट से हो' पढ़ा। यह सत्य है कि मंदिर-मस्जिद विवादों का स्थायी समाधान केवल दो तरीके से संभव है। एक, अदालत के माध्यम से और दूसरा आपसी सहमति से। यह भी सच है कि आक्रमणकारियों ने भारत में कई मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिदें बनवाईं, लेकिन आज देश समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे में धार्मिक संघर्ष को सामाजिक और आर्थिक प्रगति में रुकावट नहीं बनने देना चाहिए।

दीपा सिन्हा, ईमेल से

■ भारत के लिए अवसर

वर्तमान में बांग्लादेश में यूनुस की सरकार कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी के प्रभाव में है। यह पार्टी 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद से बांग्लादेश में फल-फूल रही है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद यह संगठन पूरी तरह सक्रिय हो गया है और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। भारत को 1971 की तरह कठोर कदम उठाने की दिशा में सोचना चाहिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं सहित अन्य लोगों की रक्षा के लिए उसे UN के माध्यम से शांति सेना भिजवानी चाहिए। यह भारत के लिए गलती सुधारने का अवसर है।

समरज चौहान, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

नेपाल-चीन ने नौ बिंदुओं पर समझौता – एक खबर
– हिंदी-चीनी भाई-भाई वाला नाटक अब नेपाल के साथ दोहराया जाएगा?

प्रीति गोयल

[illegible]

कल्पमेधा

सहनशील होना अच्छी बात है, परंतु अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है।

- जयशंकर प्रसाद

सुरक्षा पर सवाल

पंजाब अलगाववादी गतिविधियों के लिहाज से अब भी संवेनशील राज्य है। पिछले कुछ समय से फिर कनाडा आदि देशों में रह रहे कुछ अलगाववादी सिख खालिस्तान की मांग उठाने लगे हैं। उसका कुछ असर पंजाब में भी देखा गया। हालांकि सरकार ने चुस्ती दिखाई और ऐसे तत्त्वों पर लगाम कसने में कामयाब हुई। मगर पिछले कुछ समय से पंजाब में आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं, दिनदहाड़े और सरेआम किसी को गोली मार देने में भी अपराधियों को कोई हिचक नहीं होती। ऐसे वातावरण में पुलिस से अधिक चौकस रहने की अपेक्षा की जाती है। मगर पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर जिस तरह स्वर्ण मंदिर परिसर में जानलेवा हमला हो गया, उससे जाहिर है कि पुलिस ने उनकी सुरक्षा के अपेक्षित इंतजाम नहीं किए थे। जिस व्यक्ति ने उन पर गोली चलाई वह खालिस्तान समर्थक पूर्व आतंकवादी है। रामरहीम के आपराधिक मामले में सुलह करवाने के आरोप में अकाल तख्त ने सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित कर गुरुद्वारे में सेवा करने और कीर्तन सुनने का आदेश दिया था। उसी का पालन करते हुए स्वर्ण मंदिर परिसर में वे सेवा दे रहे थे। एक व्यक्ति ने उसी वक्त उन पर हमला करने की कोशिश की। गनीमत थी कि वहां सादी वर्दी में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसे दबोच लिया। इस तरह गोली बादल को न लग कर दीवार पर जा लगी।

हालांकि स्वर्ण मंदिर परिसर में उस तरह श्रद्धालुओं की तकनीकी जांच नहीं होती, जिस तरह अन्य अनेक पूजा स्थलों पर की जाती है। श्रद्धालु मुक्त रूप से परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। पर सुरक्षा के लिहाज से परिसर में सैकड़ों सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। यह अच्छी बात है कि श्रद्धा के मामले में वहां सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, मगर सुखबीर बादल वहां किसी सामान्य श्रद्धालु की तरह नहीं गए थे। उनकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह की लापरवाही की अपेक्षा नहीं की जा सकती। गनीमत है कि सादी वर्दी में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उस हमले को नाकाम कर दिया, पर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि आखिर बंदूक लेकर कोई शख्स कैसे पूर्व मुख्यमंत्री के करीब तक पहुंच गया। अगर उसे परिसर में प्रवेश से पहले ही पकड़ लिया जाता, तो वह गोली चलाने में कामयाब ही न हो पाता। दूसरी बात, कि अगर मंदिर परिसर में सादी वर्दी में प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तैनात थे, तो उन्हें उस व्यक्ति को पहचानने में इतनी देर कैसे हो गई कि वह बादल के करीब तक पहुंच गया।

पंजाब सीमावर्ती राज्य होने के कारण भी बहुत संवेदनशील है। अमृतसर तो बिल्कुल पाकिस्तान सीमा से लगा हुआ है। यह भी छिपी बात नहीं है कि अलगाववादी तत्त्वों के तार पाकिस्तानी दहशतगर्दों से भी जुड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति ने बादल पर हमला किया, उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि खालिस्तान आंदोलन के दौरान पाकिस्तान गया था। ऐसे में पुलिस और सुरक्षाबलों की मामूली लापरवाही भी बड़ी घटना का कारण बन सकती है। पंजाब में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर काबू न पा सकने की वजह से स्वाभाविक ही वहां की राज्य सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। सुखबीर बादल पर हमले के बाद फिर से सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर अंगुलियां उठने लगी हैं। हमला करने वाले की बादल पर गोली चलाने के पीछे मंशा चाहे जो रही हो, पर चिंता की बात है कि वह सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरी का फायदा उठाने में कामयाब हो गया।

दावों की पोल

देश की राजधानी में डेंगू के साथ मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, उससे यह साबित हो गया कि स्थानीय निकाय के साथ राज्य सरकार भी इनकी रोकथाम के लिए गंभीर नहीं थी। इसी के साथ उनके तमाम दावों की पोल भी खुल गई है। यह हाल तब है जबकि दिल्ली सरकार का शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा बजट है। यह दुखद है कि डेंगू के मामले प्रति वर्ष आते हैं, लेकिन इसे रोकने की पुख्ता तैयारी नहीं होती। इस साल नवंबर तक करीब पौने छह हजार लोग डेंगू की चपेट में आए। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक यह संख्या पांच वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। चिकनगुनिया से भी दिल्लीवासी त्रस्त रहे। मलेरिया सहित इस तरह के रोग आमतौर पर अगस्त-सितंबर में बढ़ते हैं और मौसम में ठंडक उतरने के साथ अक्तूबर-नवंबर तक समाप्त हो जाते हैं। मगर इस बार मौसम निकल जाने पर भी लोग मच्छरजनित बीमारियों की चपेट में आते रहे। हालांकि दिल्ली नगर निगम ने लावारोधी उपायों, धुएं के छिड़काव और दवा आदि पर खर्च करने की बात कही है, फिर भी मामले नहीं थमे। स्पष्ट है कि कहीं न कहीं उससे बड़ी चूक हुई है।

अमूमन सर्दियों की शुरुआत के साथ मच्छर कम होने लगते हैं, लेकिन इस बार आश्चर्यजनक रूप से बीमारियां बढ़ीं। अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। जबकि मच्छरों से निपटने और इलाज आदि पर सौ करोड़ रुपए खर्च करने की जानकारी दिल्ली नगर निगम ने दी है। आखिर इतनी बड़ी राशि किस तरह और कहां खर्च हुई, यह जांच का विषय है। बीमारियों से निपटने के उपायों पर स्थानीय निकाय और राज्य सरकार में समन्वय होना चाहिए। खासकर जब एक ही दल दोनों जगह सत्तारूढ़ हो। कोई दो राय नहीं कि राज्य सरकार और नगर निगम अगर योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाते, तो डेंगू और चिकनगुनिया के मामले इतने नहीं बढ़ते। सरकार मोहल्ला क्लीनिकों को सक्रिय कर सकती थी। मच्छर जनित बीमारियों को रोकने के लिए टीमें तैनात की गई थीं, लगातार जनजागरूकता अभियान चलाए जाते रहे, इसके

बढ़ता मृदा प्रदूषण, घटता उत्पादन

मृदा क्षरण का गहराता संकट न सिर्फ पैदावार को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में यह अनेक समस्याओं का कारण बन रहा है, जिनमें मुख्य रूप से पारिस्थितिकी असंतुलन भी शामिल है।

कुशाग्र राजेंद्र

मिट्टी के ऊपर भुरभुरा और स्नेहिल तत्त्व बीजों को अंकुरित कर और जड़ों को धारण कर हमारी धरती पर जीवन सुनिश्चित करता है। यह आज के दौर में आठ अरब लोगों के लिए खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने, बिगड़ते पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और जलवायु संकट को काफी हद तक कम करने का मजबूत संबल है। मगर आज प्राणियों के लिए पोषक मिट्टी का अस्तित्व खुद गंभीर संकट में घिरा है। मिट्टी का बड़े पैमाने पर क्षरण न केवल कृषि पैदावार और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को और अधिक व्यापक तथा जटिल बना रहा है। मिट्टी के क्षरण के साथ उसकी उत्पादकता की कमी धीरे-धीरे बढ़ रही है, प्रदूषण के इतर इसका दायरा आधुनिक कृषि तरीकों के कारण दबे पांव फैल रहा है।

मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, जमा होता नमक और जहरीले रसायनों के संदूषण और फसल उत्पादन में आ रही कमी मृदा क्षरण के दायरे में आते हैं। मृदा क्षरण आमतौर पर मौजूदा रसायनों (जिसमें खाद और जहरीले कीटनाशक शामिल हैं) के अंधाधुंध इस्तेमाल, भूमि के परंपरागत उपयोग में व्यापक बदलाव, जंगल की कटाई, बाढ़, सुखाड़, जलजमाव और जलवायु परिवर्तन से तापमान आदि कारणों से पैदा होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां खेती-किसानी आज भी अधिकांश लोगों के लिए जीविका का स्रोत है, दस लाख 78 हजार वर्ग किलोमीटर दायरे में फैले विश्व के दूसरे सबसे बड़े कृषि तंत्र की रीढ़ मिट्टी ही है। मृदा क्षरण का गहराता संकट न सिर्फ पैदावार को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में यह अनेक समस्याओं का कारण बन रहा है, जिनमें मुख्य रूप से पारिस्थितिकी असंतुलन भी शामिल है। मिट्टी सर्वेक्षण के राष्ट्रीय ब्यूरो के मुताबिक भारत में लगभग एक-तिहाई मिट्टी यानी लगभग 12 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र मृदा क्षरण के दायरे में है, जिसका अच्छा-खासा हिस्सा समुद्र के लवणीकरण से प्रभावित है।

बड़े पैमाने पर मृदा क्षरण के बावजूद, तकनीक आधारित गहन कृषि के कारण पैदावार में वृद्धि हुई है, और अब भारत कृषि उपज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वह खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। मगर बाढ़ के दौरान और निर्माण कार्य के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी के कटाव, रासायनिक खाद के व्यापक इस्तेमाल से जमा होती लवणता, बढ़ती अम्लीयता और जलभराव आदि से कृषि योग्य भूमि का एक बड़ा भाग ऊसर होता जा रहा है। अगर इसी तरह मृदा क्षरण जारी रहा तो आने वाले वर्षों में खाद्य आयात करना पड़ सकता है, जबकि भारत, दुनिया के केवल 2.4 फीसद भूमि क्षेत्र के साथ, विश्व की 18 फीसद आबादी को खिलाने में सक्षम है।

मृदा क्षरण के प्रमुख कारणों में अमर्यादित तरीके से खेती के अलावा बड़े पैमाने पर शहरीकरण और औद्योगीकीकरण के लिए भूमि उपयोग में व्यापक बदलाव भी जिम्मेदार है। इसके साथ-साथ भारत मवेशियों की संख्या के लिहाज से भी सबसे बड़ा देश है। इनके चरने के दौरान जमीन की ऊपरी वनस्पति हटने से मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर हो

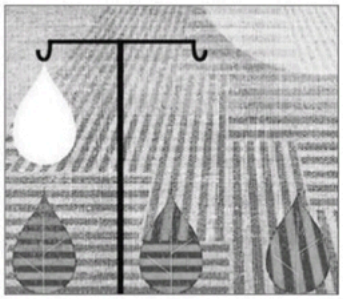

जाती है और यह वर्षा और हवा के कारण कटाव का शिकार हो जाती है। भारत जनसंख्या के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा देश है और डेढ़ अरब लोगों का पेट भरने के लिए जरूरी अनाज उत्पादन का दबाव कृषि पर लगातार बना हुआ है। साथ ही उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा

> उर्वर मिट्टी आज के दौर में भारत जैसे देश के लिए न सिर्फ पेट भरने किए जरूरी, बल्कि अर्थव्यवस्था की धुरी है। ऐसे में जरूरत है कि मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक तरीके से वापस लाया जाए। इसके लिए हमें मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक स्वास्थ्य को बहाल करने की आवश्यकता होगी, जो एक लंबी और जटिल, पर संभव प्रक्रिया है। अपने जैविक तत्व यानी कार्बन को खोकर ऊसर हो चुकी मिट्टी में दोबारा जैविकता लौटाने की जरूरत होगी। अभी कुल इस्तेमाल हो रहे उर्वरकों में केवल छह फीसद जैविक स्रोत वाले उर्वरक का इस्तेमाल हो रहा है। जरूरत है कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम कर जैविक खाद आधारित खेती-किसानी को प्रोत्साहन मिले।

रखरखाव और अक्षम प्रबंधन के कारण बर्बाद हो जाता है। इन सबका असर अंततः मिट्टी पर पड़ता है।

आजादी के बाद अनाज की बढ़ती जरूरत और खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए हरित-क्रांति का प्रकल्प लागू हुआ, जो मुख्य रूप से कृत्रिम सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और संकर बीज पर आधारित था, जिसका मुख्य लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा अनाज का उत्पादन। इस प्रयास में मिट्टी की उर्वरता नेपथ्य में चली गई। लगातार एक ही तरह की फसल उगा कर ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा किया जाने लगा, जिससे मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्त्व कम होने लगे। इसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव और जैविक पदार्थ खत्म होते चले गए। वर्तमान में कृषि कार्य में 94 फीसद तक रसायनिक उर्वरक का उपयोग होता है। यहां तक कि रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से हमारे खेतों और फसलों को जहरीला बना दिया। हरित-क्रांति के दौरान हमारा अनाज उत्पादन पांच करोड़ टन से बढ़ कर तीस करोड़ टन पहुंच गया, पर यह उपलब्धि उपजाऊ मिट्टी की कीमत पर हासिल की गई प्रतीत होती है।

ऐसे में मिट्टी का तेज गति से क्षरण भारत की बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा के गंभीर संकट का कारण बन सकता है। मृदा क्षरण के कारण न सिर्फ उत्पादकता में कमी आती है, बल्कि इसमें प्राकृतिक रूप से मौजूद कार्बन की मात्रा कम हो जाने से इसकी पानी सोखने और जकड़ कर रखने की क्षमता भी काफी हद तक घट जाती है। नतीजा यह कि पानी के स्रोतों से जल का पुनर्भरण काफी कम हो जाता है, जो भारत में बढ़े स्तर के भूजल स्तर में गिरावट और सूखे की बढ़ रही समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। हरियाणा और पंजाब, जो भारत के सबसे अधिक अनाज उत्पादक हैं, वहां जल स्तर खरतनाक रूप से गिर चुका है। समृद्ध और उपजाऊ मिट्टी कृषि-प्रधान भारत के लिए वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रखती है। तभी तो पिछले कुछ दशक में आई बड़े स्तर की वैश्विक मंदी में भी भारतीय अर्थव्यस्था मामूली असर के साथ तेजी से आगे बढ़ती रही।

उर्वर मिट्टी आज के दौर में भारत जैसे देश के लिए न सिर्फ पेट भरने किए जरूरी, बल्कि अर्थव्यवस्था की धुरी है। ऐसे में जरूरत है कि मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक तरीके से वापस लाया जाए। इसके लिए हमें मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक स्वास्थ्य को बहाल करने की आवश्यकता होगी, जो एक लंबी और जटिल, पर संभव प्रक्रिया है। अपने जैविक तत्व यानी कार्बन को खोकर ऊसर हो चुकी मिट्टी में दोबारा जैविकता लौटाने की जरूरत होगी। अभी कुल इस्तेमाल हो रहे उर्वरकों में केवल छह फीसद जैविक स्रोत वाले उर्वरक का इस्तेमाल हो रहा है। जरूरत है कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम कर जैविक खाद आधारित खेती-किसानी को प्रोत्साहन मिले। हालांकि इससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी की आशंका शामिल है।

भारत में प्रकृति केंद्रित समृद्ध कृषि परंपरा रही है, जो मिट्टी की क्षमता, मौसम और पानी की उपलब्धता के सामंजस्य पर आधारित है। इसे पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। दबे पांव मिट्टी-पानी का संकट हमारे खेतों से होते हुए हमारी थाली तक आ पहुंचा है। ऐसे में इस भीषण समस्या का संज्ञान लेने और सरकार, समाज तथा व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है।

जिंदगी के मोड़

प्रभात कुमार

जिंदगी के रास्तों पर अनेक जगह चाहे-अनचाहे मोड़ आ जाते हैं, जिनका हमें पता नहीं चलता। किसी भी रास्ते पर सही जगह मुड़ने का खास महत्त्व है। वाहन चलाते हुए भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हम रास्ता भूल जाते हैं, सड़क पर आगे निकल जाते हैं और एकदम से बाएं या दाएं नहीं मुड़ सकते। हमें कुछ आगे जाकर वापस मुड़ने के लिए बनाई गई जगह या 'यूटर्न' से पीछे आना पड़ता है और सही रास्ता लेना होता है। खासकर लंबी दूरी की सड़कों पर कहीं भी मुड़ जाने की सुविधा हर कहीं नहीं होती। इस क्रम में कई बार काफी दूरी का सफर तय करना पड़ता है। अपनी मर्जी से कहीं भी मुड़ जाने पर तेज रफ्तार सड़कों पर जोखिम से गुजरना या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है। जिंदगी एक दिलचस्प, अप्रत्याशित घटनाओं और संभावनाओं से भरा सफर है। इसे सुरक्षित तरीके से तय करते रहने वाले भी अनेक बार गलती से आगे, इधर या उधर चले जाने के कारण थोड़ा पीछे आते हैं और फिर सही रास्ता अपना लेते हैं, ताकि आगे बढ़ते रहें। यों भी, सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अगर थोड़ी दूरी भी तय करनी पड़े, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बल्कि यह अपने हित में होता है।

इस सफर में उचित स्थिति अपने मन की बात कहकर यह आकलन कर लेने की है कि आपके शब्द सामने वाले को बुरे तो नहीं लगे या कितने बुरे लगे। अगर माफी मांगना जरूरी है, तो वक्त की जरूरत के मुताबिक माफी मांग भी लेनी चाहिए। खुले दिल से माफी मांग ली जाए तो संबंधों का पुल सलामत रहता है। जमाने से सुनते आए हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन जबान से निकले शब्दों से बना जख्म कभी नहीं भरता। हालांकि वक्त के साथ यह बात अपनी प्रवृत्ति बदल रही है। शब्द उन फलों की तरह हैं कि पहले भेंट कर दें, पता चले कि सामने वाले ने चख लिए, लेकिन स्वाद नहीं लगे तो फल वापस ले लिए जाएं। शब्दों में अब वह पुरानी बात नहीं रही। जिंदगी बाजार की गिरफ्त में है। कहे गए शब्द वापस लिए जा सकते हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि इस तरह से सामने वाले को भी बेहतर लगने लगेगा।

जिंदगी जीने के अंदाज सिखाने वाले कम नहीं हैं। राजनीति भी अब जिंदगी की प्रशिक्षक हो गई है। यह सिखाती है कि बात कैसे करते हैं। अवसर और परिस्थिति के अनुसार कौन-से स्वादिष्ट या बेस्वाद शब्द दूसरों को परोसने चाहिए। यह अभिनेताओं को अभिनय सिखा रही है। उन्हें समझाती है कि राजनीति में सिर्फ अभिनय नहीं करते, बल्कि बहुत समझदारी भरी कुटिलता से अभिनय करते हैं। काबिल अभिनेता भी अगर वांछित अभिनय न कर पाए, तो छोटा-सा संवाद वापस लेने के लिए मोड़ ढूंढ़ना पड़ता है। इससे मानसिक रूप से परेशानी होती है, भूख उड़ जाती है और आत्मा तड़पती है, फिर भी स्थिति ठीक होने का अभिनय लगातार करते रहना होता है। सही मोड़ काटना सीखते रहना होता है।

दिग्गज व्यक्ति अनुभव के वस्त्र बदल-बदल कर, अभिनय करते-करते निर्देशक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी नए मोड़ चुनने पड़ते हैं। शतरंज की बिसात पर नए मोहरे चलाना सीखना पड़ता है। कई मोड़ ऐसे भी आते हैं, जहां सार्वजनिक खेद प्रकट करना होता है। देखा जाए तो अपनी गलती पर अगर सचमुच अफसोस नहीं है, तो खेद प्रकट करना भी कई बार सही अवसर पर किया गया कुशल अभिनय होता है। जिंदगी में हर तरह का किरदार निभाना होता है जो उसी तरह के अभिनय की मांग करता है। यहां करतब भी जरूरी होते हैं। स्थिति के अनुसार एक दूसरे को स्थिर या अस्थिर करने के लिए विश्वसनीय करतब करवाए जाते हैं और कई बार तो असली मारधाड़ भी जरूरी हो जाती है, जो करनी ही पड़ती है। यह जिंदगी का खतरनाक मोड़ होता है, जिस पर आमतौर पर सभी ठहरना नहीं चाहते। ऐसी जगह रुकना एक तरह की मजबूरी होती है। पीड़ित व्यक्ति अगर शांत रहे तो बेहतर, नहीं तो फिर अनुभवी मोड़ चुनना होता है।

यह मोड़ होता है 'माफी मोड़', जहां अपनी गलती का अहसास करते हुए या फिर स्थिति को सामान्य करने के मकसद से माफी मांग ली जाती है। यह तारीफ के काबिल मोड़ होता है। सभी समझदार लोग इसकी तारीफ ही करते हैं। देखा जाए तो इससे दोनों काम हो जाते हैं। गुस्सा भी जाहिर कर दिया और माफी मांगकर स्थिति भी नियंत्रण में कर ली। माफी मांगते हुए अगर यह कह दिया जाए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या मेरे कहने का वह मतलब नहीं था तो भी तारीफ मिल सकती है।

निजी जिंदगी में आराम से काटे गए मोड़ काफी राहत पहुंचाते हैं। अगर पत्नी और पति एक दूसरे को ऐसा कहते रहें तो अच्छा संवेदनशील व्यवहार माना जाता है, जिसमें रास्ते पर आगे जाकर मुड़कर लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। विकास के कारण बढ़ती आजादी ने हर एक को कुछ भी बोलने, देखने और करने का अधिकार दे दिया है, लेकिन आजादी के इस मोड़ पर कर्तव्य भुलाए जा रहे हैं। ड्राइविंग चाहे राजनीतिक, धार्मिक या पारिवारिक हो, ऐसी होनी चाहिए कि नियंत्रण बरकरार रहे। स्थितियों की आवाजाही उचित गति से चलती रहे। जहां मुड़ना है, उस जगह को भूला न जाए, ताकि आगे जाकर वापस आना न पड़े।

दुनिया मेरे आगे

> अगर माफी मांगना जरूरी है तो वक्त की जरूरत के मुताबिक माफी मांग भी लेनी चाहिए। खुले दिल से माफी मांग ली जाए तो संबंधों का पुल सलामत रहता है। जमाने से सुनते आए हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन जबान से निकले शब्दों से बना जख्म कभी नहीं भरता। हालांकि वक्त के साथ यह बात अपनी प्रवृत्ति बदल रही है।

इतिहास की भूमिका

इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि यह समाज के मूल्यों तथा विचारधारा का जीवंत दस्तावेज है। जब इस दस्तावेज को तोड़ा-मरोड़ा जाता है, तो न केवल अतीत के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की दिशा को भी विकृत करता है। हमारे देश में ऐतिहासिक तथ्यों को प्रायः राजनीतिक उद्देश्यों, साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण और वैचारिक प्रचार के लिए हथियार बनाया गया है। उदाहरण के लिए, स्वाधीन नायकों और स्वतंत्रता संग्राम के योगदान को कई बार क्षेत्रीय या जातीय पहचान तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि उनकी भूमिका राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखी जानी चाहिए। यह समस्या विशेष रूप से शिक्षा प्रणाली में स्पष्ट होती है, जहां पाठ्यक्रम में ऐतिहासिक घटनाओं का चयन और प्रस्तुति प्रायः पक्षपातपूर्ण होती है। इस स्थिति से निपटने के लिए इतिहास की लेखन प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष, वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित बनाने की आवश्यकता है। इतिहास के अध्ययन को तर्कसंगत दृष्टिकोण से जोड़ना अहम कदम हो सकता है। इतिहास को मिथ्या और सत्य के बीच संतुलित रखना न केवल शिक्षाविदों की जिम्मेदारी है, बल्कि यह हर नागरिक का दायित्व भी है।

- अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

चुनाव पर नजर

महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद अब दिल्ली विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर है। दिल्ली में चुनाव अगले साल फरवरी में संभावित है। दिल्ली के चुनावी परिणाम का असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ता है। इसलिए सभी प्रमुख दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आम जनता में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गली-मोहल्ले में चर्चा शुरू हो चुकी है। सड़कें-गलियां और चौराहे संभावित उम्मीदवारों के पोस्टरों से भर चुके हैं। सभी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने तो अपने ग्यारह उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है, लेकिन मौजूदा समय में दिल्ली की राजनीति का जो हाल है, उसमें भाजपा को इस चुनाव में पर्याप्त अवसर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी यहां की विभिन्न समस्याओं को हल करने में असफल रही है।

- विजय किशोर तिवारी, दिल्ली

निरर्थक बहस

आज इलेक्ट्रानिक मीडिया का चेहरा बदल गया है। दिन-रात समाचार देने की उनमें क्षमता बची नहीं है, तो ज्यादातर समय वे निरर्थक राजनीतिक बहसों में बर्बाद कर देते हैं। लोग टीवी पर समाचार सुनने-देखने के लिए तरस जाते हैं। इतने बड़े देश में कहीं न कहीं कोई घटना घट रही होती है। मगर कोई खबर नहीं। टीवी चैनलों पर चर्चा के लिए गैर-राजनीतिक विश्लेषकों जैसे लेखकों और राजनीति में रुचि रखने वाले प्रबुद्ध नागरिकों को बुलाया जाना चाहिए। आर्थिक विषयों के लिए निष्पक्ष अर्थशास्त्रियों को बुलाना चाहिए, विशेषकर चुनाव परिणाम और बजट प्रस्ताव पर बातचीत के लिए या इनकी संभावित भविष्यवाणी के लिए। नेताओं को नहीं बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग प्रायः गलत व्याख्या करते हैं। झूठे आरोप लगाते हैं। भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, जिससे जनता को गलत जानकारी देने के साथ ही सामाजिक सद्भावना को आघात पहुंचने का डर रहता है।

- ललित दुबे, रतलाम

लापता होते बच्चे

राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने वर्ष 2018 से 2022 तक गायब हुए बच्चों के आंकड़े जारी किए हैं। एनसीआरबी के अनुसार मध्यप्रदेश में रोजाना औसतन 30 बच्चे लापता हो रहे हैं। वर्ष 2018 से 2021 तक देश में यह राज्य पहले, तो 2022 में दूसरे स्थान पर था। मध्यप्रदेश बच्चों के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक है। यहां लड़कों की तुलना में लड़कियों का अपहरण चार गुना ज्यादा हो रहा है। भीख मंगवाने और मानव अंग तस्करी के लिए भी अपहरण किए जा रहे हैं। अपहरण के लिए दो से चौदह साल तक के बच्चे उठाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें फुसलाना और धमकाना आसान होता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि पुलिस बच्चों के लापता होने पर गुमशुदगी नहीं, बल्कि अपहरण की धारा में मामला दर्ज करें। साथ ही एक दिशा-निर्देश में कहा गया है कि लापता बच्चों के बारे में तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचित करे।

म्यांमार में सैनिक शासन

ढीली पड़ती पकड़

म्यांमार में सैनिक शासन की पकड़ लगातार ढीली हो रही है जिससे भविष्य में विखंडन का खतरा पैदा हो गया है। सालों तक दमनकारी शासन, मानवाधिकार उल्लंघनों तथा जनता के खिलाफ अत्याचारों के बाद म्यांमार के सैनिक शासक अब रक्षात्मक स्थिति में आ गए हैं। सशस्त्र विद्रोहियों को लगातार सफलतायें मिलने के बाद अब सत्ता पर उनकी पकड़ लगातार ढीली पड़ती जा रही है। साल भर की आक्रामकता के बाद सैनिक शासक-विरोधी बलों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के 480 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है जो मांडले को चीन से जोड़ता है। यह महत्वपूर्ण मार्ग उत्तरी म्यांमार के दुर्गम क्षेत्र से गुजरता है। इस विजय से सेना को टैक्स संग्रह करना कठिन हो गया है और इससे उसका केन्द्रीय पैदानों में मजबूत गढ़ों पर वर्चस्व घटा है। इससे गृह युद्ध के चौथे वर्ष में प्रवेश के साथ विद्रोहियों का साहस बढ़ा है। म्यांमार वर्तमान समय में विघटन की कगार पर है क्योंकि 2021 में सत्ता पर कब्जा करने वाले सैनिक शासक को लगातार पूरे देश में सशस्त्र विद्रोही समूहों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले साल नस्ली सशस्त्र संगठनों तथा स्थानीय मिलिशियाओं ने अपने आक्रमण तेज कर प्रमुख क्षेत्रों पर कब्जे कर लिए जिससे म्यांमार के विभाजित नियंत्रण क्षेत्रों में बंटने का खतरा पैदा हो गया है। सैनिक शासक को सबसे बड़ी चुनौती अराकान आर्मी-एए तथा म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस आर्मी-एमएनडीएए व तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी-टीएनएलए के गठबंधन से मिली है। मुख्यत: चीन की सीमा से सटे शान राज्य में सक्रिय इन समूहों ने रणनीतिक व समन्वित हमले शुरू कर महत्वपूर्ण क्षेत्र पर सैनिक शासक का नियंत्रण समाप्त कर दिया है।

राखीन व चिन राज्यों में अराकान सेना के हमलों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रीय लाभ प्राप्त किए हैं तथा विशाल भूक्षेत्र व महत्वपूर्ण कस्बों को अपने नियंत्रण में लिया है। इस प्रगति से सैनिक शासक स्वयं को इस क्षेत्र में अधिकारी की तरह नहीं पेश कर सकते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे तथा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। म्यांमार में चीन के बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक हित हैं और उसने सैनिक शासक तथा विद्रोही समूहों के बीच अपना प्रभाव डालने के प्रयास किए हैं। विद्रोहियों द्वारा राखीन प्रांत तथा शान राज्य के बड़े हिस्सों पर लगभग पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने के बाद एक एकीकृत संरचना के रूप में पूरे देश पर नियंत्रण करने की सैनिक शासक की क्षमता तेजी से गायब हो रही है। इस विखंडन से वास्तव में म्यांमार विभिन्न समूहों द्वारा नियंत्रित स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित हो सकता है। यह युद्ध आम जनता के लिए आसान नहीं है और उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। खासकर रोहिंग्या-बहुसंख्य क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों में पूरे समुदाय विस्थापित हुए हैं क्योंकि लोगों को विभिन्न मोर्चों पर हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। मूलभूत सेवायें बहुत बुरी स्थिति में हैं तथा मानवाधिकार संकट लगातार गहरा रहा है। लंबे समय से जारी युद्ध के कारण म्यांमार की अर्थव्यवस्था बरबाद हो गई है, विदेशी निवेश नहीं आ रहा है तथा प्रमुख क्षेत्र ध्वस्त हो रहे हैं। चीन तथा अन्य देशों द्वारा समर्थित ढांचागत परियोजनायें संकट का सामना कर रही हैं जिससे आर्थिक अस्थिरता और बढ़ रही है। म्यांमार में अस्थिरता के दक्षिणपूर्व एशिया पर व खासकर थाईलैंड व भारत पर व्यापक प्रभाव पड़ेंगे। सीमापार से हिंसा, शरणार्थियों की बाढ़ तथा नशीले पदार्थों के व्यापार जैसी संभावित अवैध गतिविधियों के कारण क्षेत्रीय स्थिरता को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आने वाले दिन यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे कि म्यांमार अपनी एकजुटता बनाए रखता है या वह विखंडन और लगातार टकराव का शिकार बन जाता है।

नेहरू का विरोधियों पर हमला

जवाहर लाल नेहरू ने भारत के संविधान को स्वरूप देने वाले डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा डा. बी.आर. अंबेडकर पर निशाना लगाया क्योंकि वे राष्ट्र के प्रति उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं थे।

अनिर्वान गांगुली
(लेखक, डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं)

वर्ष 1951-52 में देश के पहले आम चुनाव के लिए प्रचार अभियान शुरू होने के समय नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने दो नेताओं पर आक्रामक ढंग से निशाना लगाया। जनसंघ और डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर निशाना लगाते हुए नेहरू सीधे गालीगलौज की भाषा पर उतर आए और उन्होंने 'जनसंघ को कुचल देने' का आह्वान किया। लेकिन डा. अंबेडकर तथा उनके नेतृत्व वाली 'शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन' के लिए थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाया।

बाबा साहेब अंबेडकर को चुनाव में पराजित करने के लिए नेहरू ने अपने विश्वसनीय कम्युनिस्ट मित्रों को लगाया। वास्तव में अपने राजनीतिक व बौद्धिक विरोधियों से निपटने के मामले में नेहरू बहुत क्षुद्र मनोवृत्ति वाले व्यक्ति थे। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कुछ ही दिन पहले तक संविधान सभा में ये उनके मित्र थे और उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए संवैधानिक आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान किया था। नेहरू अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पराजित करवाना चाहते थे। उनको इन नेताओं के संसदीय कौशल तथा भारत के लिए नई राजनीति निर्धारित करने में इनके भाषण कौशल और पैरोकारी की क्षमता से चिढ़ पैदा होती थी।

नेहरू ऐसी नई संसद चाहते थे जहां कम्युनिस्टों को छोड़ कर उनके कोई विरोधी न हों क्योंकि वास्तव में हर हाल में कम्युनिस्ट उनके वैचारिक साथी थे। नेहरू ने इसी कारण कज़ूर में कम्युनिस्ट नेता ए.के. गोपालन के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। उनकी दोस्ती खासकर सरदार पटेल के निधन के बाद और गहरी हुई थी। लेकिन नेहरू की व्यापक आक्रामक रणनीति के बावजूद डा. मुखर्जी ने कोलकाता दक्षिण सीट पर विजय प्राप्त की और उनके नेतृत्व में जनसंघ एक राष्ट्रीय पार्टी बनने में सफल रही। इस चुनाव में बाबा साहेब अंबेडकर बंबई उत्तर की सीट से हार गए क्योंकि नेहरू की मिलीभगत से कम्युनिस्टों ने उन पर निशाना लगाया था। नेहरू ने अंबेडकर को हराने का यह काम कम्युनिस्टों को खासतौर से दिया था।

नेहरू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि डा. अंबेडकर का स्वास्थ्य खराब हो रहा था जिसके कारण उनको आवागमन में कठिनाई होती थी। उनको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि डा. अंबेडकर ने स्वयं को संविधान को स्वरूप देने में अपने को पूरी तरह थका डाला था और इस कारण उनको नैतिक रूप से समर्थन मिलना चाहिए था।

डा. अंबेडकर के सर्वाधिक आधिकारिक व विश्वसनीय जीवनीकार धनंजय कीर के अनुसार, अंबेडकर अपनी पराजय का कारण एस.ए. डांगे के हथकंडों को मानते थे। प्रचार अभियान के दौरान डांगे ने दुष्टतापूर्ण नारा देते हुए कहा था कि 'अपने वोटों को बरबाद कर डालो, पर उनको अंबेडकर को न दो।' डा. अंबेडकर के दृष्टिकोण से 'कम्युनिज्म जंगल की आग की तरह था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज और सभी चीजों को जला कर राख कर देता है।'

लेकिन नेहरू को 'जंगल की इस आग' से प्रेम था। डा. अंबेडकर के जीवन के बारे में अपनी स्मृतियों के डा. सविता अंबेडकर ने याद किया है कि पहले चुनाव के दौरान नेहरू 'उनके निर्वाचन क्षेत्र पर गहरी नजर रखते थे'। वे जानते थे कि मुंबई कांग्रेस के प्रमुख एस.के. पाटिल तथा कम्युनिस्ट पार्टी के एस.ए. डांगे को कैसे एकजुट रखा जाए। सविता अंबेडकर ने लिखा, 'नेहरू, एस.के. पाटिल और डांगे ने तय किया कि वे सब कुछ करेंगे, अवसर के अनुकूल कोई भी रणनीति अपनाएंगे, पर वे हर हालत में डा. अंबेडकर को चुनाव में जीतने नहीं देंगे।' सविता अंबेडकर ने आगे लिखा कि 'कांग्रेस-कम्युनिस्ट षड़यंत्र के कारण संविधान निर्माता डाक्टर साहेब को चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा।' इस प्रकार कांग्रेस के हथकंडों के कारण भारतीय संविधान निर्माता को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

जवाहरलाल नेहरू ऐसी नई संसद चाहते थे जहां कम्युनिस्टों को छोड़ कर उनके कोई विरोधी न हों क्योंकि वास्तव में हर हाल में कम्युनिस्ट उनके वैचारिक साथी थे। नेहरू ने इसी कारण कज़ूर में कम्युनिस्ट नेता ए.के. गोपालन के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था।

डा. अंबेडकर को जानबूझ कर पराजित करने की इस रणनीति ने उनको अत्यधिक निराश कर दिया क्योंकि वे संसद में वापस लौटना चाहते थे। उनको लगता था कि संसद उनका स्वाभाविक कार्यक्षेत्र है और वे आने वाले वर्षों में देशवासियों को अपना सर्वोत्तम योगदान दे सकते हैं। सविता अंबेडकर ने लिखा, 'चुनाव में इस भयानक पराजय से उनके पहले से ही खराब हो रहे स्वास्थ्य पर भयानक नकारात्मक प्रभाव पड़ा, वे निराशा और अवसाद में डूब गए तथा इसके कारण उनमें एक प्रकार की विकलांगता आ गई।'

जब बाबा साहेब ने भंडारा सीट से उपचुनाव के माध्यम से लोकसभा में प्रवेश का प्रयास किया तो नेहरू और कांग्रेस ने उनके लिए दूसरी चुनावी पराजय सुनिश्चित की। उल्लेखनीय है कि इस चुनाव में बाबा साहेब ने युवा आरएसएस प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी को अपना चुनाव समन्वयक बनाया था। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने अगले दो साल तक बाबा साहेब के निर्देशन में काम किया और उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन आंदोलन-'भारतीय मजदूर संघ' के लिए धन की व्यवस्था की। भंडारा उपचुनाव कांग्रेस के लिए अवसर था कि वह अपनी क्षुद्रता से बाहर निकल सके, लेकिन नेहरू बाबा साहेब के अंध-विरोध के रास्ते पर डटे रहे। डा. सविता अंबेडकर ने बहुत दु:ख के साथ लिखा कि 'कांग्रेस को उचित सम्मान के साथ संविधान निर्माता को संसद में आमंत्रित करने के लिए बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। यदि किसी और चीज के लिए नहीं तो देश के कल्याण के लिए नेहरू को बाबा साहेब को लोकसभा में निर्वाचित होने में सहायता करनी चाहिए थी। लेकिन इसके एकदम उलट कांग्रेस ने डांगे जैसे व्यक्ति से हाथ मिलाया और बाबा साहेब को हराने के लिए हर हथकंडा अपनाया।

इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस को देश के कल्याण के बजाय अपनी पार्टी की ज्यादा चिन्ता है।' धनंजय कीर ने लिखा कि भंडारा चुनाव में डा. अंबेडकर पर नेहरू और कांग्रेस लगातार हमले कर रहे थे। अंबेडकर चुनाव इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा था, 'जनता को विपक्ष की ओर से एक और दृष्टिकोण दिया जा सके। यदि वे कांग्रेस से समझौता कर लेते तो संसद पहुंचना उनके लिए कठिन नहीं था।'

लेकिन बाबा साहेब ने कांग्रेस से समझौता न करने का निर्णय किया और इस कारण अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राजनीतिक अपमान और उत्पीड़न का सामना किया। विडंबना है कि आज नेहरू के वारिस पूरी बेशर्मी से संविधान की प्रतियां लहराते हैं। उनके इस कृत्य की घोर निन्दा की जानी चाहिए। उनकी कार्रवाई को अप्रासंगिक तथा पराजित राजनीतिक पार्टी का निराशाजनक ढोंग कहा जाना चाहिए।

आत्मा की शाश्वत है यात्रा

> जीवन और मृत्यु नवीनीकरण के एक शाश्वत चक्र में गुंथे हुए हैं, जो आत्मा को विकास के अवसर प्रदान करते हैं।

ब्रह्मकुमार निकुंज
(लेखक, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

बहुत कम मनुष्य जानते हैं कि मृत्यु कब आएगी, कैसे होगी और यह कहाँ ले जाएगी क्योंकि मृत्यु अपरिहार्य है और इसका कोई कैलेंडर नहीं है। जीवन सभी के लिए न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन मृत्यु सभी के साथ समान रूप से पेश आती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शक्तिशाली हो या नम्र, देवता हो या राक्षस, संत हो या पापी। मृत्यु के कई रंग हैं। देशभक्ति या सामाजिक कारण जैसे किसी महान उद्देश्य के लिए मरना मृतकों को गौरव प्रदान करता है। ऐसी मौतें आत्मा के लिए बहुत सहानुभूति और सद्भावना जीतती हैं।

फिर कुछ लोग बिना किसी बीमारी या दर्द के चुपचाप मर जाते हैं। ऐसी मौतें भाग्यशाली आत्माओं की होती हैं जो अच्छे कर्म करते हैं। दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या, फांसी आदि जैसी हिंसक मौतें भी होती हैं। ऐसी मौतों से पहले दुख और कड़वाहट होती है और उसके बाद आत्मा को और अधिक पीड़ा होती है। तो! क्या कोई सुखद मृत्यु होती है या क्या मृत्यु एक पुरस्कृत अनुभव हो सकती है? अच्छा!

इसे समझने के लिए, हमें पहले जीवन को समझना होगा। इसके लिए हमें खुद से कुछ सवाल पूछने की जरूरत है कि जब ईसान जिंदा होता है तो क्या होता है। जब मौत होती है तो क्या खत्म हो जाता है? एक तरफ हम कहते हैं कि एक व्यक्ति मर गया और दूसरी तरफ हम शरीर को नश्वर अवशेष के रूप में देखते हैं। तो नश्वर क्या है? व्यक्ति या शरीर? संक्षेप में, जीवन एक ऐसी घटना है जो तब सामने आती है जब आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है और मृत्यु बस एक ऐसी स्थिति है जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए जो व्यक्ति मर जाता है वह आत्मा है जो शरीर में रहती थी। तो, आत्मा क्या है? आत्मा एक संवेदनशील ऊर्जा है जो खुद को तीन स्तरों, मन, बुद्धि और संस्कारों में प्रकट करती है। एक आम कहावत है कि जब आप मर जाते हैं तो दुनिया आपके लिए मर जाती है। इसलिए, मृत्यु के साथ जो खत्म होता है वह आत्मा का उस सीमित दुनिया से संबंध या लगाव है जिससे वह शरीर में रहते हुए जुड़ी हुई है, जैसे रिश्ते, संपत्ति, भूमिकाएं, आदि। हालांकि, आत्मा की एक अद्भुत विशेषता यह है कि यह कर्म ऋण और संस्कारों को अगले जीवन में ले जाती है। हम सभी जानते हैं कि एक दिन सभी को मरना है, फिर भी हम अपनी मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचते। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आत्मा के रूप में हम सदियों से जन्म-जन्मांतर तक अलग-अलग शरीरों में रहते आए हैं। शरीर के प्रति हमारा लगाव इतना मजबूत है कि बुढ़ापे में भी लोग बड़ी और बेहतर संपत्ति खरीदते हैं और भविष्य के लिए निवेश करना जारी रखते हैं ताकि वे आराम से रह सकें। मृत्यु हर चीज का अंत नहीं है, लेकिन यह मानव दुनिया में आत्मा की यात्रा में एक बड़ा मोड़ है।

मृत्यु का मतलब नयापन भी है। यह आत्मा को ताजगी और जीवन के लिए नए उत्साह से भर देती है और आत्मा के लिए खुद को समृद्ध करने और अलग-अलग भूमिकाओं, शरीरों और स्थानों में अलग-अलग आत्माओं के साथ नए अनुभवों के साथ विकसित होने के दायरे को व्यापक बनाती है। यह नवीनीकरण हो अनंत काल की अवधारणा को सार्थक बनाता है। यदि मृत्यु न होती तो जीवन और विश्व नाटक का चक्र अनंत काल तक नहीं चल सकता था। आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध आत्मा के लिए, मृत्यु का अर्थ सांसारिक बंधनों से अंतिम मुक्ति है; यह अस्तित्व के उच्चतर क्षेत्र में आरोहण है जहाँ आत्मा पूर्ण स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव कर सकती है क्योंकि एक प्रबुद्ध आत्मा स्वर्ण युग में पुनर्जन्म लेती है जहाँ उसे असामयिक या दर्दनाक मृत्यु नहीं झेलनी पड़ती। तो, मृत्यु के भय से कैसे उबरा जाए? इसके लिए, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे भय का मूल कारण जो हमें पाप और पीड़ा की ओर ले जाता है, वह शरीर की चेतना और आसक्ति है। इसलिए यह जागरूकता कि हम शाश्वत आत्मा हैं, मृत्यु के भय पर विजय पाने की कुंजी है।

अमरता हमारे शाश्वत होने और शरीर पर महारत हासिल करने की जागरूकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा एक ही शरीर में रहेंगे, नहीं। आध्यात्मिक रूप से सशक्त आत्मा शरीर में रहते हुए आत्म चेतना का अभ्यास करके अमर हो जाती है।

दूसरी ओर, पापी आत्माओं के लिए जीवन ही एक जीवित मृत्यु है क्योंकि वे हर दिन भय, पश्चाताप और पीड़ा से मरते हैं लेकिन जो लोग जीवित मरते हैं यानी जो सांसारिक मामलों से कोई लगाव नहीं रखते हुए दुनिया में रहते हैं, वे वास्तव में जीवन में भी मुक्त होते हैं।

आप की बात

बांग्लादेश में हिन्दू संकट में

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं को निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना की भारत समर्थक सरकार के अपदस्थ होने के बाद तो यह होना ही था। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत सरकार का अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति रिकार्ड बेदाग है। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि जहां पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू व अन्य गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों की संख्या में भारी कमी आई है, वहीं भारत में मुस्लिम तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी है और वे जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहे हैं। बांग्लादेश को अपनी बहुलतावादी विरासत का संरक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके सभी नागरिकों को सुरक्षा और सम्मान मिले, भले ही उनका विश्वास चाहे जो हो। केवल ऐसा कर ही बांग्लादेश अपना स्थायित्व सुनिश्चित करने के साथ ही निरंतर अंतरराष्ट्रीय सम्मान का भागीदार बन सकता है। यूनूस सरकार वस्तुत: आर्थिक कुप्रबंधन तथा राजनीतिक अस्थिरता से ध्यान हटाने के लिए अल्पसंख्यकों पर निशाना लगा रही है। हालांकि, नई दिल्ली ने अक्सर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में चिन्ता प्रकट की है, पर उसे तनाव बढ़ने से बचने के लिए सावधानी से आगे बढ़कर कदम उठाने होंगे।

– **सुनीत रस्तोगी**, मेरठ

जम्मू-कश्मीर के हालात

कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों की लहर ने, नई राज्य सरकार के गठन के बाद, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर चिंताओं को फिर से जगा दिया है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और क्षेत्र को स्थिर करने के केंद्र सरकार के प्रयासों के बावजूद, जम्मू और कश्मीर अस्थिर बना हुआ है। दूसरे, जम्मू के विशाल वन क्षेत्र आतंकवादियों के लिए एक आश्रय स्थल बन गए हैं, जो गुरिल्ला युद्ध के लिए प्राकृतिक कवर प्रदान करते हैं और सुरक्षा बलों को बाधित करते हैं। तीसरे, कश्मीर में बेहतर कानून और व्यवस्था ने उग्रवादियों का ध्यान जम्मू की ओर स्थानांतरित कर दिया है, जहाँ कमजोरियों का फायदा उठाया जा रहा है। चौथा, जबकि आतंकवादी गतिविधियां अस्थायी रूप से कम हो गई थीं, उग्रवाद का फिर से उभरना गहरी जड़ें जमाए हुए खतरों की निरंतरता को रेखांकित करता है। आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में रोमांटिक बनाने वाली कहानियों को खारिज करना और इन नेटवर्क को खत्म करने के लिए स्थानीय समुदायों और कानून प्रवर्तन के बीच सहयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। भारत सरकार को हर हाल में आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना होगा तथा जम्मू-कश्मीर की नई सरकार को केंद्र के साथ सहयोग स्थापित करके चलना होगा।

– **नीरजा शर्मा**, गाजियाबाद

दिल्ली की जहरीली हवा

पंजाब और हरियाणा सहित पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की वार्षिक कृषि प्रथा दिल्ली की धुंध में योगदान करती है। वायु गुणवत्ता संकट में इसका कायम रहना एक महत्वपूर्ण कारक बना हुआ है। सर्दियों के दौरान, दिल्ली का ठंडा तापमान और तेज हवाओं की कमी प्रदूषकों को जमीन के करीब फंसा देती है इस आवर्ती समस्या से निपटने के प्रयास में, वायु गुणवत्ता में 'बहुत खराब' श्रेणी में गिरावट के बाद, 21 अक्टूबर से दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू किया गया। इस योजना में निर्माण और औद्योगिक संचालन जैसी प्रदूषण में योगदान देने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। हालांकि, ग्राप-2 के क्रियान्वयन के बावजूद, वायु गुणवत्ता सूचकांक चिंताजनक रूप से उच्च बना हुआ है, जो शहर की लगातार वायु गुणवत्ता समस्याओं को दूर करने के लिए सख्त प्रवर्तन और संभवत: अधिक मजबूत समाधानों की आवश्यकता को दर्शाता है। दीवाली के बाद दिल्ली का प्रदूषण संकट वायु गुणवत्ता प्रबंधन की जटिल और बहुआयामी प्रकृति की याद दिलाता है। ग्राप और जन जागरूकता अभियानों जैसी पहलों के माध्यम से प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों को सीमित सफलता मिली है।

– **संदीप गर्ग**, नई दिल्ली

बढ़ती आबादी की चुनौती

बढ़ती आबादी के कारण महानगरों का शहरी बुनियादी ढांचा भारी दबाव में है। शहरी बुनियादी ढांचे के तत्काल पुनर्गठन, रेट्रोफिटिंग और नवीनीकरण के लिए मजबूत शहरी शासन आवश्यक है। राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों से लेकर वित्तीय और बुनियादी ढांचे के मुद्दों और इससे भी महत्वपूर्ण, सामाजिक-पर्यावरणीय मुद्दों तक, महानगरीय प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान संस्थागत संरचना को सार्वजनिक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए योजना और विकास एजेंसियों जैसे अधिकारियों द्वारा फिर से तैयार किया जाना चाहिए। पारास्टेटल प्रशासनिक निकायों और सार्वजनिक झुंझलाहट के बीच संघर्ष अक्सर इन एजेंसियों के प्रसार और उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के धुंधले होने के कारण बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश के शहरीकरण के बावजूद, राज्य में निश्चित रूप से बड़ी शहरी आबादी है। इस महानगरीय आबादी को अनियंत्रित और अव्यवस्थित विकास पैटर्न में प्रबंधित करने की चुनौती है।

– **विनय कुमार**, कानपुर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
ज्ञान और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं

त्वरित न्याय की आस

तीन नए आपराधिक कानूनों का पूर्ण अनुपालन करने वाले चंडीगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने इन कानूनों के माध्यम से त्वरित न्याय हासिल होने की जो उम्मीद जताई, वह पूरी होनी ही चाहिए। इससे ही इन तीनों कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सार्थकता सिद्ध होगी। पूरे देश में इन तीनों कानूनों पर इसी जुलाई से अमल शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ उनका अनुपालन करने में सबसे आगे रहा। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चंडीगढ़ से न केवल प्रेरणा लेनी चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कानूनों के जरिये लोगों को समय पर न्याय मिले। अभी तो तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम है और इसके चलते निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यदि तीनों आपराधिक कानूनों को अमल में लाकर त्वरित न्याय के सपने को साकार किया जा सके तो यह विश्व का सबसे बड़ा सुधार तो होगा ही, स्वतंत्र भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पुराने आपराधिक कानून अंग्रेजों ने बनाए थे और उनका निर्माण भारत को गुलाम बनाए रखने के इरादे से किया गया था। यह ठीक है कि समय के साथ उनमें कुछ संशोधन-परिवर्तन किए गए, लेकिन वे औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके। विडंबना यह रही कि पिछली सरकारों ने न तो अंग्रेजों के बनाए कानूनों से मुक्ति पाने की कोई पहल की और न ही न्याय में देरी को दूर करने के उपाय किए।

न्याय में देरी केवल लोगों को हताश-निराश ही नहीं करती, बल्कि किसी न किसी स्तर पर देश के विकास की गति को भी बाधित करती है। इसके अतिरिक्त देश की छवि को भी खराब करने का काम करती है। जब समय पर न्याय नहीं मिलता तो कानून एवं व्यवस्था का आदर न करने और उसके उल्लंघन के आदी लोगों का दुस्साहस बढ़ता है। तीनों आपराधिक कानूनों पर अमल से एक ओर जहां 60 दिन के अंदर आरोप तय किए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर सुनवाई पूरी होने के 45 दिन के अंदर फैसला सुनाना आवश्यक होगा। यह शुभ संकेत है कि तीनों आपराधिक कानूनों पर अमल के बाद से कई मामलों में सचमुच समय पर न्याय हुआ है, जैसे कि चंडीगढ़ में वाहन चोरी में मामला दर्ज होने के 75 दिन के अंदर अदालत ने सजा सुना दी। इसी तरह अशांति फैलाने के एक मामले में 20 दिन में सुनवाई करके सजा सुना दी गई। दिल्ली में भी एक मामले में एफआइआर दर्ज होने के 60 दिन के अंदर फैसला आ गया। ऐसा देश भर में सभी मामलों में होना चाहिए। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निचली अदालतों के जिन फैसलों को ऊंची अदालतों में चुनौती दी जाए, वहां भी उनका निस्तारण आनन-फानन हो।

बिहार में 'विहार'

बिहार सरकार पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों को पर्यटन नीति की जानकारी देने और अधिक से अधिक निवेश प्राप्त करने के लिए जल्द ही प्रमंडल स्तर पर कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। यह कार्यशाला पर्यटन क्षेत्र से जुड़े होटलों, रेस्टोरेंट एवं अन्य व्यवसायी समूहों के साथ होगी। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 30 प्रतिशत का सीधा पूंजीगत अनुदान देगी। बिहार में 'बिहार' की ऐसी पहल सराहनीय है, नाम के मायने सार्थक होने की उम्मीद जगाने वाली। बिहार में सदियों पहले लोग ज्ञानार्जन और प्रकृति के साक्षात्कार को आते थे। विक्रमशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, मंदार, राजगीर, बोधगया जैसे पर्यटन स्थल गवाह हैं। ये तो वे प्रमुख स्थल हैं जो ख्याति प्राप्त हैं। राज्य के हर प्रखंड में एक से एक शानदार स्थल हैं, यहां पर्यटन की अपार संभावाएं हैं। इन संभावनाओं को तभी भुनाया जा सकता है, जब इन्हें विकसित किया जाए। वहां तक बेहतर कनेक्टिविटी मिले। रुकने, खाने-पीने के साथ पर्यटक यह जरूर देखते हैं कि वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं। यहां काम किए जाने की जरूरत है और यहीं रोजगार की संभावनाओं के द्वार भी खुलते हैं। पर्यटन मित्रों को हर प्रमुख प्रखंड में नियुक्ति, टूर गाइड, आवासन की व्यवस्था के लिए होम स्टे और होटल, घूमने के लिए वाहन जैसे क्षेत्र हैं, जहां लाखों लोगों की आय का सृजन किया जा सकता है। जाहिर है, इससे पलायन भी रुकेगा। इस सकारात्मक पहल में राज्य को केंद्र का भी साथ मिलता दिख रहा है। सहरसा में मल्स्यगंधा झील पर ग्लास ब्रिज बनाने और इसे वैश्विक स्तर का पर्यटन केंद्र बनाने के लिए 97.61 करोड़ रुपये का उपबंध इसी की कड़ी है।

पर्यटन के नक्शे पर राज्य को उभारने की पहल सराहनीय है, इसके बेहतर परिणाम होंगे

कठिन होता जलवायु परिवर्तन से बचना

शिवकांत शर्मा

विकसित देश स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के लिए 1300 के बजाय मात्र 300 अरब डालर देने को राजी हुए और वह भी 2035 से। यह ऊंट के मुंह में जीरा है

अवधेश राजपूत

विश्व मौसम विज्ञान के अनुसार इस वर्ष वायुमंडल का औसत तापमान औद्योगीकरण से पूर्व के तापमान से 1.54 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है। तापमान वृद्धि के कारणों की जांच कर उसकी रोकथाम के लिए बने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के जलवायु सम्मेलन 1996 से होते आ रहे हैं। 2015 के पेरिस सम्मेलन में तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रोकने के हरसंभव उपाय करने पर सहमति हुई थी। विज्ञानियों ने चेतावनी दी थी कि यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश नहीं लगा तो 2028 तक तापमान 1.5 डिग्री पार कर जाएगा, जिसके बाद सूखे, बाढ़ और तूफान जैसी आपदाओं से निपटने एवं तापमान वृद्धि की रोकथाम और कठिन हो जाएगी। सदस्य देशों ने अपनी-अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के प्रयास किए, मगर तापमान वृद्धि की गति बता रही है कि वे पर्याप्त नहीं रहे हैं।

अजरबैजान की राजधानी बाकू में हाल में संपन्न हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में कैलन दी उल्लेखनीय समझौते ही हो पाए। पहला कार्बन क्रेडिट स्कीम पर, जो लगभग दस साल से लंबित था। दूसरा जलवायु परिवर्तन की रोकथाम लिए वित्तीय सहायता पर। वह भी इस भय के कारण कि अमेरिका की बागडोर ट्रंप के हाथों में जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन को महत्व नहीं देते। इसमें विकासोन्मुख देश चाहते थे कि तापमान को वर्तमान स्तर तक लाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले विकसित देश स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के लिए उन्हें कम से कम 1300 अरब डालर सालाना की वित्तीय सहायता देना शुरू करें, लेकिन धनी देश रो-पीट कर मात्र 300 अरब डालर सालाना देने को तैयार हुए और वह भी 2035 से। धनी देशों का कहना है कि प्रस्तावित राशि मौजूदा 100 अरब डालर से तिगुनी है, इसलिए विकासशील देशों को नाराज होने की जगह खुश होना चाहिए, मगर विकासशील देशों का कहना है कि यह जरूरत के एक चौथाई के बराबर भी नहीं है। इसीलिए भारत की प्रतिनिधि चांदनी रैना ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता एक मुगन्हाणा से अधिक कुछ नहीं है। इससे इस गंभीर चुनौती का सामना करने में खास मदद नहीं मिलेगी। विकासशील और छोटे गरीब देशों ने इस सम्मेलन की कड़ी आलोचना की।

जलवायु सम्मेलनों में हर साल होने वाले समझौतों और बड़े-बड़े वादों के बावजूद निरंतर बढ़ता तापमान दिखा रहा है कि या तो अब तक किए जा रहे उपाय नाकाफी रहे हैं या उन्हें ईमानदारी से लागू नहीं किया जा रहा। स्टैनफोर्ड में पढ़ाने वाले आर्थिक इतिहासकार वाल्टर शैडेल की प्रसिद्ध पुस्तक 'द ग्रेट लैवलर' के अनुसार मानव इतिहास में असली परिवर्तन हमेशा महाविनाश की वजह से हुए हैं। निरंतर महाविनाश की ओर ले जा रहे जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए ठोस उपाय करने की जगह हर साल की अंतहीन सौदेबाजी शीडेल की बात को सही साबित करती है, पर इससे भी इन्कार नहीं कि जैसी विश्वव्यापी सहमति जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए बनी है, वैसी और किसी मुद्दे पर कभी नहीं बनी। इसीलिए बिल गेट्स का मानना है कि हम एक ऐसी युगसंधि पर पहुंच गए हैं, जो इतिहास बदलेगी। नई और स्वच्छ तकनीक का विकास जलवायु परिवर्तन से होने वाले महाविनाश से बचा ले जाएगा।

धूप, हवा, पानी और परमाणु से पैदा की जाने वाली स्वच्छ ऊर्जा की लागत में तेजी से आ रही गिरावट और उससे चलने और कम ऊर्जा खपत वाले वाहनों और मशीनों के विकास को देखकर बिल गेट्स की बातों पर भरोसा होता है, पर जैव ईंधनों से चलने वाले वाहनों, कारखानों, बिजलीघरों को स्वच्छ ऊर्जा वाली व्यवस्था में बदलने के लिए जिस 11,000 अरब डालर के निवेश की जरूरत है, वह कहां से और कैसे आएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। बाकू में 300 अरब डालर सालाना मदद देने का वादा 2035 से किया गया है। क्या तब तक तापमान थमा रहेगा? विकसित देशों ने विकासशील देशों के आयात पर कार्बन शुल्क भी लगाने शुरू कर दिए हैं। यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से भारत जैसे देशों के निर्यातकों की लागत बढ़ जाएगी। इसलिए विकसित देशों को तापमान बढ़ाने में उनकी भूमिका याद दिलाते हुए वित्तीय सहायता का दबाव बनाए रखने के साथ-साथ विकासशील देशों को चीन की तरह जलवायु की रक्षा के कारगर उपाय स्वयं ही करने होंगे। सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक बन जाने के साथ-साथ चीन स्वच्छ ऊर्जा और उस पर आधारित तकनीक का भी सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है। विकसित देशों का मुंह बंद रखने के लिए उसने वित्तीय सहायता में भी योगदान की पहल की है। तापमान बढ़ाने वाली एक तिहाई गैसें भोजन के उत्पादन, प्रसंस्करण और सप्लाई से जुड़े उद्योगों से पैदा हो रही हैं, जिनकी रोकथाम पर गंभीर चर्चा तक नहीं हो रही। विश्व के 15 प्रतिशत जैव ईंधन की खपत खेती और उसके लिए जरूरी खाद और कीटनाशकों के उत्पादन में होती है। पालतू मवेशियों द्वारा उत्सर्जित मीथेन गैस का भी तापमान बढ़ाने में बड़ा योगदान है। भोजन के प्रसंस्करण, शंतलन, पैकिंग और सप्लाई के उद्योग भी जैव ईंधनों से चलते हैं। खेती को स्वच्छ ऊर्जा से चलाकर और आयातित की जगह ताजा एवं मौसमी भोजन और मांस की जगह शाकाहार को बढ़ावा देकर तापमान बढ़ाने वाली लगभग एक तिहाई गैसों की रोकथाम की जा सकती है, लेकिन विकसित से लेकर विकासशील देशों में किसान और भोजन उद्योग इतने संगठित हैं कि उन पर इतने बड़े परिवर्तनों का दबाव डालने की इच्छाशक्ति किसी सरकार में नहीं।

पूरे उत्तरी भारत के हर साल तेजाबी धुंध की चादर से ढक जाने के बावजूद न चुनाव में यह प्रमुख मुद्दा बनता है और न संसद में इस पर कोई सार्थक चर्चा होती है। 1950 के आसपास लंदन का वायु गुणवत्ता सूचकांक या एक्यूआइ दिल्ली से भी खराब हुआ करता था। आज दिल्ली से कई गुना जीडीपी देने के बावजूद लंदन का एक्यूआइ औसतन 20 रहता है और दिल्ली का 150 जो अक्टूबर में 400 के पार चला जाता है। 2013 में बीजिंग का एक्यूआइ 600 और सिंगापुर का 400 पार कर गया था। आज दोनों का एक्यूआइ दिल्ली से बहुत कम है। लोग कमर कस लें तो क्या नहीं हो सकता?

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

पटरी पर आई महाराष्ट्र की राजनीति

अवधेश कुमार

विचारधारा ही शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के भाजपा के साथ बने रहने की गारंटी होगी

महाराष्ट्र के राज्यपाल संग महायुति के नेता। एएनआइ

देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का रास्ता साफ होते ही महाराष्ट्र की राजनीति स्थिर आयाम तक पहुंच गई। विधानसभा चुनाव परिणाम का स्वाभाविक राजनीतिक फलितार्थ यही हो सकता था कि फडणवीस मुख्यमंत्री बनें। 2014 से उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र की राजनीति के जिस दौर की शुरुआत हुई, उस पर 2019 में ग्रहण लगने का कोई स्वाभाविक कारण नहीं था। भाजपा और शिवसेना दोनों को मिलाकर जनता ने 161 सीटों का बहुमत दिया था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। यहां से महाराष्ट्र की राजनीति अस्वाभाविक, अनैतिक और अस्थिरता के ऐसे दौर में उलझी कि राजनीतिक विचारधारा का सबसे बड़ा संघर्ष कायम हुआ। हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना ने सत्ता के लिए जिस तरह रंग बदला, उसे जनता की स्थायी स्वीकृति मिलना 2014 से भारत में आरंभ हुई राजनीति के दौर के बीच असाधारण घटना होती। आखिरकार हाल के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति स्वाभाविक विचारधारा की पटरी पर आ गई।

एक तरह से जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के अंदर हुए विद्रोह ने ही संदिग्ध दे दिया था कि अस्वाभाविक वैचारिकता को बड़ा वर्ग स्वीकार करने को तैयार नहीं। जब अजीत पवार के नेतृत्व में राकांपा भी भाजपा के साथ आ गई तो साफ हो गया कि महाराष्ट्र के सत्ता समीकरण में कांग्रेस को छोड़कर किसी दल के अंदर सहजता नहीं थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के प्रभावी प्रदर्शन ने फिर से स्वाभाविक राजनीति पर ग्रहण लगाया, लेकिन माना यही गया कि यह भी एक अस्थायी परिघटना है। लोकसभा चुनाव में कई कारकों ने महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश और इससे कम परिमाण में कुछ दूसरे राज्यों में अपनी भूमिका निभाई, जिससे भाजपा के नेतृत्व में राजग की सीटें कम हुईं। लगता है कि स्वयं मतदाताओं ने भी समझा कि उनसे गलती हो गई है। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में मतदाताओं ने अनुकूल परिस्थितियों एवं समीकरणों की सहजता को देखते हुए जनादेश दिया।

चुनाव परिणाम के बाद सरकार गठन में लगभग दो सप्ताह का समय इसी कारण लगा, क्योंकि फडणवीस को नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए शिंदे को तैयार करना था या कहें कि उन्हें तैयार होना था। चुनाव परिणाम से इतना तो स्पष्ट था कि शिंदे के विद्रोह को शिवसैनिकों ने स्वीकार किया। उन्होंने इतने प्रभावी परिवार से पार्टी को अलग कर उसे विचारधारा की स्वाभाविक पटरी पर लाने की अकल्पनीय भूमिका निभाई। जून 2022 में भाजपा नेतृत्व के सामने सरकार की स्थिरता और सुदृढ़ता के लिए आवश्यक था कि शिंदे को नेतृत्व दिया जाए। भाजपा नेतृत्व ने उन्हें स्थायी रूप से मुख्यमंत्री बनाने का कोई वचन दिया होता तो वह अवश्य इसकी चर्चा करते।

निश्चित रूप से शिंदे के समर्थकों का एक वर्ग फिर से उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता होगा, लेकिन ऐसा होना महाराष्ट्र की राजनीति के फिर से अस्थिर होने का कारण बन जाता। शिंदे को भी जन्मतिथिक्रम का आभास हो गया होगा कि उद्धव ठाकरे के विरुद्ध विद्रोह से निर्मित सशक्त नेता की उनकी छवि सरकार गठन में बाधा बनने से कमजोर होगी। ध्यान रहे कि दूसरे साझेदार अजीत पवार के साथ भाजपा को बहुमत मिल गया था और इस कारण शिंदे की अपरिहार्यता नहीं रह गई थी। यह सतह पर दिखने वाला एक पहलू है। भाजपा नेतृत्व को पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उनके लिए शिंदे की शिवसेना के साथ विचारधारा के आधार पर दीर्घकालिक काम करना आवश्यक है। दूसरी ओर, अजीत पवार ने परिपक्वता दिखाई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने दूरगामी सोच के साथ अपनी पार्टी और दोनों साझेदारों को किसी स्तर पर असंतुष्ट और नाराज होने का अवसर नहीं दिया। सोच की भी प्रभावी सक्रियता रही। यही कारण था कि सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में हल्के-फुल्के मतभेद होते हुए भी तीनों दल और प्रमुख नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ते रहे। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि एकनाथ शिंदे जब उद्धव ठाकरे से विद्रोह कर बाहर आए थे तो उन्हें भी भान नहीं था कि भाजपा उनके हाथों सरकार का नेतृत्व सौंप देगी, क्योंकि भाजपा के पास विधानसभा में 105 सीटें थीं।

यह स्पष्ट है कि देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक जीवन के नए दौर की शुरुआत हो रही है। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने अपने भाषण में हिंदवी स्वराज से लेकर अहिल्याबाई होलकर का नाम लेकर अपनी राजनीतिक धारा को बिल्कुल स्पष्ट किया। चुनाव प्रचार के दौरान भी उनकी छवि आत्मविश्वास से भरे हिंदुत्ववादी शुद्ध स्वयंसेवक भाजपा नेता की बनी। उन्होंने कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं और उनको समर्थन देने वाले महाविकास आघाड़ी के विरुद्ध लगातार प्रखर प्रहार से अपनी छवि वर्तमान राजनीतिक धारा के अनुरूप बनाई। चुनाव के समय लगा था कि एक हैं तो सेफ हैं और बंटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर महायुति में मतभेद हैं। जब अजीत पवार ने बंटेंगे तो कटेंगे नारे के विरुद्ध बयान दिया था, तो फडणवीस ने स्पष्ट कहा था कि योगी जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला। अजीत पवार बहुत बाद में गठबंधन से जुड़े और धीरे-धीरे उन्हें भी समझ में आ जाएगा। यह सरकार गठन के पूर्व भावी नीतियों को लेकर छीषणा थी यानी गठबंधन का कोई दबाव संघ तथा भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे में बाधा नहीं बनेगा। यही विचारधारा शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के भाजपा के साथ बने रहने की गारंटी होगी।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मौन का महत्व

मनुष्य की चुप्पी आत्मचिंतन और अंतर्द्वंद्व का भी संकेत है। जब जीवन के बवंडर और भावनाओं की बाढ़ हमें घेर लेती है, तब मन मौन की शरण चाहता है। वह मौन जो केवल बाहरी संसार से नहीं, बल्कि आत्मा की अंतर्निहित गूंज से भी दूरी बना ले। यह मौन आत्म-चेतना और आत्म-साक्षात्कार का क्षण है, जब हम अपने अंतरात्मा की धीमी फुसफुसाहटों को भी सुनने का प्रयत्न करते हैं। शब्दों की निर्जीवता से मुक्त होकर अपने विचारों और भावनाओं में डूबना चाहते हैं, जहां केवल आत्मा का साक्षात एवं पूर्ण साक्षात्कार हो। ऐसे क्षणों में मन की गहराइयों में उतरने की तीव्र इच्छा होती है, जहां हमें अपने विचारों और भावनाओं का सही रूप दिखाई दे सके। इस चुप्पी में वह शक्ति छिपी है, जो हमें हमारी वास्तविक पहचान एवं क्षमताओं से परिचित कराती है। यह एक ऐसा क्षण है, जब व्यक्ति संसार के कोलाहल से अलग होकर अपने भीतर की गहराइयों में झांकना चाहता है।

मौन नकारात्मकता का प्रतीक न होकर आत्म-विवेचना और आत्म-निरीक्षण की अवस्था है, जब मनुष्य स्वयं को इतना शांत बना लेता है कि उसका अंतःकरण भी उसकी उपस्थिति को महसूस न कर सके। आत्मविस्मरण के इस क्षण में मनुष्य का अस्तित्व उसकी चेतना की सीमाओं से परे चला जाता है। तभी वह अपने अस्तित्व के वास्तविक एवं अव्यक्त पहलुओं से परिचित होता है। यह चुप्पी इतनी गहन होती है कि शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। विचार और भावनाएं जैसे घुल-मिलकर मौन के समुद्र में विलीन हो जाते हैं। इस मौन में व्यक्ति अपने आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करता है, जहां शब्द असमर्थ हो जाते हैं, केवल अनुभूतियां शेष रह जाती हैं। यह मौन व्यक्ति को उसकी पहचान, अंतरिक शांति के सूत्रों व उसकी आध्यात्मिक गहराइयों के मार्ग की ओर प्रशस्त करता है।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

प्रदूषण से बढ़ता कैंसर का जोखिम

सुनीति मिश्रा

वायु प्रदूषण के कई दुष्प्रभावों में कैंसर सर्वाधिक खतरनाक है, जिस पर नियंत्रण आवश्यक है

भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में 22 प्रतिशत हिस्सा कैंसर का है। हाल ही में 'द लांसेट' में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि यह आंकड़ा पिछले एक दशक में तीगुना हो गया है। विशेष चिंता की बात यह कि इनमें युवा आबादी का प्रतिशत बढ़ रहा है। कैंसर के मामलों में तेजी से वृद्धि के कई बड़े कारण हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जीवनशैली में बदलाव मुख्य रूप से जिम्मेदार है। वर्तमान में कैंसर का एक प्रमुख कारण प्रदूषण भी है। वस्तुतः आज वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण अपने चरम पर है जिसकी वजह से कैंसर रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।

उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के कारण बढ़ते कैंसर के मामलों ने चिकित्सा जगत में चिंता पैदा कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली लगातार तीसरे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है, जहां पी.एम. 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 20 गुना अधिक है। ये आंकड़े करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी एक भयावह वास्तविकता हैं। कैंसर विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में फेफड़ों के कैंसर के मामलों में 45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिनमें से 37 प्रतिशत मरीज ऐसे हैं जो कभी धूमपान नहीं करते थे। एम्स द्वारा वर्ष 2023 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि दिल्ली में प्रतिवर्ष लगभग 80 हजार लोग वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से प्रभावित होते हैं।

वस्तुतः पराली दहन उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के एक नए कारक के रूप में उभर कर सामने आया है। एम्स और आइआइटी दिल्ली द्वारा 2023 में किए गए एक संयुक्त अध्ययन में यह पाया गया कि पराली के धुएं में बेंजीन, फार्मल्डिहाइड और पालीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कैंसरकारी तत्व मौजूद होते हैं। इन तत्वों की मात्रा सामान्य दिनों की तुलना में पराली जलाने के मौसम में छह गुना तक बढ़ जाती है।

वायु प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए कैंसर के कारकों का समाधान किए जाने पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में सरकार को पराली से होने वाले वायु प्रदूषण के कारकों के निवारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि उसे उत्पन्न कैंसर की भयावहता को रोका जा सके।

हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, ग्रीन कवर में वृद्धि और औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी निगरानी आदि इनमें शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर, वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, शराब और तंबाकू से परहेज और स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर कैंसर के मामलों से बचा जा सकता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

राजनीति से मुक्त हो इतिहास लेखन

'इतिहास के मिथ्याकरण का रोग' शीर्षक से लिखे आलेख में शंकर शरण ने इतिहास शिक्षा को लेकर शिक्षकों को सतर्क रहने की सीख दी है। उन्होंने स्पष्ट लिखा कि शिक्षक किसी ऐतिहासिक पुरुष की निंदा या प्रशंसा करने से बचें, क्योंकि हमारे इतिहास लेखन में राजनीतिक लाभ-हानि का ध्यान रखा गया और वास्तविक तथ्यों को नजरअंदाज किया गया। इसका पूरा दोष नीतिकारों एवं राजनीतिज्ञों को जाता है कि उन्होंने ऐसे विकृत इतिहास लेखन पर जोर दिया, जिसमें सभी समाजों, महापुरुषों एवं क्षेत्रों को सम्यक स्थान नहीं मिला। लिहाजा तथ्यों के अन्वेषण के माध्यम से इतिहास की पाठ्यपुस्तकों की नए सिरे से रचना की जरूरत है। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, मगर उसके अनुरूप अभी तक पाठ्यपुस्तकों का निर्माण संभव नहीं हो सका है। अध्यापकों के लिए पाठ्यपुस्तक मार्गदर्शन का काम करती हैं। पाठ्यपुस्तकों के जरिए ही उन सीमाओं का निर्धारण होता है कि उन्हें किसे विषयवस्तु को लेकर कहां तक जाना है? लिहाजा लेखक के उद्देश्य में सफलता तभी मिल सकती है, जब प्रमाणिक पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी एवं शिक्षकों के समक्ष मौजूद हों, जिसका लेखन राजनीति से मुक्त होकर ही संभव है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

साइबर अपराध से हो बचाव

केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़ी एजेंसी सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्राड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार पिछले महीने तक साइबर ठगी के चलते आमजन को 11,333 करोड़ रुपये की चपत लग चुकी है। लगातार हो रहे साइबर अपराध से लोग विचलित हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट के भी काफी मामले सामने आ रहे हैं। गाढ़ी कमाई को ठग उड़ा ले जा रहे हैं। देशभर में धड़ल्ले से हो रहे साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने साइबर फ्राइम कोआर्डिनेशन सेंटर एवं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की स्थापना कर सही कार्य किया है। रोजाना हो रहे डिजिटल अरेस्ट एवं अन्य ठगी को रोकने के लिए मोटी सरकार को और अधिक कठोर कानून लागू करने चाहिए। मोबाइल फोन पर आने वाली काल पर सतर्क रहते हुए जवाब देना चाहिए। मोबाइल पर आए लिंक को क्लिक करने से पहले पूरी तरह आश्वस्त होना जरूरी है। सबसे आश्वयक यह है कि हम किसी लोभ में न फंसे।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद, हरियाणा

नए कानून से मिलेगा त्वरित न्याय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 1860 से अंग्रेजों के बनाए कानून में परिवर्तन कर बढ़ते अपराधों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संशोधन कर नए कानून को पहली जुलाई 2024 से लागू किया गया। संशोधित कानून के अनुसार अब दी बार से अधिक स्टे आर्डर नहीं मिलेगा। इस तरह नए कानून के लागू होने से अपराधियों पर जल्दी से शिकंजा कसा जा सकेगा।

मीना धानिया, दिल्ली

स्थानीय नायकों के प्रति उदासीन इतिहास

इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं है, बल्कि यह सभ्यता के विकास, समाजिक मूल्य और विचारधारा का भी जीवंत दस्तावेज होता है। जब इसे तोड़ा-मरोड़ा जाता है तो यह न केवल अतीत के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलता है, बल्कि भविष्य की दिशा को भी विकृत करता है। इतिहास का मिथ्याकरण एक ऐसी समस्या है, जो न केवल सत्य की हत्या करता है बल्कि समाज में लोगों के बीच अविश्वास और भ्रम की स्थिति को भी पैदा करता है। हमारे देश में ऐतिहासिक तथ्य को अक्सर राजनीतिक उद्देश्य, संप्रदायिक ध्रुवीकरण और वैचारिक दुष्प्रचार के लिए हथियार बनाया गया। इससे निपटने के लिए इतिहास की लेखन को निष्पक्ष, वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित करने की आवश्यकता है। प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन कर स्थानीय नायकों की भूमिका को उजागर करना होगा, ताकि लोगों को अपनी संस्कृतिक जड़ों से जोड़कर एक व्यापक दृष्टिकोण निर्मित की जा सके।

अवनीश कुमार गुप्ता, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संपादक-सह, पूर्वांचल गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-सह, नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-वीरेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

10 वें पायदान पर रखा गया है भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग, विशेषज्ञ संख्या और शोध प्रकाशनों पर आधारित 73 देशों की वैश्विक रैंकिंग में, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार।

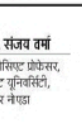

डा. संजय वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा

आजकल

एआइ की बादशाहत में भारत की दस्तक

हमारे देश में एआइ के योगदान को देखते हुए कंप्यूटर, आइटी और इंजीनियरिंग के अलावा भी तमाम क्षेत्रों में उसमें विशेषज्ञता हासिल करने की होड़ मची हुई है। इसका परिणाम फिलहाल यह निकला है कि एआइ विशेषज्ञों की संख्या में भारत ने वैश्विक स्तर पर दूसरा और शोध प्रकाशन (रिसर्च पब्लिकेशन) के क्षेत्र में तीसरा स्थान हासिल किया है। लेकिन क्या यह शुरुआती उपलब्धि रोजगारों, उद्योग जगत की चुनौतियों एवं नवाचारों के क्षेत्र में इतना उत्साह भर सकती है कि वह हमारे देश को लाभ की स्थिति में पहुंचा सके...

प्रतीकात्मक

शिक्षा क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिहाज से आजकल हमारे देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- एआइ) के भविष्य को लेकर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। थोड़ा पीछे चलें तो पता चलता है कि बीसवीं सदी के अंतिम दशक में जब पूरी दुनिया में कंप्यूटर क्रांति हो रही थी, भारत उस बदलाव से कदमताल करते हुए दुविधा भरे एक माहौल में फंसा हुआ था। एक तरफ कंप्यूटर साइंस और आइटी में पढ़-लिखकर नए वैश्विक अवसरों की तलाश में निकली हुई युवा पीढ़ी थी जो इस क्रांति में स्वयं को अग्रणी साबित करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ देश के भीतर कंप्यूटरों का विरोध यह कहकर किया जा रहा था कि यह क्रांति हमारे रोजगारों के लिए काल बन जाएगी। हालिया अतीत बताता कि उस आइटी क्रांति के महत्व को समझने वाली हमारी युवा पीढ़ी ने क्या कमाल किया है। नौकरियों पर ग्रहण लगने के बजाय उनमें बढ़ोतरी हुई और आइटी तकनीक की दुनिया में भारत का सिक्का सिर चढ़कर बोलने लगा। कुछ वैसे ही बदलाव इधर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर हुए हैं।

सबसे उल्लेखनीय यह है कि इस बार माहौल में दुविधा नहीं है। बीते दो वर्षों में जब से ओपनएआइ द्वारा जेनरेटिव एआइ का एक बेजोड़ माडल चैटजीपीटी के रूप में दुनिया के सामने रखा गया और उसके जैसे कई और माडल सामने आए, तो हमेशा की तरह मानव सभ्यता के खतरे में पड़ जाने की आशंकाएं सामने आ खड़ी हुईं। इसे लेकर काफी कुछ कहा-सुना गया कि जिस दिमागी ताकत (बुद्धि) के बल पर इंसान ने इस जीव जगत पर अपनी बादशाहत कायम की है, वह अगर मशीनों के पास चली जाएगी, तो इंसान का क्या होगा। इन आशंकाओं का उत्कर्ष इसमें दिख रहा है कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि मशीनें हर चीज से इंसानों को बेदखल कर दें और दुनिया में केवल उनका ही राज चलने लगे। मशीनों के जड़ से चेतन हो जाने का जो करिश्मा एआइ की बदौलत हमारी आंखों के सामने साकार हो रहा है, उसे लेकर भयभीत करने के किस्सों की भरमार है। ये किस्से हकीकत में कितना बदलेंगे, यह कोई नहीं जानता, लेकिन भावी अनहोनियों से डरे बिना जो देश एआइ को अपनी ताकत के टूल में बदलना चाहते हैं, भारत उनमें से एक है। इसी का नतीजा है कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट में दिखता है।

वैश्विक सूची के पहले दस देशों में भारत : बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एआइ के उपयोग, विशेषज्ञ संख्या और शोध प्रकाशनों पर आधारित 73 देशों की ग्लोबल रैंकिंग में भारत पहले दस देशों की पायदान पर खड़ा है। एआइ विशेषज्ञों की संख्या में दूसरा और शोध प्रकाशनों के मामले में तीसरा देश होने का एक मतलब यह निकलता है कि भारत उन देशों की पांत में शामिल है जो एआइ को अपनाने के मामले में सबसे ज्यादा तैयार है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में एआइ से जुड़े पेटेंट हासिल करने की दर भी काफी अधिक है। इससे एआइ के जरिए यहां जिंदगी के हर क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावनाएं पैदा हो रही हैं। एआइ की इस तैयारी का आधार इसे लेकर देश के पारिस्थितिकी तंत्र की भागीदारी, कौशल और अनुसंधान और विकास पर तय होता है। बोस्टन ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले दुनिया की 70 प्रतिशत अर्थव्यवस्थाएं औसत से नीचे का स्कोर करती हैं। जबकि भारत में एआइ को लेकर काफी तैयारी है। इस तैयारी का मतलब यह है कि यहां सरकार और निजी क्षेत्र एआइ को लागू और एकीकृत करने की क्षमता दिखा रहे हैं।

मामला केवल बोस्टन रिपोर्ट तक सीमित नहीं है। इस साल मार्च में जब सरकार ने इंडियाएआइ मिशन के लिए 10,372 करोड़ रुपयों के खर्च का बजट निर्धारित किया, तो साफ हो गया था कि सरकार इस तकनीक को लेकर कितनी संजीदा है। यही नहीं, जुलाई में सरकार ने इस मिशन के लिए 551.75 करोड़ रुपये आवंटित भी कर दिए। वैसे इस इरादे की झलक पिछले साल 2023 में भारत में हो आयोजित जी-20 सम्मेलन और एआइ पर वार्षिक बैठकों में ही मिल गई थी कि देश में एआइ को लेकर कैसा है।

इन क्षेत्रों में मूरत बदलने का माद्दा : यहां सवाल है कि आखिर वे कौन-कौन से क्षेत्र हैं, जिनमें हमारा देश एआइ की मदद से बड़े बदलाव कर सकता है। वैसे, एक आम धारणा यह है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने सबसे बड़ा असर शिक्षा और फिल्म, मीडिया से संबंधित डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में डाला है। हालांकि इन दोनों ही क्षेत्रों में एआइ के नकारात्मक प्रभाव सबसे पहले सामने आए। जैसे, छात्रों को दिए जाने वाले गृहकार्य और शोध पत्र आदि तैयार करने में एआइ टूल ने इतनी महारत दिखाई कि वहां मौलिकता का अभाव होने लगा और नकल का बर्जस्व बढ़ गया। इस कारण दुनिया के कई विश्वविद्यालयों ने कैंपस में एआइ टूल्स के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया। सिनेमा व मीडिया में भी मौलिकता के महत्व को प्राथमिकता मिलने लगी है। इनसे इतर क्षेत्रों में एआइ सहयोगी टूल के रूप में ही सामने है। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में रोग के निदान संबंधी सटीकता, मरीज के इलाज की व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था व इलाज के प्रबंधों को एआइ से बेहतर किया जा रहा है।

इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव : इसमें संदेह नहीं कि भारत में सरकारी प्रयासों और निजी क्षेत्र की उत्सुकता की वजह से एआइ को लेकर माहौल तेजी से बदल रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो इसके रास्ते में अड़चनें पैदा करती है। जैसे, एक तथ्य यह है कि समूचे विश्व का 20 प्रतिशत डाटा पैदा करने वाले हमारे देश में केवल दो प्रतिशत डाटा सेंटर हैं। साथ ही, कंप्यूटिंग से जुड़ा भारत का बुनियादी ढांचा वैश्विक क्षमता की तुलना में दो प्रतिशत से कम है। इन कठिनाइयों का तात्पर्य यह निकलता है कि हमारे देश को एआइ का पूरा लाभ उठाने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने में निवेश करना होगा। देश की कंप्यूटिंग शक्ति में इजाफा करना होगा और डाटा की गुणवत्ता में सुधार करते हुए इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना होगा। एआइ से संबंधित चुनौतियों को समझने के लिए यह भी जरूरी है कि इंडस्ट्री से अकादमिक सहयोग में भी बढ़ोतरी हो। एआइ क्षमताओं में तेज विकास तभी संभव है, जब उद्योग जगत और शिक्षाविदों के बीच व्यापक सहयोग हो और विचारों का आदान-प्रदान हो। ऐसा होने पर ही शैक्षिक पाठ्यक्रमों को इंडस्ट्री की जरूरतों से जोड़कर और अनुसंधान व विकास को बढ़ावा देकर एआइ के माहौल में तेजी से परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसे बदलाव लाकर भारत एआइ से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक कुशल कार्यबल बना सकता है। कह सकते हैं कि अगर सफ नीयत और ठोस इरादे के साथ इस दिशा में पहल की गई, तो एआइ में भारत दबदबे की ऐसी स्थिति में आ सकता है, जहां वह विश्वगुरु भले न कहलाए, लेकिन चीन, अमेरिका आदि देशों में इस तकनीक के संदर्भ में होने वाली प्रगति से मुकाबला जरूर कर सकता है।

एआइ का उन्नत एवं रणनीतिक उपयोग

वैसे पढ़ने-लिखने से वास्ता रखने वाले लोगों को काफी अरसे से हमारे देश में बुद्धिजीवी कहने का चलन रहा है, लेकिन एआइ की ठीकठाक जानकारी रखने वालों के लिए इससे मिलते-जुलते शब्द- नालेज वर्कर के रूप में जाना जाता है। कह सकते हैं कि उन्हें यह नाम दिया गया है। ऐसे नालेज वर्करों का हिसाब-किताब रखने वाले एक ग्लोबल लीडर एटलसियन की हालिया रिपोर्ट का दावा है कि एडवांस एआइ के मामले में भारत की हैसियत अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और आस्ट्रेलिया से भी बेहतर है। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत में जो नालेज वर्कर एआइ का उपयोग करते हैं, उनमें से लगभग आधे यानी 46 प्रतिशत ऐसे हैं जो एआइ के एडवांस यूजर हैं। यानी इन्हें एआइ की काफी उन्नत जानकारी है। जबकि भारत के बाद आने वाले अमेरिका में ऐसे लोगों की संख्या 34 प्रतिशत और जर्मनी में 32 प्रतिशत है। आस्ट्रेलिया में तो केवल 23 प्रतिशत नालेज वर्कर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांस यूजर हैं।

इस रिपोर्ट में एआइ उपयोग के चार चरणों का उल्लेख किया गया है। पहले चरण में लोग एआइ का बुनियादी उपयोग करते हैं यानी उसके सिंपल टूल आजमाते हैं, जबकि बढ़ते हुए क्रम में चौथे चरण के नालेज वर्कर एआइ का उन्नत व रणनीतिक उपयोग करते हैं और फैसले लेने की भूमिका में होते हैं। इन चरणों का विभाजक आधार बताता है कि भारत में पहले चरण (स्टेज-1) वाले नालेज वर्कर एआइ की अपनी जानकारियों के उपयोग से औसतन प्रतिदिन 104 मिनट के कार्य समय की बचत करते हैं, जोकि वैश्विक औसत लगभग 45 मिनट से बेहतर है। जबकि चौथे चरण (स्टेज-4) वाले भारतीय नालेज वर्कर अपनी ज्ञान व क्षमताओं के बल पर प्रतिदिन 127 मिनटों के श्रम-समय की बचत करते हैं। यह बचत सप्ताहिक औसत में एक अतिरिक्त कार्यदिवस के बराबर होती है। इस आधार पर दावा किया जा रहा है कि भारतीय नालेज वर्कस एआइ के उपयोग से देश को महत्वपूर्ण उत्पादकता लाभ दिला रहे हैं।

यहां सवाल है कि क्या एआइ का यह ज्ञान और इसके उपयोग से होने वाली समय की बचत की कोई उपयोगिता है भी या नहीं। रिपोर्ट के अनुसार, जैसे-जैसे एआइ का बेहतर उपयोग होता जाता है, कर्मचारियों के संदर्भ में होने वाले लाभ बढ़ने लगते हैं। जैसे एक आकलन से पता चला है कि तीसरे और चौथे चरण वाली भूमिका में काम करने वाले 92 नालेज वर्करों ने स्वीकार किया कि उन्होंने एआइ को सीखने के लिए जो समय लगाया, वह फायदेमंद रहा। इससे न केवल उन्होंने काम के समय की बचत की, बल्कि कार्य की गुणवत्ता और सहभागिता में भी बढ़ोतरी हुई। (डा. संजय वर्मा)

खरी-खरी

रचना चोरी न होने का दर्द

विनोद कुमार विक्की

निराला कुमार वर्षों से लिख रहे हैं। कमोबेश दैनिक रूप से फेसबुक सहित इंटरनेट मीडिया पर भी रचनात्मक उपस्थिति दर्ज करा ही रहे हैं। पैसा और प्रकाशक की अनुकंपा से दो-चार साहित्यिक पुस्तकें भी मार्केट में उपलब्ध करा चुके हैं। यद्यपि कुमार बाबू छपने के क्षणिक सुख तथा लेखन निर्वाण से होते हुए साहित्यिक महापरिनिर्वाण की अवस्था में पहुंच चुके हैं, तथापि उनका मन व्यग्र और बेचैन है।

दरअसल आज तक इनकी कोई भी रचना अथवा रचना का कोई अंश किसी ने भी कापी-पेस्ट अथवा चोरी नहीं की है। उनको इस बात का घोर मलाल है कि अपनी चुराई गई रचना का स्क्रीनशट इंटरनेट मीडिया पर शेयर करके संबंधित लेखक को ट्रोल करने तथा संपादक को कोसने का सौभाग्य और सुख दोनों से अब तक वंचित रहना पड़ा है। कापीराइट का हवाला देते हुए उक्त मुद्दे पर गदर मचाने का पराक्रम अब तक प्राप्त नहीं हो पाया है।

आजकल कम छपने वालों की रचनाओं को भी कापी-पेस्ट कर चोर महाराज स्वयं और मौलिक लेखक को चर्चित करने को आतुर रहते हैं, परंतु निराला कुमार के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। एक अयोग्य सास को भी कामकाजी बहू को जब तब ताना मारने या महिला मंडली में शिकायत करके स्वयं के सास होने के अस्तित्व को साबित करने का मौका मिल जाता है, किंतु एक प्रतिष्ठित साहित्यकार की रचना चोरी नहीं होना किसी त्रासदी से कम नहीं।

साहित्यिक जीवन में अस्तेय की परिपाटना से वंचित रहना आत्मसम्मान और साहित्यिक प्रतिष्ठा दोनों का हनन माना जा सकता है। उनके सामने अभी भी यह यक्ष प्रश्न है कि पराली के धुएं की तरह यत्र-तत्र-सर्वत्र फैली हुई उनकी रचनाओं की स्तरीयता चोरी करने के लायक है या नहीं।

बहरहाल कुमार की रचनाओं पर कभी न कभी किसी साहित्यिक गिरहकट की नजरें इनायत होंगी और उनकी मौलिक रचनाओं को वह अपने नाम से प्रकाशित कर उन्हें हो-हल्ला मचाने का सौभाग्य प्रदान कर दें, इसी साहित्यिक चक्र में उनका मोक्ष फंसा हुआ है।

पोस्ट

सुखबीर सिंह बादल पर गोली चली। पहले तनखैया बने और अब जानलेवा हमला। यह कैसा जुनून है? क्यों है?
मानक गुप्ता@manakgupta

महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाकर भाजपा ने यही दर्शाया है कि उसने राजस्थान में हुई गलती से सबक लिया है।
अभिषेक द्विवेदी@Rezang_La

अमेरिका से भारतीय लोकतंत्र लाख गुना बेहतर है। भारत के किसी राष्ट्रपति ने अपने देश या समाज के अपराध क्षमा करने के लिए कभी अपने विशेषाधिकार इस्तेमाल नहीं किए। अमेरिका में क्यों की हद हो गई।
पंकज शर्मा@Pankaj__Sharma

एक ऐसे देश में जहां कोई ईसाई मत प्रचारक मतांतरण के जरिये असाध्य बीमारियों को ठीक कर देता है, वहां नवजोत सिंह सिद्धू को अपना ऑक्सीय ब्योरा साझा करने पर नोटिस दिए जा रहे।
राहुल राज@x_rahulraj

एक समय विनोद कांबली को सचिन तेंदुलकर से भी अधिक प्रतिभाशाली माना गया था, मगर सचिन आत्म-अनुशासन और आत्मनियंत्रण अपना कर कांबली से कोसों आगे निकल गए।
एक्स क्रिकेटर@old_cricketer

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सीमा पर हालात सामान्य होने के बाद चीन पर भरोसा किया जा सकता है?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या भारत में भी 16 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल नेटवर्क प्लेटफार्म से दूर रखने की पहल होनी चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

आया नंगादीश केबटने का फिरदौर, उपदवी जाएउधर स्मातानी इसओर।
स्मातानी इसओर बनाए 'छोटा भारत', झेल रहे जो आज वेवारे वहां हिकारत।
'मुवितवाहिनी' भेजनहटाओ भय का साया, हिंदू हित में वक्त आज निर्णय का आया।
- ओमप्रकाश तिवारी

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश डायरी

रोजगार सृजन के अवसरों को प्रोत्साहन

गांवों में गौ पालन और उद्योगों में निवेश, रोजगार के दो नए सिरे तय कर मोहन सरकार आगे बढ़ रही है। कार्यकाल का पहला साल पूरा करने के निकट पहुंच चुके मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने शुरुआत से ही गौ पालन पर जोर दिया और अब इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा में उद्योग में निवेश के लिए इन्वेस्टर समिट करते हुए युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाओं का प्रयास मोहन सरकार तलाश रही है। दरअसल, अपने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा निवेश को लेकर खींची गई लकीर को आगे बढ़ते हुए मोहन यादव ने भी इन्वेस्टर समिट पर जोर दिया। फर्क केवल इतना है कि शिवराज सरकार प्रदेश स्तरीय इन्वेस्टर समिट आयोजित करती थी, जबकि मोहन सरकार ने इसे संभागों में बांट दिया है। विदेश जाकर वहां से भी निवेश लाने का दावा करते हैं। उन्हें पता है कि सरकारी नौकरियों के साथ उद्योगों से मिलने वाले रोजगार से ही प्रदेश की जरूरत को पूरा नहीं किया जा सकता है। साथ ही गांव से पलायन होकर महानगरों पर बढ़ते दबाव को भी नियंत्रित करना आवश्यक है। ऐसे में उन्होंने कृषि की आय बढ़ाने के मोदी सरकार के उपायों के साथ कदमताल करते हुए गौ पालन को भी बढ़ावा देने का निश्चय कर लिया है।

मोहन यादव यह बताना नहीं भूलते कि अभी दुग्ध उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी नौ प्रतिशत है, जिसे वह 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तय है कि जब दुग्ध उत्पादन दोगुना होगा, तो इसकी खपत और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा और निश्चित तौर पर ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। युवाओं को नौकरियों के पीछे भागने के बजाय अपने गांव में ही अच्छी आमदनी का जरिया प्राप्त हो सकेगा। हालांकि गौ पालन को मोहन यादव के हिंदुत्व एजेंडे से भी जोड़कर देखा जाता है। मोहन सरकार योजना बनाकर 10 गाय पालने पर अनुदान देने और दूध पर बोनस देकर किसानों की आमदनी बढ़ाने की योजना लाने की तैयारी की जा रही है।

बीते दिनों जर्मनी में वहां के एक प्रमुख उद्योगपति एवं निवेशक से मिलते डा. मोहन यादव। (फाइल)

हाल ही में मुख्यमंत्री इंग्लैंड और जर्मनी की छह दिवसीय यात्रा पर गए थे, जो प्रदेश की आर्थिक प्रगति में सहायक सिद्ध होगी। दोनों देशों की यात्रा में अलग-अलग क्षेत्रों से 78 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। वैश्विक स्तर पर मध्य प्रदेश को भी एक नई पहचान मिली है। विदेश यात्रा से लौटने के बाद डा. यादव ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य न केवल निवेश आकर्षित करना था, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगों, शोध केंद्रों, शिक्षा केंद्रों, संस्कृतिक केंद्रों का दौरा कर प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसरों का सृजन करना था। मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश, तकनीकी साझेदारी और सांस्कृतिक संबंधों के केंद्र के रूप में स्थापित करना था।

मुख्यमंत्री की इस विदेश यात्रा में निवेश आकर्षित करने और साझेदारी बढ़ाने के तीन तरह से प्रयास किए गए। पहला, निवेशकों को भरोसा दिलाया गया कि वे प्रदेश में उद्योग लगाकर अपना व्यवसाय बढ़ाएं और प्रदेश के लिए रोजगार के अवसर सृजित करें। दूसरा, जो लोग सीधे निवेश नहीं करना चाहते हैं, उनसे आग्रह किया कि वे ज्वाइंट वेंचर की कंपनी बनाकर प्रदेश में निवेश कर सकते हैं। तीसरा प्रयास, उद्योगपतियों से आग्रह किया कि हमारे प्रदेश उद्योगों के साथ अपनी तकनीक शेयर करें, ताकि हमारे यहां रोजगार के अवसर बढ़ें और कारोबरियों को भी लाभ हो।

मध्य प्रदेश के प्रयासों को काफी हद तक सकारात्मक परिणाम मिलना आरंभ हो गया है। हेल्थकेयर और फार्मास्युटिकल उद्योगों के विस्तार के लिए हेलीयन फ्रामों ने तीन हजार करोड़ रुपये निवेश का प्रस्ताव रखा तो सरकार ने तत्काल कंपनी को भूमि आवंटित भी कर दिया। यह कंपनी अपना प्लांट इंदौर के स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में लगाएगी। डा. यादव ने बताया कि जर्मनी ने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार के द्वार भी खोले हैं। वहां की सरकार ने कहा कि इंजीनियर, डाक्टर, वकील, पैरामेडिकल से लेकर जितने तकनीकी युवा हैं, उन्हें जर्मन भाषा सिखाकर हमारे देश भेज दें, हम उन्हें रोजगार देंगे। इसके लिए जर्मनी में फ्रेंड्स आफ एमपी ग्रुप बनाया गया है। यह भी अच्छी खबर है।

कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में गांव से लेकर शहर तक में रोजगार की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, यदि ये प्रयास सफल रहते हैं तो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बड़ी संख्या में बढ़ सकते हैं। निवेश बढ़ाने के प्रयास तो पहले भी हुए हैं, लेकिन पहला अवसर है, जब सरकार ने बेहद गंभीरता दिखाई है, इसलिए माना जा सकता है कि प्राकृतिक और खनिज संसाधनों से भरपूर मध्य प्रदेश भी निवेशकों की पहली पसंद बन सकता है।

काप-29

जवाबदेही से बचते विकसित देश

जलवायु वित्त, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहयोग को लेकर विकसित देश अपने अड़ियल रवैये पर कायम हैं। हानि एवं क्षतिपूर्ति कोष की रूपरेखा भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाई है

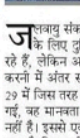

अरविंद कुमार मिश्रा
लोक नीति विश्लेषक

जलवायु संकट का समाधान खोजने के लिए दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अमीर देशों की कथनी-करनी में अंतर सबके सामने है। काप-29 में जिस तरह दुनिया दो खेमों में बंट गई, वह मानवता के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इससे एक बार फिर साबित हो गया है कि धरती की सेहत को लेकर विकसित देश गंभीर हैं।

जलवायु न्याय के लिए उठाए जाने वाले किसी भी कदम के लिए तकनीक और वित्त की आवश्यकता होती है। इस व्यावहारिक बात को नजरअंदाज कर धरती को हराभरा बनाने का कोई भी प्रयास सिर्फ लच्छेदार भाषण तक सीमित रह जाएगा। आज जो विकसित देश अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं जलवायु संकट के सबसे बड़े हिस्सेदार वही हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की एक रिपोर्ट के अनुसार जीवाश्म ईंधन तथा भूमि के उपयोग में बदलाव से पैदा होने वाले कार्बन उत्सर्जन में लगभग 80 प्रतिशत हिस्सेदारी जी-20 अर्थव्यवस्थाओं की है। इसमें अमेरिका, चीन और यूरोपीय यूनियन अग्रणी हैं। अमेरिका में दुनिया की चार प्रतिशत आबादी रहती है, जबकि 1850 से 2021 तक वैश्विक कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन में उसकी हिस्सेदारी 17 प्रतिशत रही है। औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित देशों का जहां संसाधनों पर नियंत्रण बढ़ा, वहीं उपभोग की प्रवृत्ति से उन्होंने पर्यावरण को जिस कदर नुकसान पहुंचाया है, इसका खामियाजा छोटे और द्वीपीय देशों से लेकर विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। विकसित देश चाहते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु अनुकूलन को लेकर छोटे देशों पर भी वही शर्तें लागू हों, जो विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए तय हों। यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा असर विकासशील देशों की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा आर्थिक विकास दर पर पड़ना तय है। ऐसे में इसके समाधान के लिए तकनीक और वित्त का सहयोग तंत्र विकसित करना होगा। पिछले कई जलवायु सम्मेलनों से अर्जित परिणाम को यदि देखें तो हर बार एक समझौते को अंतिम रूप दिया जाता है, लेकिन पिछली सहमतियों के क्रियान्वयन में सबसे बड़े उत्सर्जक देश ही उदासीन नजर आते हैं। गत वर्ष दुबई में आयोजित काप-28 में हानि एवं क्षतिपूर्ति कोष का शुभारंभ किया गया था। यह जलवायु वित्त से अलग व्यवस्था करार दी गई थी, लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, यह स्पष्ट नहीं है।

वैसे पर्यावरणीय संकट के समाधान की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ही पेरिस समझौते (2015) से जुड़ी कई नीतिगत पहल जैसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान कार्यक्रम, कार्बन क्रेडिट, जलवायु वित्त, हानि एवं क्षतिपूर्ति कोष आदि अस्तित्व में आए हैं। धरती को जहरीले प्रदूषण से मुक्त करने वाली हर पहल अच्छे परिणाम लेकर आएगी, यदि उन्हें लागू करने में प्रत्येक देश के हितों का ध्यान रखा जाए। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में जलवायु सम्मेलनों में तय हुए समझौते एवं संधियों के क्रियान्वयन की गति काफी धीमी है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र को भयावह होते जलवायु संकट के इस दौर में अपनी भूमिका पुनः परिभाषित करनी होगी। काप-29 में संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक कार्बन बाजार के लिए नियमों पर सहमति बनी है। इससे कार्बन क्रेडिट खरीदने और बेचने के नियम आसान बनेंगे। इसका सीधा असर जलवायु अनुकूल परियोजनाओं के लिए धन जुटाने में होगा। भारत समेत विश्व भर में कार्बन बाजार की व्यवस्था विकसित होने से पर्यावरण अनुकूल उत्पादों, सेवाओं, ईंधन, नवाचार में निवेश बढ़ेगा। इससे एक देश दूसरे देश को कार्बन क्रेडिट बेच सकेगा।

वैश्विक तापमान वृद्धि को दो डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखने तथा पेरिस समझौते में किए गए वादे के अनुसार इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए देशों को 2030 तक प्रतिवर्ष 30 गीगाटन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। एक अध्ययन के अनुसार, 2023 में विश्व में जीवाश्म ईंधन की खपत और उत्सर्जन अपने चरम पर पहुंच चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 2030 से 2050 तक जलवायु संकट की वजह से ढाई लाख अतिरिक्त मौतें होंगी।

आज विश्व में साढ़े तीन अरब लोग ऐसे स्थानों पर रह रहे हैं, जो पर्यावरणीय दृष्टि से अतिसंवेदनशील हैं। ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लिए विश्व के हर देश को एकजुट और गंभीर प्रयास करने होंगे। वर्ष 2025 का काप-30 सम्मेलन, ब्राजील के पूर्वी अमेजन इलाके बेलेन में होगा। उम्मीद है कि अगले जलवायु सम्मेलन से पहले जी-7, जी-20 से लेकर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंच जलवायु प्रतिबद्धताओं को लेकर अपनी भूमिका पर विलंब करने के बजाय उस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे।

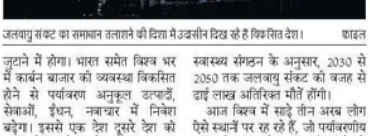
जलवायु संकट का समाधान तलाशने की दिशा में उदासीन दिख रहे हैं विकसित देश। फाइल